राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 5 अंक 21

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 1 जुलाई, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14



खेल रत्न पुरस्कार के लिए मिताली राज नामित >>12

जागरण विशेष

विदेश में नौकरी छोड़ गांव में सिखा रहे मछली पालन



गाजियाबाद : उत्तर प्रदेश के मोदीनगर के पतला गांव निवासी रजनीश कुमार इंजीनियर बन चुके थे। इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे देशों में नौकरी की। विदेश में 30 लाख के पैकेज पर अच्छी नौकरी थी, लेकिन वह अपने गांव लौट आए। मछली पालन करते हैं और दूसरों को सिखा भी रहे हैं। (पेज-10)

कोविशील्ड व कोवैक्सीन को मंजूरी दो, नहीं तो भारत आने पर क्वारंटाइन हो

बराबरी का प्रस्ताव ▶ वैक्सीन पर भारत ने यूरोपियन यूनियन को 'गिव एंड टेक' का फार्मूला सुझाया

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

यूरोपियन यूनियन (ईयू) की तरफ से भारत निर्मित वैक्सीन कोविशील्ड व कोवैक्सीन को डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट में शामिल नहीं किए जाने से उपजी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने 'गिव एंड टेक' फार्मूले का प्रस्ताव किया है। यानी ईयू भारत की वैक्सीन को वहां आने-जाने के लिए प्रमाणित करता है तो भारत भी डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट को वीजा देने में प्राथमिकता देगा। इस सर्टिफिकेट को हासिल करने वाले यूरोपीय नागरिकों को भारत में क्वारंटाइन भी नहीं होना पड़ेगा। भारत ने यह प्रस्ताव ईयू में शामिल सभी देशों को अलग-अलग भी भेजा है।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच इस बारे में बातचीत जारी है। जल्द सकारात्मक समाधान की संभावना है। यह समस्या तीन दिन पहले ईयू की तरफ से डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट (ग्रीन पास) जारी करने से संबंधित नियम से पैदा हुई है। इस व्यवस्था में भारत निर्मित वैक्सीन को शामिल नहीं किया गया है। वैसे ईयू ने चीन की वैक्सीन को भी शामिल नहीं किया है, लेकिन भारतीय वैक्सीन शामिल न किए जाने से यूरोप के किसी देश में जाने वाले भारतीयों को परेशानी हो सकती है। हालांकि, ईयू ने कल यह सफाई दी थी कि उसके ग्रीन पास संबंधी नियम में किसी वैक्सीन का नाम शामिल नहीं होने का मतलब यह नहीं कि कोई दूसरी वैक्सीन लेने वालों को वहां एंट्री की इजाजत नहीं होगी। ग्रीन पास ईयू के सदस्य देशों के बीच आवागमन में सहूलियत के लिए है। हर देश अपने यहां एंट्री के नियम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत निर्मित वैक्सीन लेने वालों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट फ्रेमवर्क पहली जुलाई से लागू होने वाला है।

▶ भारतीयों को ग्रीन पास मिला तो यूरोपीय भी भारत में क्वारंटाइन से राहत पाएंगे



कोरोना से जंग में वैक्सीन अहम हथियार है। फाइल

इस फ्रेमवर्क में फाइजर, माडर्ना, एस्ट्राजेनेका जैसी वैक्सीन को शामिल किया गया है। इन सभी वैक्सीन को यूरोपियन मेडिसिंस एजेंसी (ईएमए) से मंजूरी दी गई है। ये वैक्सीन लेने वालों को ईयू के भीतर आने-जाने की छूट होगी। भारत निर्मित वैक्सीन को ईएमए से मंजूरी नहीं मिली है। ईयू ने कहा था कि 28 जून, 2021 तक कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने उसके पास आवेदन ही नहीं किया।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारत सरकार ने ईयू से आग्रह किया है कि कोविशील्ड व कोवैक्सीन को भी सर्टिफिकेट फ्रेमवर्क में शामिल किया जाए। भारत के कोविन पोर्टल की तरफ से दिए जाने वाले सर्टिफिकेट को अनुमित दी जाए। इसके बदले भारत भी ईयू के सर्टिफिकेट को मान्यता देगा और कोविन पोर्टल उसे स्वीकार करेगा।

खतरनाक डेल्टा वैरिएंट को प्रभावी ढंग से असरहीन करती है कोवैक्सीन

वाशिंगटन : भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर अमेरिका से बहुत अच्छी खबर आई है। अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान यानी एनआइएच ने कोवैक्सीन को कोरोना वायरस के सबसे खतरनाक वैरिएंट डेल्टा के खिलाफ बहुत अधिक प्रभावी बताया है। अमेरिकी संस्था के मुताबिक कोवैक्सीन अल्फा वैरिएंट के खिलाफ भी कारगर है। एनआइएच ने कहा है कि कोवैक्सीन लेने वाले लोगों के ब्लड सीरम को लेकर दो अध्ययन किए गए। (विस्तृत खबर पेज-6 पर)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

न्यायपालिका को नियंत्रित नहीं किया जा सकता : सीजेआइ

नई दिल्ली : चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि न्यायपालिका को 'पूर्ण स्वतंत्रता' होनी चाहिए। इसे विधायिका या कार्यपालिका के जरिये नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा किया गया तो 'कानून का शासन' छलावा बनकर रह जाएगा। उन्होंने जजों को इंटरनेट मीडिया के प्रभाव से भी आगाह किया। कहा कि नए मीडिया उपकरण, जिनमें किसी चीजों को बढ़ा-चढ़ा कर बताए जाने की क्षमता है वे सही और गलत, अच्छे और बुरे और असली तथा नकली के बीच अंतर करने में असमर्थ हैं।

राजनीति ▶ पृष्ठ 4

सिद्धू सुलह फार्मूले पर राजी, नई भूमिका का एलान जल्द

नई दिल्ली : कांग्रेस हाईकमान के सुलह-समझौते के भारी प्रयासों के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ अपनी खुली जंग खत्म करने पर सहमत हो गए हैं। साथ ही पार्टी नेतृत्व ने सिद्धू को पंजाब की सत्ता सियासत में सम्मानजनक नई भूमिका का जो फार्मूला दिया है उस पर वे राजी हो गए हैं। हाईकमान ने यह भी संकेत दिया कि सिद्धू के नए सियासी रोल के प्रस्ताव पर अमरिंदर सिंह की सहमति भी मिल गई है।

कोरोना से मौत पर मुआवजे का हक

सुप्रीम कोर्ट का आदेश ▶ एनडीएमए छह सप्ताह में जारी करे मुआवजे की गाइडलाइन

न्यूनतम राहत तय करना एनडीएमए का वैधानिक दायित्व, इसमें मरने पर अनुग्रह राशि देना शामिल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा या अनुग्रह राशि दिए जाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम राहत की गाइडलाइन तय करना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) का विधायी कर्तव्य है। इसमें कोरोना से मौत पर अनुग्रह राशि देना शामिल है। इस बारे में गाइडलाइन नहीं जारी करना एनडीएमए की अपने विधायी कर्तव्य निर्वहन में नाकामी है। कोर्ट ने एनडीएमए को आदेश दिया कि वह छह सप्ताह के भीतर अनुग्रह राशि देने के बारे में न्यूनतम राहत की गाइडलाइन जारी करे। यह राशि कितनी होगी, यह फैसला कोर्ट ने एनडीएमए के विवेक पर छोड़ दिया जो उपलब्ध कोष, महामारी के दौरान इंतजाम और राहत की प्राथमिकताओं को देखते हुए तय होगी। साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया सरल की जाए और उसमें स्पष्ट तौर पर कारण कोरोना से मौत दर्ज किया जाए। इतना ही नहीं, जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार की व्यवस्था के भी निर्देश दिए।

ये निर्देश जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कोरोना से मौत पर परिजनों को मुआवजा देने की मांग वाली याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिए। वकील रीपक कंसल और गौरव कुमार बंसल ने याचिका दाखिल कर आपदा प्रबंधन कानून (डीएमए), 2005 की धारा-12 का हवाला देकर कहा था कि कोरोना को महामारी घोषित किया गया है इसलिए कोरोना से मौत पर चार-चार लाख रुपये मुआवजा देना सरकार की विधायी जिम्मदारी है।

केंद्र की दलील ठुकराई पेज>>6



- ऐसा न करके एनडीएमए अपने विधायी कर्तव्य के निर्वहन में नाकाम रहा
- मुआवजा राशि तय करने का फैसला एनडीएमए के विवेक पर छोड़ा
- मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया भी सरल बनाने का दिया आदेश
- मृत्यु प्रमाणपत्र में स्पष्ट दर्ज किया जाएगा कि मौत कोरोना से हुई
- जारी मृत्यु प्रमाणपत्र में सुधार की भी व्यवस्था करने का दिया आदेश

राज्यों का दिया उदाहरण

शीर्ष कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कुछ राज्य कोरोना संक्रमण से मरने वाले परिवारों को अनुग्रह राशि दे रहे हैं, जैसे बिहार में चार लाख रुपये, कर्नाटक में एक लाख रुपये और दिल्ली में 50 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। हालांकि, प्रदेश सरकारें ये पैसा राज्य आपदा प्रबंधन कोष (एसडीआरएफ) से नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री राहत कोष या अन्य राहत कोषों से दे रही हैं। कोर्ट ने कहा, किसी भी तरीके के पक्षपात और असंतोष से बचने के लिए उचित होगा कि एनडीएमए अनुग्रह राशि की न्यूनतम राहत के बारे में समान दिशानिर्देशों की संस्तुति करे, जैसा डीएमए एक्ट की धारा-12 में कहा गया है। इस धारा में मौत पर अनुग्रह राशि देने की बात शामिल है। कोर्ट ने साफ किया कि राज्यों को अपने राहत कोषों से कोरोना से मौत पर अनुग्रह राशि या अन्य मदद देने की छूट होगी। अदालत ने कहा कि कुछ राज्य कोरोना से मौत पर अनुग्रह राशि दे रहे हैं, इस आधार पर केंद्र सरकार को एक निश्चित अनुग्रह राशि देने का आदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि कोष का खर्च केंद्र सरकार द्वारा तय प्राथमिकताओं पर आधारित होता है। इसलिए अनुग्रह राशि में कितना पैसा दिया जाएगा, यह एनडीएमए और केंद्र सरकार के विवेकाधिकार पर छोड़ा जाता है।

...ताकि पीड़ित परिवारों को मिल सके सरकारी योजनाओं का लाभ : कोर्ट ने कहा, हमने पाया है कि मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया काफी जटिल है, इसे सरल बनाया जाए। प्रमाणपत्र पर स्पष्ट तौर पर कारण कोरोना से मौत दर्ज किया जाए ताकि पीड़ित परिवार को सरकार की घोषित योजना का लाभ लेने में दिक्कत न हो। अगर किसी की कोरोना से मौत हुई है या कोरोना के चलते हुई किसी और दिक्कत से हुई है, तो यह भी मृत्यु प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए।

सही मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करना हर अथारिटी की जिम्मेदारी : शीर्ष कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक अथारिटी की यह जिम्मेदारी है कि वह सही मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करे। कोर्ट ने कहा, गाइडलाइन में कहा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पाजिटिव आती है और उसकी दो या तीन महीने में मौत हो जाती है, चाहे अस्पताल में हो या घर पर, अगर मरने वाले के परिजन को जारी मृत्यु प्रमाणपत्र को लेकर कोई शिकायत है तो उसे सुधारने का तंत्र और व्यवस्था बनाई जाए। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह वित्त आयोग की 15वीं रिपोर्ट के पैराग्राफ 8.131 के आधार पर अन्य पक्षकारों के साथ परामर्श कर उचित कदम उठाए।

कोरोना संक्रमित होने पर सीए की परीक्षा से हट सकते हैं

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि आइसीएआइ द्वारा मुहैया कराई गई योजना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सीए की पांच जुलाई से होने जा रही परीक्षा में शामिल होने से वे लोग हट सकते हैं जो खुद या जिनके परिवार का कोई सदस्य कोरोना से पीड़ित हुआ है। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की तीन सदस्यीय पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि परीक्षा से हटने के अनुरोध के साथ परिवार के सदस्यों के लिए किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उम्मीदवार को आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट पेश करने की भी जरूरत नहीं है। (पेज-3)

साढ़े तीन लाख से अधिक गांवों में पहुंचेगा ब्रॉडबैंड इंटरनेट

नई दिल्ली : जल्द ही उप्र, हरियाणा, पंजाब व हिमाचल समेत 16 राज्यों के 3.61 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का काम शुरू होने जा रहा है। इन राज्यों में केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल के अलावा पूर्वोत्तर भारत के सातों राज्य शामिल हैं। इस काम के लिए सरकार पीपीपी मॉडल अपनाएगी। इसके लिए 19,041 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस राशि का इस्तेमाल वाएबिलटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के रूप में होगा। निजी कंपनियां गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के साथ उनके रखरखाव एवं संबंधित कार्य करेंगी। (पेज-7)

महिला आयोग ने ट्विटर से हफ्तेभर में अश्लील सामग्री हटाने को कहा

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक को एक हफ्ते के अंदर अपने प्लेटफार्म से अश्लील सामग्री हटाने के निर्देश दिए हैं और इस संदर्भ में उठाए गए कदमों के बारे में 10 दिनों के भीतर जानकारी देने को कहा है। एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को भी पत्र लिखकर मामले की जांच करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है।

महिला आयोग की ओर से जारी बयान के मुताबिक, 'एनसीडब्ल्यू ने ट्विटर पर अश्लील सामग्री साझा कर रहे कई प्रोफाइल पर स्वतः संज्ञान लिया है। रेखा शर्मा ने ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर एक हफ्ते के भीतर प्लेटफार्म से सभी अश्लील सामग्री तत्काल हटाने के लिए कहा है।' आयोग ने कहा कि पूर्व में इसी तरह की शिकायत मिलने पर आयोग तत्काल कार्रवाई के लिए मामले को ट्विटर के संज्ञान में लाया था, लेकिन ट्विटर ने कथित तौर पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। आयोग इस बात से व्यथित है कि ऐसी प्रतिबंधित सामग्री की उपलब्धता के बारे में पता होने के बावजूद उसने उन्हें हटाने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जो न सिर्फ भारतीय कानूनों का, बल्कि ट्विटर की अपनी नीति का भी उल्लंघन है। महिला आयोग ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब नए आइटी नियमों समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच रस्साकशी चल रही है।



उचित कानूनी कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को भी लिखा पत्र

गूगल को अप्रैल में मिली 27 हजार शिकायतें, 59 हजार सामग्री हटाई गई पेज>>3

जम्मू में सैन्य छावनी क्षेत्र में फिर दिखा ड्रोन

जेएनएन, जम्मू

जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद सैन्य छावनी क्षेत्रों को निशाना बनाने की साजिश चल रही है। लगातार चौथे दिन बुधवार को भी कालूचक और कुंजवानी में ड्रोन मंडराते देखे गए। 600 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे ड्रोन पर सैन्य जवानों ने फायरिंग कर उसे खदेड़ दिया। सैन्य प्रतिष्ठानों में सुरक्षा बढ़ी हुई है। जम्मू-श्रीनगर हाईवे में सेना और अर्धसैनिक बल के जवानों की गश्त जारी है। फिर भी ड्रोन कहां से आ रहे हैं, इसका अभी तक पता नहीं चला है।

जानकारी के अनुसार, कालूचक और कुंजवानी में मिलिट्री स्टेशन और एयरफोर्स सिग्नल के ऊपर तड़के 4.40 और 4.52 बजे ड्रोन मंडराते देखे गए हैं। लगातार ड्रोन देखे जाने की घटना के उपरांत आसपास इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया। साथ ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मामले की सेना के आला अधिकारियों को जानकारी दी गई।

- ▶ कालूचक्क और कुंजवानी क्षेत्र में 600 मीटर की ऊंचाई पर मंडरा रहा था
- ▶ सेना के जवानों ने ड्रोन पर की फायरिंग, तलाशी अभियान चलाया गया



जम्मू में बुधवार को कालूचक और कुंजवानी में ड्रोन मंडराते देखे जाने के बाद जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलर्ट सुरक्षा बल। प्रेट्र

राजौरी में ड्रोन के इस्तेमाल व बिक्री पर लगा प्रतिबंध

राजौरी से जागरण संवाददाता के अनुसार जम्मू में ड्रोन की बढ़ती घटनाओं से स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला उपायुक्त (डीसी) राजेश कुमार शवन ने बुधवार को राजौरी में ड्रोन के भंडारण, बिक्री, उपयोग और एक से दूसरी जगह ले जाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया। आदेश में ड्रोन या इसी तरह की अन्य वस्तु रखने वालों को स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करने का निर्देश दिया है। हालांकि सर्वेक्षण और निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाली सरकारी एजेंसियां स्थानीय पुलिस थाना प्रभारी और कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सूचित करने के बाद उपयोग कर सकेंगी। आदेश के अनुसार जिला उपायुक्त राजेश कुमार शवन ने जिले में अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया है।

कृषि कानून विरोधियों का भाजपा के दलित पदाधिकारी के काफिले पर हमला

प्रदर्शनकारियों का उपद्रव

- गाड़ियों के शीशे तोड़े, तलवार, लोहे की राड और लाठी-डंडों से लैस थे हमलावर
- 25 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता घायल



गाजियाबाद के यूपी गेट पर भाजपा के प्रदेश मंत्री के काफिले पर प्रदर्शनकारियों के हमले के बाद क्षतिग्रस्त कार और प्रदर्शनकारियों की तलवार के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते पार्टी कार्यकर्ता। अनिल बराल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने बुधवार सुबह गाजियाबाद के यूपी गेट पर भाजपा के दलित पदाधिकारी (प्रदेश मंत्री) अमित वाल्मीकि के काफिले पर हमला कर दिया। उप्र भाजपा के प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि का स्वागत करने जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं को काले झंडे दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों ने तलवार, लोहे की राड और लाठी-डंडों से हमला किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने 40 से अधिक गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। इस दौरान 25 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता चोटिल हुए।

अमित वाल्मीकि बुधवार को दिल्ली से बुलंदशहर जा रहे थे। सुबह साढ़े नौ बजे से भाजपा कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए यूपी गेट से एलिवेटेड रोड कट के बीच जुटने शुरू हुए। करीब पौने 11 बजे जैसे ही उनका काफिला दिल्ली से यूपी गेट पहुंचा तो करीब 50-60 प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। प्रदर्शनकारी लाठी, डंडे, लोहे की राड और तलवार लिए थे। काले झंडे दिखाते हुए उन्होंने अमित वाल्मिकी की कार के शीशे तोड़ दिए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रदाधिकारी को बचाते हुए उनकी कार को बुलंदशहर रवाना कर दिया।

भाजपा प्रदेश मंत्री के आने की सूचना स्थानीय पुलिस को भी थी। इसके चलते 15-20 पुलिसकर्मी भी वहां तैनात थे। भाजपा कार्यकर्ताओं को जुटते देख प्रदर्शनकारियों ने हमले की योजना बनाई। पुलिस की मौजूदगी में ही भाजपाइयों पर हमला हुआ। भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना उन्होंने डीएम व एसएसपी को दी। दोनों पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि तब तक आरोपित फरार हो चुके थे।

एसएसपी कार्यालय पर हंगामा, दी तहरीर : कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के बाद भाजपाइयों ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के खिलाफ तहरीर दी है। आरोप है कि टिकैत ने अपने गुंडों के साथ मिलकर उन पर हमला किया और लूटपाट की। यशपाल पहलवान पर जान से मारने की नीयत से तलवार से हमला किया। उनके हाथ पर चोट लगी है, जिससे वह घायल हो गए। बिजेंद्र सिंह, सनी की सोने की चेन व राजा यादव का मोबाइल लूटा गया। आरोपितों ने उनकी कारों में जमकर तोड़फोड़ की और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया।

आंदोलन को बदनाम करने की साजिश : राकेश टिकैत पेज>>5

कोरोना वायरस पर शोध कर रही थी चीनी सेना

साजिश के तार

वायरस पर शोध करने वाली बैट वुमेन ने सैन्य विज्ञानियों के साथ किया था काम, डा. शी झेंगली ने सैन्य विज्ञानी टोन यिगांग के साथ 2018 में कोरोना पर शोध किया था, दूसरे सैन्य विज्ञानी झोउ युसेन के साथ 2019 में शोध में जुड़ी थीं

बीजिंग, एएनआइ : कोरोना वायरस के फैलने के पीछे चीनी साजिश की आशंका और पुख्ता हो रही है। अब तक शोध को लेकर सेना से संबंधों को नकारते रहे वुहान इंस्टीट्यूट आफ वायरोलॉजी का यह दावा झूठा साबित हुआ है। इंस्टीट्यूट में कोरोना वायरस पर शोध करने वाली और बैट वुमेन के नाम से प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट डा. शी झेंगली के संबंध चीनी सेना के विज्ञानियों से होने की बात सामने आई है। फॉक्स न्यूज ने अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों के हवाले बताया है कि ऐसे कई प्रमाण हैं, जिनसे डा. झेंगली और चीन के सैन्य विज्ञानियों के बीच संबंध की पुष्टि होती है।

एक बड़ा वर्ग है, जो मानता है कि मौजूदा महामारी का कारण बनने वाला सार्स-कोवी-2 वायरस वुहान के इंस्टीट्यूट से ही फैला है। चीनी सेना द्वारा वायरस को जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल की कोशिशों की भी बातें सामने आती रही हैं। हालांकि चीन लगातार इन दलीलों को खारिज करता रहा है। अब सामने आया है कि बैट वुमेन डॉ. झेंगली ने चीन के दो सैन्य विज्ञानियों के साथ काम किया था। इनमें से एक विज्ञानी की बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डा. झेंगली ने सैन्य विज्ञानी टोन यिगांग के साथ 2018 में कोरोना को लेकर काम किया था। इसके बाद 2019 में डा. झेंगली ने झोउ युसेन के साथ शोध किया था। 2020 में एक लेख में फुटनोट में जिक्र किया गया था कि झोउ की मौत हो गई है। हालांकि उनकी मौत के कारण के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। वायरस की लीक थ्योरी के बीच एक रिपोर्ट यह भी है कि चीन ने कोरोना वायरस के शोध से जुड़े पुराने डाटा मिटा दिए हैं, ताकि किसी भी तरह इसकी उत्पत्ति तक न पहुंचा जा सके। इससे वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की जांच भी प्रभावित हुई। 2021 की शुरुआत में चीन में जांच के लिए गई डब्ल्यूएचओ की टीम को इस बात के बहुत कम ही प्रमाण मिल पाए कि चीन किस तरह के शोध कर रहा था। जांच दल को वहां खोजबीन करने के लिए सीमित अधिकार ही चीन ने दिए थे। जांच दल ने शुरुआत में कह दिया था कि प्रयोगशाला से वायरस लीक होने की आशंका गलत है, लेकिन बाद में डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस एदनम ने कहा कि इस मामले में और जांच की जानी चाहिए। चीन ने तो जांचकर्ताओं को कोरोना संक्रमण के शुरुआती मामलों की विस्तृत जानकारी भी नहीं दी। अब तक की जांच में इस वायरस के प्राकृतिक होने और किसी अन्य जानवर से मनुष्य में पहुंचने जैसा कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है। जिस वुहान मार्केट से वायरस के फैलने की बात चीन करता है, वहां कोई ऐसा जानवर नहीं मिला है, जिससे इस दावे की पुष्टि हो सके।



बैट वुमेन के नाम से प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट डा. शी झेंगली। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

अगले हफ्ते जम्मू-कश्मीर जाएगा परिसीमन आयोग

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर के विस चुनावों से पहले प्रस्तावित परिसीमन का काम तेज हो गया है। परिसीमन आयोग ने बुधवार को दिल्ली में एक अहम बैठक की, जिसमें परिसीमन का काम समय पर पूरा करने के लिए सभी से सहयोग मांगा गया और छह से नौ जुलाई तक जम्मू-कश्मीर के दौरे पर रहने का एलान किया। इस दौरान वह सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ परिसीमन पर चर्चा करेंगे। (पेज-3)

हरियाणा में आंदोलनकारियों से क्षति की भरपाई का कानून लागू

चंडीगढ़ : हरियाणा ने आंदोलनकारियों से संपत्ति को पहुंचे नुकसान की भरपाई का कानून लागू कर दिया है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। सरकार ने गत 28 जून को इसकी अधिसूचना जारी की है, लेकिन इसे एक अप्रैल से लागू माना है। (पेज-5)

10 फीसद अधिक बारिश हुई देश में जून महीने में। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून के राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना सात जुलाई तक नहीं है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 1 जुलाई, 2021

सरकार ने लगाई यमुना में मछली पकड़ने पर रोक

पशुपालन विभाग ने जारी की अधिसूचना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

यमुना के जिस जल के आचमन और जिसमें स्नान करने का पौराणिक महत्व है, वह जल अब जलीय जीवों के लायक भी नहीं रह गया है। यमुना में प्रदूषण का स्तर इस हद तक बढ़ गया है कि दिल्ली सरकार को एहतियातन इसमें मछली पकड़ने पर रोक लगानी पड़ गई है। पशुपालन विभाग ने नदी में उच्च प्रदूषण स्तर का हवाला देते हुए इसके कुछ हिस्सों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

विभाग की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्रतिबंधित किए गए हिस्सों में मछली पकड़ना भारतीय मत्स्य पालन अधिनियम 1987 के तहत दंडनीय होगा। अगले आदेश तक मछली पकड़ने का लाइसेंस भी निलंबित रहेगा। जानकारों का कहना है कि प्रतिबंधित घाटों से पकड़ी गईं मछलियों को खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।

गौरतलब है कि यमुना में तेजी से बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है। दैनिक जागरण ने भी बुधवार के अंक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। कुछ दिनों से इंटरनेट मीडिया पर भी नदी की सतह पर तैरती झाग के दृश्य शेयर किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार साबुन और डिटर्जेंट यमुना में प्रदूषण बढ़ाने के प्रमुख कारकों में शामिल हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के एक अधिकारी के मुताबिक, यमुना में जहरीले झाग के बनने का प्राथमिक कारण अपशिष्ट जल में उच्च फास्फेट सामग्री है क्योंकि डिटर्जेंट का उपयोग रंगाई उद्योगों, घरों और धोबी घाटों में किया जाता है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में यमुना में प्रदूषण को रोकने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के नवीनतम मानकों के अनुरूप साबुन और डिटर्जेंट की बिक्री, भंडारण, परिवहन और विपणन पर प्रतिबंध भी लगा दिया है।

इन स्थानों पर मछली पकड़ना प्रतिबंधित : हिंडन नहर, गाजीपुर- शादीपुर नाले, यमुना के एक हिस्से में ग्रोयन नंबर 85 (डाउनस्ट्रीम), न्यू ओखला बैराज से दिल्ली सीमा तक।

क्या है बीओडी और डीओ

नदी के पानी की गुणवत्ता को बीओडी और डीओ के मानकों पर मापा जाता है। बीओडी यानी बायोलाजिकल आक्सीजन डिमांड का मतलब है कि उस पानी में किसी जैविक पदार्थ को डिकंपोज (सड़ाने) करने के लिए किसी बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव को कितनी आक्सीजन की जरूरत है। जबकि डीओ यानी डिजाल्व आक्सीजन उस पानी में घुली हुई आक्सीजन के बारे में जानकारी देती है। पानी में बीओडी की मात्रा तीन मिलीग्राम प्रति लीटर या उससे कम होनी चाहिए और डीओ की मात्रा पांच मिलीग्राम प्रति लीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए।

कारिडोर के लिए बदली जाएगी यमुना की धारा

वी.के. शुक्ला, नई दिल्ली



यमुना किनारे का वह भाग जिसके नीचे से यमुना की धारा को गुजारा जाएगा। जागरण

बारापुला फेज-तीन एलिवेटेड कारिडोर के लिए सराय काले खां के सामने यमुना की धारा बदली जाएगी। आने वाले समय में कारिडोर के बन चुके भाग के नीचे से यमुना को रास्ता दिया जाएगा। इसके बाद यमुना के वर्तमान बहाव वाले क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। हालांकि धारा में यह बदलाव उस समय तक ही रहेगा जब तक यमुना के बहाव क्षेत्र में परियोजना का काम पूरा नहीं हो जाता।

यमुना के बहाव क्षेत्र में जिस स्थान पर परियोजना का काम होना है, उस भाग में पानी की सतह से 50 मीटर गहराई में कारिडोर के एक पिलर की नीव का फाउंडेशन पिछले साल मानसून के दौरान टेढ़ा हो गया था। जानकारों का कहना है कि ऐसा पानी के तेज बहाव से हुआ है। बहरहाल विभाग के लिए काम कर रही संबंधित कंपनी ने इसे मशीनों के माध्यम से कटवाकर निकलवा दिया है। अब फिर से इसे बनाया जाना है और सराय काले खां की ओर से कारिडोर को बनाते हुए मयूर विहार की ओर ले जाया जाना है। फिर से फाउंडेशन के टेढ़े हो जाने जैसी कोई समस्या नहीं आए इसके लिए यमुना को वर्तमान बहाव से सराय काले खां की ओर करीब 100 मीटर आगे रास्ता दिया जाएगा। तकनीकी जानकारों की मानें तो इस नए रास्ते में यमुना के बहाव पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। जिस जगह में यमुना को रास्ता दिया जाना है उस क्षेत्र में कारिडोर का काम पूरा हो चुका है। इस भाग में जमीन पर कोई काम नहीं बचा है। बारापुला के तीसरे फेज में सराय काले खां से मयूर विहार तक एलिवेटेड कारिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसकी लंबाई साढ़े तीन किलोमीटर है। यह कारिडोर आठ लेन का है, जिसकी चौड़ाई 35 मीटर है। इसके तैयार होने पर मयूर विहार से एम्स तक साढ़े नौ किलोमीटर सड़क सिग्नल फ्री हो जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत आ रही जमीन को लेकर विवाद हो चुका है। करीब आठ एकड़ जमीन पर खेती कर रहे किसानों द्वारा दावा कर देने से मयूर विहार की तरफ कुछ भाग में अभी काम रुका हुआ है।

जांच बढ़ी पर नए मामले रहे कम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

कोरोना की संक्रमण दर अब तक निचले स्तर पर आ चुकी है। पिछले दो-तीन दिनों इसे इसमें मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि, दो दिन पहले के मुकाबले दर और नए मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 94 नए मामले सामने आए हैं। वहीं, 248 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान छह लोगों की मौत भी हुई है।

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 79,935 सैंपल की जांच हुई। इसमें 0.12 फीसद सैंपल पाजिटिव पाए गए हैं। इससे एक दिन पहले 66,397 में से 0.15 फीसद सैंपल पाजिटिव पाए गए थे। दिल्ली में अब सक्रिय मामले घटकर 1379 रह गए हैं। इनमें से 943 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। 329 घर में क्वारंटाइन हैं। अन्य मरीज कोविड केयर और हेल्थ सेंटर में भर्ती हैं।

कोरोना के मामले कम होने के साथ कंटेनमेंट जोन की संख्या भी कम की जा रही है। अब कुल 1599 कंटेनमेंट जोन रह गए हैं। अब तक राजधानी में 14,34,188 लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 14,07,832 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं, 24,977 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 2,14,83,104 सैंपल की जांच हो चुकी है। जो कि आबादी से ज्यादा है।

जल्द शुरू हो जाएंगी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब : जैन

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली: स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बनाई जा रही दो जीनोम सीक्वेंसिंग लैब जल्द शुरू हो जाएंगी। इनमें से एक लैब लोकनायक अस्पताल में और दूसरी आइएलबीएस अस्पताल में बनाई जा रही है। दोनों करीब एक हफ्ते में काम करना शुरू कर देंगी। जैन ने बताया कि इन लैब के शुरू होने के बाद डेल्टा पल्स वैरिएंट की जांच भी इन अस्पतालों में हो सकेगी। अभी तक केंद्र सरकार के पास जांच के लिए इसका सैंपल भेजना पड़ता था। जैन ने बताया कि दिल्ली में डेल्टा प्लस वैरिएंट का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। केंद्र की तरफ से डेल्टा प्लस वैरिएंट के लिए किसी खास तरह की तैयारी की जरूरत नहीं बताई गई है। बाजारों पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में जैन ने कहा कि कोविड के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने की जरूरत है। जैन ने कहा कि कोरोना की आने वाली लहर की आशंका के मद्देनजर पूरी तैयारी कर ली है। हमारे पास 28 हजार कोविड बेड की उपलब्धता थी, और इसे बढ़ाकर 37 हजार बेड करने की तैयारी की जा रही है।

न्यूज गैलरी

78 लोगों की गिरफ्तारी पर पुलिस आयुक्त से मांगा स्पष्टीकरण

नई दिल्ली: नामचीन आनलाइन शापिंग साइट के कर्मचारी बनकर काल सेंटर के जरिये अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने के आरोप में 78 लोगों की गिरफ्तारी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का स्पष्ट और घोर उल्लंघन बताते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र बेदी के कोर्ट ने कहा है कि आयुक्त उन परिस्थितियों की व्याख्या करें, जिसके लिए इतने लोगों की तत्काल गिरफ्तारी जरूरी थी। अब इस मामले में आठ जुलाई को सुनवाई होगी। 25 जून को पुलिस ने जगतपुरी में छापेमारी कर एक काल सेंटर से 78 लोगों को एक साथ गिरफ्तार किया था। इनमें से महिला आरोपित मुस्कान गंडोत्रा और लीजा सिंह को जमानत देते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। (जासं)

आज आइएमए के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम

नई दिल्ली : डाक्टर्स डे के अवसर पर गुरुवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) की तरफ से कोरोना काल में जान गंवाने वाले डाक्टरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा सराहनीय योगदान देने वाले डाक्टरों को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में आइटीओ स्थित आइएमए के मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। आइएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. जेए जयालाल ने बताया कि दोपहर तीन बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में दस मिनट के लिए आनलाइन जुड़ेंगे। इस दौरान वह चिकित्सक वर्ग को संबोधित भी करेंगे। यह हमारे लिए गौरव की बात है। (जासं)

ब्लू लाइन पर बाधित रही मेट्रो सेवा

नई दिल्ली : दिल्ली मेट्रो के ब्लू लाइन पर बुधवार सुबह सिग्नल की समस्या के कारण कुछ देर के लिए मेट्रो ट्रेन परिचालन बाधित रहा। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) के अधिकारियों का कहना है कि करीब 15 मिनट में समस्या दूर कर ली गई थी। उसके बाद ट्रेनों की आवाजाही सामान्य हो गई थी। डीएमआरसी के अनुसार, द्वारका और द्वारका सेक्टर-21 के बीच सिग्नलिंग केबल का करीब 150 मीटर का हिस्सा चोरी हो गया था जिसके कारण मेट्रो सेवा बाधित रही थी। ब्लू लाइन दिल्ली के द्वारका को नोएडा और गाजियाबाद के वैशाली को जोड़ती है। रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। (राब्यू)

निजी स्कूल जल्द पूरा करें ईडब्ल्यूएस में दाखिले : सिसोदिया

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली

- प्राइवेट स्कूलों में इस साल ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत लगभग 32,500 बच्चों को मिलेगा दाखिला

दिल्ली सरकार की तरफ निजी स्कूलों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत दाखिले जल्द पूरे करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा शिक्षा निदेशालय की तरफ से 19 जुलाई से 31 जुलाई के बीच स्पेशल पीटीएम का आयोजन किया जाएगा।

दाखिले की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि स्कूल पहले सामान्य श्रेणी के तीन बच्चों का दाखिला करते हैं उसके बाद ईडब्ल्यूएस श्रेणी के एक बच्चे का दाखिला होता है, लेकिन कोरोना की इस विषम परिस्थितियों में स्कूलों में सामान्य श्रेणी के दाखिले पूरे नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से स्कूल ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों को दाखिला देने से मना कर रहे है। उपमुख्यमंत्री ने निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द ईडब्ल्यूएस श्रेणी में चयनित बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया पूरी करें। दिल्ली सरकार इन स्कूलों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के दाखिले पर फीस व अन्य शुल्क के रूप में प्रति बच्चा प्रतिमाह 2,260 रुपये देती है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दाखिला प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्राइवेट स्कूलों को इस राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

स्कूलों में होगी स्पेशल पीटीएम (पैरेंट्स टीचर मीटिंग) इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने स्पेशल पीटीएम की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण स्कूलों का खुलना अभी तय नहीं है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि कोविड संबंधी सभी प्रोटोकाल का पालन करते हुए 19 जुलाई से 31 जुलाई के बीच दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में एक स्पेशल पीटीएम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अभिभावकों को बच्चों की आगे की पढ़ाई और कोरोना काल में बच्चों के प्रति उनकी भूमिका से संबंधित जानकारी दी जाएगी।

इसके अलावा कक्षा छह के लिए संयुक्त पीटीएम का आयोजन होगा। हर साल करीब 1.5 लाख बच्चे प्लान एडमिशन के तहत एमसीडी स्कूलों से दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा छह में दाखिला लेते हैं। ये पीटीएम इन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि कक्षा छह के लिए होने वाले पीटीएम में एमसीडी स्कूलों के कक्षा पांच में पढ़ाने वाले शिक्षक भी शामिल होंगे।

दिल्ली विवि ने जारी किया संशोधित अकादमिक कैलेंडर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से प्रभावित दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक व स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष का संशोधित अकादमिक कैलेंडर जारी किया है। डीयू प्रशासन ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते चार से 16 मई तक विश्वविद्यालय बंद किया गया था। अकादमिक कैलेंडर में फेरबदल का यह बड़ा कारण है। संशोधित कैलेंडर के अनुसार प्रायोगिक परीक्षा तीन अगस्त से शुरू होंगी, जबकि प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 12 से 28 अगस्त तक चलेंगी। सेमेस्टर ब्रेक 25 से 30 अगस्त तक होगा। 31 अगस्त से नया सेशन शुरू होगा।

डीयू ने पांचवें, छठे, सातवें और आठवें सेमेस्टर का अकादमिक कैलेंडर भी जारी कर दिया है। डीयू प्रशासन की मानें तो सेमेस्टर पांच व सात का अकादमिक कैलेंडर एक होगा। इसी तरह छह और आठवें सेमेस्टर का कैलेंडर भी एक समान होगा। पांचवें व सातवें सेमेस्टर की कक्षाएं 20 जुलाई से शुरू होंगी। 10 अक्टूबर से सेमेस्टर ब्रेक शुरू होगा। सेमेस्टर ब्रेक के बाद 18 अक्टूबर से कक्षाएं पुनः प्रारंभ होंगी। 16 नवंबर से प्रायोगिक परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। 17 दिसंबर से सर्दी की छुट्टियां होंगी।

बालाजी ने संभाला पुलिस आयुक्त का पदभार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली



पुलिस मुख्यालय में नवनियुक्त पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव बुधवार को पदभार संभालने के दौरान पूर्व पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव (बाएं) को सैल्यूट करते हुए। ध्रुव कुमार

1988 बैच के वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव ने बुधवार को दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त के तौर पर पदभार संभाल लिया। वह दिल्ली पुलिस के 23वें आयुक्त बने। मंगलवार शाम को गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के बाद उन्हें आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। बालाजी श्रीवास्तव मूल रूप से मलिहाबाद के निवासी हैं।

बुधवार सुबह पहले एसएन श्रीवास्तव के सम्मान में किंग्सवे कैंप स्थित पुलिस लाइन में विदाई परेड का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली पुलिस के समस्त अधिकारियों ने उन्हें सलामी दी। उसके बाद मुख्यालय आकर उन्होंने बालाजी श्रीवास्तव को आयुक्त का पदभार सौंपा। इसके बाद एसएन श्रीवास्तव की पारंपरिक तरीके से विदाई हुई। मुख्यालय से विदा होने के दौरान कार में बैठने पर अधिकारी उनकी कार को रस्सी से खींचते हुए गेट के बाहर तक गए।

पदभार ग्रहण करने के बाद बालाजी ने समस्त अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी को कड़ी मेहनत व ईमानदारी के साथ काम करने की नसीहत दी। बालाजी बेहद सख्त व ईमानदार छवि के अधिकारी माने जाते हैं। नए आयुक्त के लिए भी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे कृषि कानून विरोधी आंदोलनकारियों से दिल्ली वासियों को सुरक्षित रखने व दिल्ली में हो रहे अपराध पर अंकुश लगाने की बड़ी चुनौती रहेगी।

एसएन श्रीवास्तव को उनकी ओर से लिए गए कई बेहतर फैसले के लिए याद रखा जाएगा। बहुत कम समय में उन्होंने पुलिस हित व अपराध पर अंकुश लगाने के मामले को लेकर कई बेहतर काम किए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जनता की नजरों में दिल्ली पुलिस की बेहतर छवि बनाने की रही। कोरोना काल में पहली व दूसरी लहर में पुलिस ने अपने कार्यों के जरिये दिल्लीवासियों का दिल जीत लिया, जिससे दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कहलाने लगी। एसएन श्रीवास्तव के 16 महीने का कार्यकाल बहुत ही चुनौतियों से भरा रहा। हर चुनौती को वह बहुत ही सूझबूझ से निपटने में सफल रहे। सेवानिवृत्ति तक उन पर कोई आरोप नहीं लगा और उनका बेहतर कार्यकाल रहा।

बालाजी श्रीवास्तव भी राजधानी व दिल्ली पुलिस की हर चीज से वाकिफ हैं। बेहतर पुलिसिंग के लिए वह कई नए फैसले लेने की कोशिश करेंगे। पुलिस को और अत्यधिक पेशेवर बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे जनता की उम्मीदों पर वह खरा उतर सकें। अपराध व महिलाओं की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता होगी। बालाजी का कार्यकाल मार्च, 2024 तक है। इससे उन्हें बेहतर काम करने के लिए काफी समय मिलेगा।

सिर्फ भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र : बीएल संतोष

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- पुराने कार्यकर्ताओं के अनुभव का लाभ लेने की सलाह
- विपक्ष के दुष्प्रचार को देना होगा मुंहतोड़ जवाब : अनुराग ठाकुर



प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (बाएं से दूसरे) का स्वागत करते प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता (दाएं से दूसरे)। संजय

भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने कहा कि देश में इस समय सिर्फ भाजपा ही एकमात्र ऐसा दल है, जिसमें आंतरिक लोकतंत्र जीवित है। कम्युनिस्ट पार्टी में भी यह व्यवस्था है, लेकिन वह अब महत्वहीन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है। यहां पद पाने के लिए किसी की शिक्षा या पृष्ठभूमि नहीं बल्कि पार्टी की विचारधारा व संगठन के प्रति लगाव और जिम्मेदारी लेने का भाव काम करता है।

बीएल संतोष दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पदाधिकारियों को समर्पण भाव से संगठन विस्तार के लिए काम करने और पुराने कार्यकर्ताओं के अनुभव का लाभ लेने की सलाह दी। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार की उपलब्धियों और कोरोना काल में उठाए गए कदमों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के साथ ही विपक्ष के दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संकट में भी विपक्ष केवल भ्रम फैलाने और विरोध की राजनीति करता रहा है। अनुराग ने कहा कि मोदी सरकार ने दो दिन पूर्व ही एक बार फिर से छह लाख करोड़ से ज्यादा का राहत पैकेज जारी किया है, जिसके तहत 50 हजार करोड़ रुपया अस्पतालों के निर्माण के लिए और 30 हजार करोड़ रुपया स्वास्थ्य सेवाओं और बाल चिकित्सालयों के विस्तार एवं नवीनीकरण के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि दिल्लीवालों पर दोहरी मार पड़ी है, क्योंकि एक तरफ महामारी की मार थी तो दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल सरकार की लापरवाही। इस सरकार की ओछी राजनीति का कड़ा जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की पूरी राजनीति झूठ पर टिकी है। केजरीवाल सत्ता के मद में चूर हैं और जनता का दुख दर्द भूलकर भ्रष्टाचार में जुटे हैं। कोरोना संकट में केजरीवाल सरकार नदारद थी। दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ता जरूरतमंदों की सेवा में जुटे रहे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार हर काम राजनीतिक द्वेष से करती है। इस सरकार की अक्षमता और विफलता के कारण ही दिल्ली पर संकट आया।

अंतरराज्यीय गिरोह के तीन गुर्गे गिरफ्तार, 100 किलो गांजा बरामद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से लाई गई थी गांजे की खेप
- आरोपितों के पास से पुलिस ने 2.75 लाख रुपये भी किए बरामद

द्वारका जिला पुलिस के एंटी नारकोटिक्स दस्ते ने गांजे की बड़ी खेप बरामद करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल होने वाली दो कारों को भी जब्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों के नाम हंसराज, पामुलापति व आकाश है।

द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त संतोष कुमार मीणा ने बताया कि तस्करों के इस गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। गिरोह का सरगना पामुलापति आंध्र प्रदेश के गुंटूर का रहने वाला है। इसे आंध्र प्रदेश की पुलिस पूर्व में भी गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपितों के पास से पुलिस ने 2.75 लाख रुपये भी बरामद किए हैं।

इस मामले में पुलिस के नारकोटिक्स दस्ते के एएसआइ विनोद कुमार को जानकारी मिली थी कि गांजा आपूर्ति करने के लिए एक तस्कर बागडोला गांव आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने एसीपीजी परिसर के पास जाल बिछाया। टीम ने आरोपित हंसराज को दबोच लिया। उसकी कार से ही गांजे की खेप बरामद हुई। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि वह गांजे की यह खेप आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से लिया था। उसने कहा कि वह पामुलापति के कहने पर ऐसा कर रहा है। इसके बाद उसने आकाश का भी नाम लिया। पुलिस ने इन दोनों को भी गिरफ्तार किया है। पामुलापति वर्ष 2015 से इस धंधे में है। इन दिनों वह गुरुग्राम में रह रहा था।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार नशीले व मादक पदार्थ तस्करी के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए द्वारका जिला पुलिस के एंटी नारकोटिक्स दस्ते को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह तस्करों पर नकेल कसे। पिछले महीने मादक पदार्थ की तस्करी के पांच मामले सामने आए थे। जून में तीन मामले सामने आए हैं। इन मामलों में पुलिस ने 18 आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

सिलेंडर फटने से लगी आग में चार लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : फर्श बाजार इलाके में मंगलवार देर रात सिलेंडर फटने से एक मकान में आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। वहीं, एक युवक झुलस गया। दमकल की नौ गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मृतकों की पहचान मनु देवी, इनके दो बेटे नरेश व ओमप्रकाश व बेटी सुमन के रूप में हुई है। परिवार में मनु देवी के एक अन्य बेटे लालचंद ही जिंदा बचे हैं। डाक्टरों का कहना है दम घुटने से सभी की मौत हुई। दरअसल, मकान के भू-तल पर दुकान बनी हुई है। इसमें मकान मालिक का भांजा मनोज उर्फ मन्नू अवैध रूप से बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस रीफिलिंग का काम करता है। पुलिस केस दर्ज कर मनोज की तलाश कर रही है।

मनु देवी मूलरूप से बांदा, उत्तर प्रदेश की रहने वाली थीं। वह परिवार के साथ भीकम सिंह कालोनी की गली नंबर 16 में किराये के कमरे में रहती थीं। इस मकान के पीछे दुकान है, जिसमें गैस रीफिलिंग का काम होता है। कमरे का रास्ता भी दुकान से लगी गैलरी से होकर निकलता है। दस महीने पहले मनु देवी के पति की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मंगलवार रात को खाना खाने के बाद लालचंद को छोड़कर परिवार के बाकी सदस्य सो गए। लालचंद फोन में वीडियो देख रहे थे। रात 12:00 बजे मनोज की दुकान में जोरदार धमाका हुआ और दुकान की दीवार मनु देवी के कमरे में जा गिरी। इससे उनका दरवाजा बंद हो गया। पूरे घर में धुआं भर गया। कमरे में एक छोटी खिड़की है। लालचंद किसी तरह से उसके पास पहुंचे। उससे चेहरा सटाकर सांस लेने लगे। कमरे में इतना धुआं भर गया कि बाकी लोग अचेत हो गए। दमकल ने लोगों के साथ मिलकर खिड़की को तोड़ा और लालचंद को बाहर निकाला। आग बुझाने के साथ ही दमकल ने बाकी चार लोगों को कमरे में से निकाला। इन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां चारों को मृत घोषित कर दिया गया। प्राथमिक उपचार के बाद लालचंद को छुट्टी दे दी।

मौसम का हाल

43 डिग्री सेल्सियस को भी पार गया दिल्ली का अधिकतम तापमान, यलो अलर्ट, गुरुवार को भी राहत मिलने के आसार नहीं, शुक्रवार को हो सकती है हल्की बारिश, हालांकि मानसून का इंतजार बरकरार

लगातार दूसरे दिन चली लू, एक दशक में सबसे गर्म रहा 30 जून

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

आषाढ़ में भीषण गर्मी का सितम बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। दिन भर लू चलती रही तो अधिकतम तापमान ने भी एक दशक का रिकार्ड तोड़ दिया। यह सामान्य से सात डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अधिक तापमान की वजह से ही दिल्ली में यलो अलर्ट जारी है। गुरुवार को भी गर्मी और लू से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। शुक्रवार को हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन मानसून के लिए इंतजार अभी जारी रहेगा।

मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से सात डिग्री अधिक 43.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले 30 जून 2011 को अधिकतम तापमान 33 डिग्री था। न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 28 से 61 फीसद रहा। गुरुवार को भी गर्म हवा जारी रहने के कारण लू से राहत नहीं मिलेगी। अधिकतम तापमान 41 व न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।

प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक पश्चिमी दिशा से आने वाली शुष्क और गर्म हवा की वजह से दिल्ली में अधिक गर्मी बढ़ रही है। अगले 24 घंटे में भी लू चलेगी और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।

उन्होंने बताया कि शुक्रवार को दिल्ली का मौसम करवट ले सकता है। हल्की बारिश गर्मी से आंशिक राहत दिला सकती है। हालांकि इसे मानसून की बारिश नहीं कहा जाएगा। मानसून की पहली बारिश आने में अभी चार से पांच दिनों का समय और लगेगा।

दोपहर में बेवजह घरों से न निकलें

मौसम विभाग ने बढ़े हुए तापमान को लेकर लोगों से बेवजह घरों से न निकलने की सलाह दी है, खासकर दोपहर के समय। विभाग की सलाह है कि दोपहर एक बजे से लेकर शाम पांच बजे तक बिना वजह घरों से न निकलें।

आठ स्थानों पर 44 पार रहा पारा

दिल्ली में आठ स्थानों पर बुधवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री पार दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस नजफगढ़ इलाके में रहा। रिज इलाके में 44, आया नगर में 44.2, मुंगेशपुर में 44.3, नरेला में 44.3, पीतमपुरा में 44.3, पूसा में 44.3 और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में 44.1 डिग्री सेल्सियस पारा रहा। मंगलवार को पांच स्थानों पर तापमान 44 डिग्री पार रहा था।

बिजली की अधिकतम मांग 69 सौ मेगावाट के पार पहुंची

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

उमस भरी गर्मी के साथ ही पिछले कुछ दिनों से बिजली की खपत बढ़ रही है। बुधवार दिन में 3:10 बजे अधिकतम मांग 6,921 मेगावाट पहुंच गई। यदि मौसम का यही हाल रहा तो अगले कुछ दिनों में यह साढ़े सात हजार मेगावाट तक पहुंच सकती है। पिछले वर्ष कोरोना महामारी व लाकडाउन की वजह से बिजली की खपत कम रही थी। अधिकतम मांग 6,314 मेगावाट रही थी। इस वर्ष भी लाकडाउन की वजह से अप्रैल व मई में बिजली की खपत कम थी। अनलाक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बिजली की खपत बढ़ने लगी। मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम मांग 6,592 मेगावाट थी। पिछले 24 घंटे में तीन सौ मेगावाट से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अगले एक-दो दिनों में बिजली की अधिकतम मांग का रिकार्ड टूटने की संभावना जताई जा रही है। अबतक सबसे अधिक मांग 7,409 मेगावाट दो जुलाई, 2019 को रही थी। 2018 में भी मांग सात हजार मेगावाट से ऊपर रही थी।

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) का कहना है कि उसके बिजली वितरण क्षेत्र में इस वर्ष का अधिकतम मांग 1,974 मेगावाट रही। बिजली वितरण कंपनियों का कहना है कि संभावित खपत को ध्यान में रखकर बिजली की व्यवस्था की गई है, लिहाजा उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं होगी।

1988 बैच के आइआइएस अधिकारी एन. वेणुधर रेड्डी ने आकाशवाणी के महानिदेशक का प्रभार संभाल लिया। वर्तमान में आकाशवाणी समाचार के प्रिंसिपल डीजी के रूप में कार्य कर रहे रेड्डी को आकाशवाणी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

एक दिन में जयशंकर की 10 देशों के विदेश मंत्रियों से वार्ता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

इटली के माटेरा शहर में दुनिया के शीर्ष 20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए मंगलवार का दिन काफी गहमागहमी वाला रहा। दिन भर चले जी-20 देशों की बैठक में व्यस्त रहने के बावजूद उन्होंने वक्त निकाल कर एक दिन में दस देशों के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय बैठकें की।

▸ अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, स्पेन, इटली, कनाडा, सिंगापुर, सउदी अरब, फ्रांस व मेक्सिको के विदेश मंत्री के साथ चला द्विपक्षीय बैठकों का दौर

जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब, फ्रांस के विदेश मंत्री जे वाइ ले द्रां, जापान के विदेश मंत्री तोशीमित्सु मोटेगी, स्पेन की विदेश मंत्री अरंचा गोंजालेज के अलावा सिंगापुर, कनाडा, सउदी अरब, मेक्सिको, इटली और अल्जीरिया के विदेश मंत्रियों से अलग-अलग मुलाकात की व द्विपक्षीय संबंधों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़े तमाम मुद्दों पर बात की। बातचीत में कोरोना महामारी और इसे खत्म करने को लेकर होने वाले सहयोग के साथ ही कुछ देशों के साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर भी बात हुई।



विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इटली के माटेरा शहर में जी-20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर अमेरिकी समकक्ष एंटोनी ब्लिंकेन से मुलाकात कर आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। प्रेट्र

विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट पर जानकारी दी कि अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकेन के साथ बैठक में एशिया प्रशांत और अफगान के मुद्दे पर बात हुई है। वैसे दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों की तरफ से इस बारे में आधिकारिक तौर अलग से कोई जानकारी नहीं दी गई।

जयशंकर की कनाडा के विदेश मंत्री मार्क गारनेऊ से भी अलग से बातचीत हुई। इस बैठक की अहमियत इसलिए है कि कनाडा सरकार की तरफ से पिछले वर्ष भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर टिप्पणी के बाद दोनों देशों के बीच पहली बार कोई उच्चस्तरीय मुलाकात हुई है। जयशंकर के मुताबिक हिंद प्रशांत क्षेत्र, कारोबार और आर्थिक सहयोग पर खास तौर पर बात हुई है।

हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर जयशंकर की जापान के विदेश मंत्री मोटेगी से भी बात हुई। साथ ही जल्द ही दोनों देशों के बीच होने वाली टू प्लस टू वार्ता (विदेश व रक्षा मंत्रियों को मिला कर) को लेकर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री के मुताबिक क्वाड की प्रगति भी एक मुद्दा रहा है।

सउदी अरब के विदेश मंत्री के साथ हुई वार्ता में जल्द से जल्द दोनों देशों के बीच हवाई मार्ग खोलने की संभावना पर चर्चा हुई। भारत में कोरोना की स्थिति को देखते हुए सउदी अरब ने फिलहाल सीधी उड़ानें रोक रखी हैं। इसके चलते वहां काम करने वाले लाखों भारतीय फंसे हुए हैं। इसी तरह से मेक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो ईबार्ड के साथ बैठक में फार्मा सेक्टर में सहयोग व कोरोना को हराने के मुद्दा हावी रहा।

कोरोना संक्रमित होने पर सीए की परीक्षा से हट सकते हैं उम्मीदवार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया (आइसीएआइ) द्वारा मुहैया कराई गई योजना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सीए की पांच जुलाई से होने जा रही परीक्षा में शामिल होने से वे लोग हट सकते हैं जो खुद या जिनके परिवार का कोई सदस्य कोरोना से पीड़ित हुआ है।

जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की तीन सदस्यीय पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि परीक्षा से हटने के अनुरोध के साथ परिवार के सदस्यों के लिए किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उम्मीदवार को आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट पेश करने की भी जरूरत नहीं है।

पीठ ने कहा कि कोई उम्मीदवार जो खुद कोरोना से संक्रमित रहा है या उसके परिवार का कोई भी सदस्य इस बीमारी की चपेट में आया है और इस वजह से वह परीक्षा में शामिल होने या परीक्षा की तैयारी में असमर्थ है, तो वह परीक्षा से हटने का विकल्प चुन सकता है। पीठ ने कहा कि किसी उम्मीदवार के इस वजह से परीक्षा से हटने को उसके प्रयासों में नहीं गिना जाएगा। ऐसे उम्मीदवार पुराने और नए पाठ्यक्रम दोनों के लिए अगली परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

▸ स्वजन के संक्रमित होने पर भी मिल सकता है परीक्षा छोड़ने का मौका, इस तरह परीक्षा छोड़ने की नहीं होगी सीमित प्रयासों में गिनती



सुप्रीम कोर्ट ने किया स्पष्ट। फाइल

परीक्षा की अवधि के दौरान लाकडाउन से प्रभावित उम्मीदवारों के संबंध में पीठ ने कहा कि आइसीएआइ की योजना के अनुसार ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा से हटने (ऑप्ट-आउट) की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रयास के रूप में नहीं गिना जाएगा तथा ऐसे उम्मीदवार को अगली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के दौरान कोरोना से पीड़ित हो जाता है तो उसे परीक्षा से हटने की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रयास के रूप में नहीं गिना जाएगा। वे अगले साल परीक्षा दे सकते हैं। उम्मीदवारों को नियमानुसार बैकअप परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है।

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि आइसीएआइ द्वारा दायर नोट में कुछ गंभीर मुद्दों का जिक्र नहीं किया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के मुद्दे का जिक्र किया। पीठ उम्मीदवारों के लिए आप्ट-आउट विकल्प, परीक्षा स्थगित करने और इस साल केंद्रों की संख्या में वृद्धि सहित विभिन्न राहत के अनुरोध वाली कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही थी।

अगले हफ्ते जम्मू-कश्मीर जाएगा परिसीमन आयोग

कवायद ▸ बुधवार को अहम बैठक में फैसला, छह से नौ जुलाई तक होगा दौरा

सभी राजनीतिक दलों और स्थानीय प्रशासन के साथ होगी चर्चा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आयोग को मिला विस्तार, 2020 में हुआ था गठन

जम्मू-कश्मीर के विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन को लेकर केंद्र सरकार ने मार्च, 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया था। सालभर में आयोग को यह काम पूरा करना था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते वह इस काम को समय पर पूरा नहीं कर पाया। लिहाजा आयोग के कार्यकाल को मार्च, 2021 में एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। आयोग में अध्यक्ष सहित कुल तीन स्थायी सदस्य हैं। इसके साथ ही स्पीकर ने पांच सदस्यों को मनोनीत भी कर रखा है। पिछली बैठक में इनमें से बुलाने पर दो ही सदस्य आए थे।

जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनावों से पहले प्रस्तावित परिसीमन का काम तेज हो गया है। परिसीमन आयोग ने बुधवार को दिल्ली में इसे लेकर एक अहम बैठक की, जिसमें परिसीमन का काम समय पर पूरा करने के लिए सभी से सहयोग मांगा गया और छह से नौ जुलाई तक जम्मू-कश्मीर के दौरे पर रहने का एलान किया। इस दौरान वह सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं और जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परिसीमन पर चर्चा करेंगे और उनकी राय जानेंगे।

परिसीमन आयोग के इस तीन दिवसीय दौरे में आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी मौजूद रहेंगे। दौरे में चंद्रा के रहने से इस बात की संभावना बढ़ गई है कि वह चुनाव से जुड़ी तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। आयोग की इस पहल से साफ है कि जम्मू-कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। खास बात यह है कि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जम्मू-कश्मीर के नेताओं की बुलाई गई बैठक में विधानसभा चुनावों को कराने का मुद्दा उठा था। सभी नेताओं ने एक स्वर से विधानसभा चुनाव जल्द कराने की मांग की थी जिस पर सरकार ने अमल का भरोसा दिया था।

इस बीच, परिसीमन आयोग की बुधवार को हुई बैठक में इस काम को तेजी से पूरा करने पर चर्चा हुई। साथ ही दौरे से जुड़ी योजना को अंतिम रूप दिया गया। दौरे में राजनीतिक दलों और सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी। इनमें ब्लाक और पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इनसे परिसीमन प्रक्रिया से संबंधित विषय पर चर्चा की जाएगी। बैठक में आयोग के सदस्य के रूप में जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से शामिल थे। मालूम हो कि परिसीमन के बाद जम्मू-कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा की सीटें नए स्वरूप में सामने आएंगी जो पहले की तुलना में लोगों के लिए आवागमन और जुड़ाव रखने में ज्यादा मुफीद होंगी।

ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप 10 में पहुंचा भारत

नई दिल्ली, प्रेट्र : साइबर हमले के खतरों के बीच साइबर सुरक्षा के मोर्चे पर भारत ने लंबी छलांग लगाई है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (आइटीयू) की रिपोर्ट के मुताबिक, साइबर सुरक्षा के मामले में भारत टॉप 10 देशों में शामिल हो गया है। इस साल जारी हुए ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स (जीसीआइ) में भारत 10वें स्थान पर रहा है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है, जबकि डिजिटल इंडिया अभियान को पहली जुलाई को छह साल पूरा हो रहा है।

सालभर पहले के मुकाबले भारत ने 37 स्थानों की छलांग लगाई है। पिछले साल इस इंडेक्स में भारत 47वें स्थान पर था। इस साल कुल 194 देशों को इसमें शामिल किया गया था। इसमें अमेरिका पहले स्थान पर, ब्रिटेन व सऊदी अरब दूसरे और एस्टोनिया तीसरे स्थान पर रहा। चीन को 33वें और पाकिस्तान को 79वें स्थान पर रखा गया है। भारत ग्लोबल आइटी सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। ऐसे में यह रिपोर्ट लोगों की डिजिटल सुरक्षा की दिशा में सरकार के प्रयासों को प्रमाणित करती है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत चौथे स्थान पर है। इस इंडेक्स में जगह बनाने के लिए साइबर सिक्योरिटी के पांच मानकों पर प्रदर्शन को आंका जाता है। इनमें कानूनी कदम, तकनीक के स्तर पर कदम, संस्थागत कदम, क्षमता निर्माण और सहयोग के मानक शामिल हैं।

आधे-अधूरे काम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एनसीबी की खिंचाई की

▸ इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से किया इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की लापरवाही और आधे-अधूरे काम के लिए उसकी खिंचाई की और मादक पदार्थ के एक मामले में आरोपित को जमानत देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया।

चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि आप (अभियोजन) इतने लापरवाह और ढीले-ढाले हैं, तो हम इस मामले में टांग क्यों अड़ाएं। भाटी ने पीठ से कहा, यह अभियोजन पक्ष की गलती थी कि जमानत मिलने वाले आरोपित के आपराधिक इतिहास के बारे में हाई कोर्ट को सूचित नहीं किया। इसके चलते उसे जमानत मिल गई। हालांकि एक अन्य मामले में हिरासत में होने के कारण उसकी रिहाई नहीं हो पाई। इस पीठ में जस्टिस एएस बोपन्ना और हृषिकेश राय भी शामिल हैं।

इस पर पीठ ने सवाल किया कि आखिर यह आधा-अधूरा काम क्यों किया गया। क्या आपके लोग ईमानदार नहीं हैं। वे बस इतना चाहते हैं कि उसकी जमानत रद कर दी जाए। इस पर भाटी ने कहा कि वे सभी विवरण देते हुए अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करेंगी।

पीठ ने कहा कि आपकी सरकार मामलों का बचाव करने में पर्याप्त ईमानदार नहीं है तो हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। शुरुआत में भाटी ने पीठ को बताया कि आरोपित नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज एक अन्य मामले में हिरासत में है।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ने कहा कि प्रतिवादी को पहले ही 10 नवंबर, 2020 के आदेश के तहत हाई कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है, लेकिन उसे रिहा नहीं किया गया है क्योंकि वह किसी अन्य मामले में भी हिरासत में है। उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हम आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि हाई कोर्ट ने अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी को पहले ही जमानत दे दी है। पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यह किसी अन्य मामले में आरोपित को रिहा करने या किसी अन्य आरोपित को लाभ देने का आधार नहीं होना चाहिए। इस मामले की प्राथमिकी के अनुसार आरोपित की कार से 20 किलो चरस बरामद किया गया है।

ले. जनरल संजीव कुमार शर्मा होंगे सेना में रणनीति व योजना के नए उप प्रमुख

नई दिल्ली, प्रेट्र : लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा सेना के नए उप प्रमुख (रणनीति) होंगे। 13 लाख जवानों वाली मजबूत सेना के परिचालन और खुफिया निदेशालय की देखरेख के लिए पिछले साल ही इस पद का सृजन किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह का स्थान लेंगे जिन्हें इस साल पहला डीसीओएएस (रणनीति) बनाया गया है।



लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा। फाइल फोटो

अधिकारियों ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल को सेना में 39 साल की सेवा के बाद बुधवार को यह पदोन्नति दी गई। मौजूदा समय में सैन्य खुफिया के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा गुरुवार को नया कार्यभार संभालेंगे। डीसीओएएस (रणनीति) का गठन सेना मुख्यालय में बड़े सुधार के तहत किया गया है। तीन साल पहले सिक्किम सेक्टर के डोकलाम में चीनी सेना के साथ 73 दिनों तक चले गतिरोध के बाद इसकी जरूरत महसूस की गई थी। लेफ्टिनेंट शर्मा राष्ट्रीय सैन्य स्कूल बेंगलुरु के पूर्व छात्र रहे हैं और उन्हें दिसंबर 1983 में राजपूताना राइफल में कमीशन मिला।

न्यायपालिका को नियंत्रित नहीं किया जा सकता : सीजेआइ

▸ यदि ऐसा किया गया तो 'कानून का शासन' महज छलावा साबित होगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने बुधवार को कहा कि न्यायपालिका को 'पूर्ण स्वतंत्रता' होनी चाहिए। इसे विधायिका या कार्यपालिका के जरिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा किया गया तो 'कानून का शासन' छलावा बनकर रह जाएगा। उन्होंने जजों को इंटरनेट मीडिया के प्रभाव से भी आगाह किया।

न्यायमूर्ति रमना ने कहा कि नए मीडिया उपकरण जिनमें किसी चीज को बढ़ा-चढ़ा कर बताए जाने की क्षमता है वे सही और गलत, अच्छे और बुरे और असली तथा नकली के बीच अंतर करने में असमर्थ हैं। इसलिए मीडिया ट्रायल मामलों को तय करने में मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने 17वें जस्टिस पीडी देसाई स्मृति व्याख्यान को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए कहा कि अगर न्यायपालिका को सरकार के कामकाज पर निगाह रखनी है तो उसे अपना काम करने की पूरी आजादी की जरूरत होगी।

न्यायपालिका को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, विधायिका या कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ उन्होंने कहा जजों को भी इंटरनेट मीडिया मंचों पर जनता द्वारा व्यक्त की जाने वाली भावुक राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। कार्यपालिका के दबाव के बारे में बहुत चर्चा होती है। अब यह चर्चा यह शुरू करना भी जरूरी है कि कैसे इंटरनेट मीडिया के रुझान संस्थानों को प्रभावित कर सकते हैं।

कोरोना के कारण पूरी दुनिया के सामने आए अभूतपूर्व संकट पर सीजेआई ने कहा कि हमें आवश्यक रूप से रुककर खुद से पूछना होगा कि हमने, अपने लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कानून के शासन का किस हद तक इस्तेमाल किया है।

उन्होंने कहा कि मुझे लगने लगा था कि आने वाले दशकों में यह महामारी अभी और भी बड़े संकटों को सामने ला सकती है। निश्चित रूप से हमें कम से कम यह विश्लेषण करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए कि हमने क्या सही किया और कहां गलत किया।

बिहार में अफसरों ने संपत्ति की जानकारी छिपाई तो दर्ज होगा आपराधिक मुकदमा

राज्य ब्यूरो, पटना

▸ कार, घर से लेकर फ्लैट की खरीद की महीने भर में देनी होगी सरकार को सूचना

▸ पहले से लागू नियम का कड़ाई से पालन न होने पर सरकार ने उठाया कदम

बिहार के भारतीय प्रशासनिक सेवा व पुलिस सेवा (आइएएस-आइपीएस) अफसरों के साथ दूसरे सरकारी अफसरों-कर्मियों की संपत्ति पर भी अब सरकार की निगाह रहेगी। संपत्ति का मामूली ब्योरा छिपाने वाले अफसरों पर एक ओर जहां अनुशासनिक कार्रवाई होगी, वहीं प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट के तहत आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। अफसर यदि कार-घर जैसे संसाधनों की खरीद करते हैं तो महीने भर के अंदर इसकी सूचना सरकार को देनी होगी। राज्य के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने नियमों का हवाला देकर एक पत्र विभागों को भेजा है।

मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि अफसरों द्वारा संपत्ति की खरीद-बिक्री की जानकारी देने के प्रविधान सरकारी सेवक नियमावली में हैं। नियमों का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा, जबकि हर सरकारी सेवक को 28 या 29 फरवरी तक अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा देना होता है। अफसरों को चल-अचल संपत्ति के साथ विरासत में मिली संपत्ति, बैंक निवेश, नकदी की भी पूरी जानकारी देनी होती है।

मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि भविष्य में यदि कोई अधिकारी अपने दो मूल वेतन के बराबर निवेश करता है तो उसे इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। अफसर किसी के साथ मिलकर कोई व्यापार करता है तो उसे इसकी अनुमति लेनी होगी। यदि ऐसा नहीं होता तो इसे कदाचार माना जाएगा और विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

यदि अफसर जमीन, मकान, फ्लैट, गाड़ी खरीदते हैं तो महीने भर में इसकी जानकारी सरकार को दें। जो संपत्ति 30 हजार रुपये से अधिक मूल्य की होगी, उसका विवरण देना आवश्यक होगा, लेकिन कपड़े, बर्तन, दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विवरण देना आवश्यक नहीं है।

राजस्थान में भी सार्वजनिक करनी होगी संपत्ति की जानकारी

जासं, जयपुर: राजस्थान के सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को एक जुलाई से 31 अगस्त के बीच संपत्तियों का रिकार्ड सार्वजनिक (आनलाइन) करना होगा। ऐसा नहीं करने वालों की पद्दोन्नति व वेतन वृद्धि नहीं होगी। राज्य के कार्मिक सचिव हेमंत कुमार गेरा ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ, पारदर्शी, जवाबदेही व भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की कड़ी में अधिकारियों व कर्मचारियों की संपत्ति सार्वजनिक करने का निर्णय लिया गया है। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए सभी सेवाओं को आनलाइन किया जा रहा है। सरकार ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों के लिए भी परिपत्र जारी किया है कि जो कर्मचारी एक ही स्थान पर पांच साल से कार्यरत है, उसका तबादला दूसरे स्थान पर किया जाएगा।

गूगल ने शिकायतें मिलने पर अप्रैल में 59 हजार सामग्री हटाई

▸ देश में नए आइटी नियमों के लागू होने के बाद पहली बार किसी डिजिटल प्लेटफार्म ने जारी की अनुपालन रिपोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : गूगल ने अपनी पहली मासिक पारदर्शिता रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें उसने बताया है कि भारतीय यूजर ने इस साल अप्रैल में स्थानीय कानून या व्यक्तिगत अधिकार के उल्लंघन से संबंधी 27,700 से ज्यादा शिकायतें कीं। इसके परिणाम स्वरूप 59,350 सामग्री हटाई गई। 26 मई को नए सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) नियमों के अमल में आने के बाद गूगल मासिक अनुपालन रिपोर्ट जारी करने वाला पहला डिजिटल प्लेटफार्म है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक ने 15 मई से 15 जून के बीच मिली शिकायतों और कार्रवाई की अंतरिम रिपोर्ट दो जुलाई को प्रकाशित करने की बात कही है।

नए आइटी नियमों के तहत 50 लाख से ज्यादा यूजर वाले बड़े डिजिटल प्लेटफार्म को हर महीने अनुपालन रिपोर्ट जारी करनी होगी, जिसमें माह के दौरान मिली कुल शिकायतों और उसके आधार पर की गई कई कार्रवाई का ब्योरा देना होगा। गूगल ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे संचार लिंक का ब्योरा भी दिया है, जिसे स्वचालित तकनीक के जरिये या तो हटा दिया गया या उन तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई है।

गूगल प्रवक्ता ने कहा कि दुनियाभर में आने वाले आग्रहों के संबंध में कंपनी की पारदर्शिता का इतिहास काफी पुराना है। प्रवक्ता ने बुधवार को कहा, 'सभी आग्रहों की निगरानी की जाती है और वर्ष 2010 से ही उन्हें पारदर्शिता रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। यह पहला मौका है जब हम भारत के नए आइटी नियमों के अनुपालन में मासिक पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित कर रहे हैं। हम भारत में अपनी रिपोर्टिंग प्रक्रिया को और बेहतर करते हुए आगे और विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करेंगे।' रिपोर्ट में कहा गया है कि डाटा प्रक्रिया और सत्यापन में समय लगने के कारण आंकड़े दो महीने बाद आएंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि गूगल व यूट्यूब को अप्रैल के दौरान कुल 27,762 शिकायतें मिलीं। इनमें 26,707 (96.2 फीसद) शिकायतें कापीराइट से जुड़ी थीं, जबकि 357 (1.3 फीसद) ट्रेडमार्क की। 275 (करीब एक फीसद) शिकायतें मानहानि से संबंधित थीं।

विदाई

प्रधान न्यायाधीश ने सेवानिवृत्त हो रहे जज को बेहतरीन इंसान और मूल्यवान सहयोगी बताया

जस्टिस भूषण के फैसले उनके मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रमाण

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) एनवी रमना ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अशोक भूषण के फैसले उनके कल्याणकारी और मानवतावादी दृष्टिकोण की गवाही देते हैं। वह हमेशा एक मूल्यवान सहयोगी बने रहे।

अयोध्या और आधार जैसे कई अहम मुद्दों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाली संविधान पीठ का हिस्सा रहे जस्टिस भूषण चार जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनको विदाई देते हुए प्रधान न्यायाधीश रमना ने कहा कि उन्हें उनके न्यायिक योगदान के लिए याद किया जाएगा और धन्यवाद किया जाएगा। जस्टिस अशोक भूषण को बेहतरीन इंसान बताते हुए सीजेआइ रमना ने कहा कि उच्च न्यायपालिका को ऊंचाई पर ले जाने में उन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

सीजेआइ ने कहा कि जस्टिस भूषण की यात्रा 'वास्तव में उल्लेखनीय' रही है और उन्होंने अदालतों में न्याय देने में लगभग दो दशक बिताए हैं। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए जस्टिस भूषण की चिंता उनके विचारों और लेखन में देखने को मिलती है।

2018 में आधार पर फैसला आया था

जस्टिस भूषण केंद्र सरकार की अहम आधार योजना को सितंबर, 2018 संवैधानिक रूप से वैध ठहराने वाले पांच जजों के संविधान पीठ का भी हिस्सा थे। हालांकि, संविधान पीठ ने आधार को बैंक खातों, मोबाइल फोन और स्कूल में दाखिल से लिंक करने के प्रविधान को खारिज कर दिया था।



जस्टिस अशोक भूषण कई ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा रहे हैं। फाइल/इंटरनेट मीडिया

मराठा आरक्षण पर दिया था फैसला

जस्टिस भूषण ने उस पांच सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता की थी, जिसने पिछले महीने ही 29 साल पुराने मंडल आयोग से संबंधित फैसले को दोबारा बड़ी पीठ के सामने भेजने से इन्कार कर दिया था, जिसमें आरक्षण के कोटे को अधिकतम 50 फीसद तय किया गया था। पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के उस कानून को भी खारिज कर दिया था, जिसमें मराठों के लिए शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रविधान किया गया था। पीठ ने कहा था कि राज्य सरकार का यह कानून समता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनना गर्व की बात : इस मौके पर जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनना उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने कहा, 'बार और बेंच दो पहियों का हिस्सा हैं और इनका रिश्ता समुद्र और बादलों जैसा है।' बार हमेशा लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए खड़ा रहा है। उन्होंने सीजेआइ और सहयोगियों को धन्यवाद दिया और बेंच, बार के सदस्यों, रजिस्ट्री और निजी कर्मचारियों का आभार जताया।

2016 में सुप्रीम कोर्ट में बने थे जज : इलाहाबाद हाई कोर्ट से 13 मई, 2016 को सुप्रीम कोर्ट में जज बने जस्टिस भूषण कई ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा रहे हैं। जस्टिस भूषण सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ के हिस्सा थे, जिसने नवंबर, 2019 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने वाला फैसला सुनाया था और केंद्र सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया था।

कह के रहेंगे माधव जोशी



2 जुलाई को कोलकाता हाई कोर्ट बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामले की अगली सुनवाई करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की समिति ने बुधवार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। कोर्ट ने 30 जून तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था।

सिद्धू सुलह फार्मूले पर राजी, जल्द होगा नई भूमिका का एलान

थमी रार ▶ नवजोत को मनाने के लिए प्रियंका, राहुल व सोनिया को घंटों करनी पड़ी माथापच्ची

सम्मानजक होगी सिद्धू की भूमिका मगर अमरिंदर ही रहेंगे चुनावी कैप्टन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस हाईकमान के सुलह-समझौते के भारी प्रयासों के बाद नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ अपनी खुली जंग खत्म करने पर सहमत हो गए। पार्टी नेतृत्व ने सिद्धू को पंजाब की सत्ता सियासत में सम्मानजनक नई भूमिका का जो फार्मूला दिया है उस पर वे राजी हो गए हैं। हाईकमान ने यह भी संकेत दिया कि सिद्धू के नए सियासी रोल के प्रस्ताव पर अमरिंदर सिंह की सहमति भी मिल गई है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सिद्धू की बुधवार सुबह हुई चर्चा के बाद शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठकों के चले कई दौर में समाधान का फार्मूला निकाला गया। हल निकलने का रास्ता साफ होने के संकेत मिलने के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देर शाम सिद्धू से मुलाकात की। कांग्रेस ने संकेत दिए हैं सिद्धू के नए रोल का एलान जल्द हो जाएगा।

पंजाब कांग्रेस की अंतर्कलह का हल निकालने के लिए बुधवार सुबह प्रियंका ने सिद्धू से मुलाकात की। नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने से पहले प्रियंका ने राहुल के घर जाकर उनसे बातचीत की। प्रियंका इस पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल से मशविरा कर चुकी थीं। प्रियंका ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस में सम्माजनक भूमिका देने का अंतिम फार्मूला दिया। इस पर सिद्धू ने भी जिद छोड़ने के सकारात्मक संकेत दिए।


कांग्रेस की पंजाब इकाई में अंतर्कलह के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को नई दिल्ली में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से उनके आवास पर मुलाकात की। प्रेट्र

हालांकि हाईकमान ने सिद्धू को यह साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सिंह ही विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा रहेंगे। सिद्धू को उनसे तालमेल बिठाना होगा। सिद्धू के हामी भरने के बाद शाम को राहुल से उनकी मुलाकात हुई।

इस बीच सिद्धू ने प्रियंका से मुलाकात की अपनी मुस्कुराती तस्वीर ट्विटर पर साझा की। इस तस्वीर के जरिए सिद्धू ने सुलह का फार्मूला निकालने के प्रयासों पर अपने सकारात्मक रुख का संदेश देने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस नेतृत्व ने भी सिद्धू को सूबे की सत्ता-संगठन में सम्मानजक भूमिका देने के कई विकल्पों पर माथापच्ची की। सिद्धू से चर्चा के बाद प्रियंका राहुल के आवास पर पहुंची और उनसे चर्चा के बाद वे सोनिया से मिलने गईं।

इसके बाद राहुल खुद 10 जनपथ आकर सोनिया को अपने आवास पर ले गए। गांधी परिवार के तीनों सदस्यों के बीच लंबी चर्चा हुई और सिद्धू ने हाईकमान को झगड़ा खत्म करने का भरोसा दे दिया। शाम को राहुल से सिद्धू की मुलाकात हुई और कांग्रेस ने सुलह का रास्ता निकलने का संदेश दिया।

पंजाब कांग्रेस का यह झगड़ा गांधी परिवार के लिए कितनी बड़ा सिरदर्द था इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रियंका से इस मुद्दे पर चर्चा के बाद खुद सोनिया उनके साथ राहुल से मशविरा करने गईं। इन तीनों के बीच हुई गहन माथापच्ची के बाद भी प्रियंका की सिद्धू से बातचीत हुई जिसमें कांग्रेस महासचिव ने हाईकमान की तरफ से उनकी प्रस्तावित नई सियासी भूमिका का अंतिम फार्मूला दिया। सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व ने पंजाब चुनाव की चुनौतियों को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी लचीला रुख अपनाने के लिए सहमत करने के बाद हाईकमान ने सिद्धू को यह प्रस्ताव दिया है।

समझा जाता है कि प्रियंका की पहल को देखते हुए सिद्धू उनके फार्मूले पर सहमत हुए हैं। गौरतलब है कि सिद्धू की राहुल व प्रियंका के साथ गहरी निकटता है। पिछले विधानसभा चुनाव से पूर्व सिद्धू को कांग्रेस में लाने में प्रियंका की ही भूमिका थी। सिद्धू भी प्रियंका की बात को तवज्जो देते हैं।

पंजाब कांग्रेस कलह का हल निकालने के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति ने भी कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में चुनाव मैदान में जाने के साथ सिद्धू को अहम रोल देने के लिए उपमुख्यमंत्री या प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपने जैसे फार्मूले की सिफारिश की थी।

उप्र में ब्लाक अध्यक्षों को भी चुनावी रणनीति समझाएगी कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उप्र में विधानसभा चुनाव के लिए संगठन का नया ढांचा खड़ा करने के बाद कांग्रेस अब ब्लाक स्तर तक मिशन-2022 की रणनीति पहुंचाना चाहती है। इसके लिए जिला और ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। खास बात यह है कि गुरुवार को प्रयागराज से शुरू हो रहे कार्यक्रम आठ जुलाई तक चलेंगे, जिसमें से किसी भी शिविर में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंच सकती हैं।

तीन दशक से प्रदेश की सत्ता से बेदखल कांग्रेस इस बार पूरा जोर लगाए हुए है। प्रियंका खुद बतौर प्रदेश प्रभारी चुनावी कमान संभाले हुए हैं। संगठन सृजन अभियान चलाया गया। दावा है कि गांव-गांव तक पार्टी का संगठन खड़ा हो चुका है। इधर, प्रदेश प्रभारी के इसी माह लखनऊ प्रवास की चर्चा फिर तेज हो गई है। इसी बीच पार्टी ने जिला और ब्लाक अध्यक्षों को चुनाव के मद्देनजर प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। इन सभी नए पदाधिकारियों को पार्टी की रीति-नीति, चुनावी एजेंडा आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। सात जिलों में दो-दो दिन के शिविर लगेंगे, जिनमें आसपास के तमाम जिलों के अध्यक्ष और ब्लाक अध्यक्ष शामिल होंगे। गुरुवार को प्रयागराज से शुरुआत होगी और कार्यक्रम आठ जुलाई तक चलेंगे। इनमें से किसी भी कार्यक्रम में प्रियंका भी शामिल हो सकती हैं। वहीं, प्रदेश प्रवक्ता अशोक सिंह ने बताया कि पार्टी जन समस्याओं के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है।

विवेक तन्खा के इस्तीफे से जी-23 ने दिया कांग्रेस को बड़ा संदेश

धनंजय प्रताप सिंह, भोपाल

- विधि प्रकोष्ठ के बहाने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर लगाया निशाना
- कांग्रेस में वंशवाद के खिलाफ आवाज में अब लंबे कार्यकाल के विरोध के भी स्वर

कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने पार्टी के विधि प्रकोष्ठ (लीगल सेल) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर असंतुष्ट नेताओं के जी-23 की तरफ से पार्टी हाईकमान को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने वंशवाद के खिलाफ जंग में अब किसी पद पर लंबे समय तक जमे रहने को लेकर नैतिक आधार पर विरोध करने की शुरुआत कर दी है। माना जा रहा है कि इससे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन की मांग का दबाव बढ़ेगा। जी-23 पिछले कुछ वर्षों से मांग कर रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर गैर गांधी को अवसर दिया जाए।

इसी साल फरवरी में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव को लेकर संकेत मिल रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर इसे जून तक के लिए टाल दिया गया। इस बीच पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव और कोरोना की दूसरी लहर के चलते इस मुद्दे को फिर टाल दिया गया। विस चुनावों में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। पार्टी में अंदरूनी तौर पर खराब प्रदर्शन की समीक्षा की आवाज उठी, जिसे नकार दिया गया।

बताया जाता है कि विस चुनावों में प्रचार की कमान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाल रखी थी, जिसके चलते इस पर चर्चा की मांग दबी रह गई, जबकि जी-23 के नेता इस पर मुखर होने के मूड में थे। इस बीच अचानक विवेक तन्खा ने विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुनाव की चर्चाओं को हवा दे दी है। उन्होंने इस्तीफे की वजह बताई थी कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक एक ही पद पर रहकर न्याय नहीं कर सकता। नई पीढ़ी को यह दायित्व सौंपा जाना चाहिए।


विवेक तन्खा की फाइल फोटो।

> वंशवाद के खिलाफ तो मैं हूं। मैंने अपने बेटे वरुण तन्खा के नरसिंहपुर विधानसभा सीट से टिकट का भी विरोध किया था। मैंने कांग्रेस नेतृत्व को साफतौर पर कहा था कि वरुण मेरा बेटा है, सिर्फ इस नाते आप टिकट दे रहे हैं, यह गलत है। वह काबिल बने फिर किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस नेतृत्व ने मुझसे पूछा कि आप लीगल सेल के चेयरमैन पद पर बने रहना चाहते हों तो बताएं। मैंने कहा कि मुझे रुचि नहीं है, किसी नए व्यक्ति को मौका दें। हमें अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है।
> – विवेक तन्खा, राज्यसभा सदस्य

बंगाल हिंसा पर एनएचआरसी की समिति ने कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- समिति ने कहा- यह अंतिम रिपोर्ट नहीं, कल मामले की होगी सुनवाई
- कोर्ट ने कहा-अंतरिम रिपोर्ट की कोई प्रति नहीं की जाएंगी प्रसारित

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा गठित समिति ने बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के मामले पर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंप दी। अदालत अब दो जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगी।

गौरतलब है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का आरोप लगाने वाली कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने एनएचआरसी के अध्यक्ष को समिति गठित कर हिंसा से जुड़ी शिकायतों की जांच करने और प्रभावित इलाकों का दौरा कर 30 जून तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। इसके बाद आयोग की समिति ने सीलबंद लिफाफे में अदालत को रिपोर्ट सौंपी है। इस पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति आइपी मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार शामिल हैं। एनएचआरसी के वकील ने कहा कि यह अंतिम रिपोर्ट नहीं है और समिति के सदस्यों ने अब तक केवल 168 स्थानों का दौरा किया है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अंतरिम रिपोर्ट की कोई प्रति प्रसारित नहीं की जाएंगी। हम पहले रिपोर्ट देखेंगे और फिर तय करेंगे कि प्रसारित करना है या नहीं। एक अधिकारी ने बताया कि राजीव जैन की अध्यक्षता वाली समिति और एनएचआरसी के कई दलों ने बंगाल के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और शिकायतों की सच्चाई का पता लगाया।


कलकत्ता हाई कोर्ट की फाइल फोटो।

नारद स्टिंग मामले में ममता और मलय घटक का आवेदन स्वीकार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- पांच-पांच हजार देना होगा जुर्माना, मामले की अगली सुनवाई 15 को

नारद स्टिंग आपरेशन मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, विधि मंत्री मलय घटक और राज्य सरकार के हलफनामा देने के लिए किए गए नए आवेदन को स्वीकार कर लिया है। प्रत्येक को हलफनामे के बाबत अदालत को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा। गौरतलब है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को याचिकाकर्ताओं का आवेदन स्वीकार करने के लिए कहा था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ममता बनर्जी, विधि मंत्री मलय घटक और राज्य सरकार की ओर से हलफनामा देने के लिए नया आवेदन सोमवार को दायर किया गया था। इस मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई थी, लेकिन पांच सदस्यीय बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को पीठ ने हलफनामा दायर करने के आवेदन को स्वीकार कर लिया। सात दिनों के अंदर स्टेट लीगल अथारिटी को पांच-पांच हजार रुपये जमा करने का निर्देश दिया है।

अदालत के निर्देश में कहा गया है कि पूरे मामले पर सीबीआइ 10 दिनों के अंदर जवाब देगी, जबकि इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

यह है मामला : सीबीआइ ने नारद स्टिंग मामले को स्थानांतरित करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि जब जांच एजेंसी ने इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधि मंत्री मलय घटक ने एजेंसी के दफ्तर में आकर अवरोध पैदा किया। ऐसे में मामले को स्थानांतरित किया जाए। इसी मामले में ममता और मलय ने हलफनामा दायर करने के लिए आवेदन किया था, मगर कोर्ट ने स्वाकीरा नहीं किया था। कोर्ट ने नौ जून के अपने आदेश में हलफनामा लेने से इन्कार कर दिया था। इस पर ममता और मलय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 जून को हाई कोर्ट से कहा था कि वह सीबीआइ की याचिका पर फैसला करने से पहले ममता-मलय की अर्जियों पर पुनर्विचार करे।

धनखड़ ने लोस अध्यक्ष से अपनी शिकायत किए जाने पर जताया अफसोस

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर की गई शिकायत पर सूबे के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अफसोस जताया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा कि मुझे यह जानकर काफी दुख हुआ कि आपने लोकसभा अध्यक्ष को मेरे विधानसभा के कामकाज में हस्तक्षेप करने की कोशिश करने की बात कही है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता और यह वास्तविकता से दूर है।

उन्होंने पत्र में लिखा कि मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि आपके क्रियाकलाप के कारण कई बार राज्यपाल के पद की गरिमा को समझौता करना पड़ा है। मेरे आने की सूचना होने पर भी एक बार विधानसभा के गेट बंद थे। उसके बाद मेरे आगमन पर विधानसभा में आपकी अनुपस्थिति महसूस की गई। आपकी तरफ से यह बात भी कही गई है कि विधानसभा में पारित किए गए कई विधेयकों को राज्यपाल की ओर से अनुमोदित नहीं किया जा रहा है, जोकि गलत है।

बसपा के लिए मुसीबत है सियासी रिश्तों का 'मायाजाल'

अजय जायसवाल, लखनऊ

- भाजपा के प्रति मायावती के नरम रुख में अपना फायदा देख रही सपा
- भाजपा से कड़े मुकाबले का संदेश देकर अल्पसंख्यक वोट रोकने की है चुनौती

परिस्थितियों के हिसाब से राजनीतिक रिश्ते बनाती-बिगाड़ती रहीं बसपा मुखिया मायावती के लिए अब रिश्तों का 'मायाजाल' ही चुनौती बन गया है। मन की कड़वाहट वह जानें, लेकिन भाजपा के प्रति तुलनात्मक रूप से नरम रहे उनके रुख ने इस धारणा को आधार जरूर दे दिया कि मायावती का झुकाव भाजपा के प्रति है। सपा इस धारणा को चुनावी मैदान तक ले जाने की जुगत में है, जबकि बसपा प्रमुख के लिए चुनौती दोहरी हो गई है। अव्वल तो संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना है। साथ ही भाजपा से दूरियां दिखाकर खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय का एकमुश्त वोट सपा के पाले में जाने से रोकना भी है।

दरअसल, अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गईं हैं। सत्ता बरकरार रखने के लिए योगी सरकार जहां शहर से लेकर सुदूर गांव तक के निवासियों के बीच अपनी योजनाओं-परियोजनाओं से पैठ बनाने में जुटी है, वहीं भाजपा संगठन भी बूथ स्तर तक अपनी स्थिति को और मजबूत करने में जुटा हुआ है। भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का दावा करते हुए यूं तो सपा, बसपा और कांग्रेस भी चुनावी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने में कौन पार्टी सक्षम है।

पिछले विधानसभा और हाल के पंचायत चुनाव के अब तक के नतीजे देखे जाएं तो सपा की स्थिति बसपा से कहीं बेहतर रही है। अब विधानसभा चुनाव का रण जीतने के लिए सपा की कोशिश यही दिखाने की है कि भाजपा से बसपा नहीं, वही मुकाबला कर सकती है। बसपा को मुख्य लड़ाई से बाहर दिखाने के लिए पार्टी सुप्रीमो मायावती के भाजपा के प्रति नरम रुख दिखाने वाले बयानों को तेजी से फैलाने की कोशिश भी की जा रही है। सियासी जानकार मानते हैं कि मायावती की भाजपा के प्रति नरम रुख की धारणा के मजबूत होने का सर्वाधिक फायदा सपा को ही होगा। इससे जहां खास तौर से मुस्लिम समुदाय में दुविधा न होने पर वे एकजुट होकर सपा के साथ जा सकते हैं, वहीं सत्ताधारी भाजपा से नाराज लोगों का रुझान भी सपा की ओर होगा।

ऐसा नहीं कि बसपा को इसका इल्म नहीं कि भाजपा के साथ दिखाई देने भर के संदेश से उसका कितना नुकसान हो सकता है। पहले भी जब मायावती ने सपा से नाराजगी जताते हुए ऐसा कुछ बोला, जिससे उसकी भाजपा से नजदीकी का आभास हुआ तो भाजपा विरोधी उससे छिटक गए। यही कारण है कि 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बसपा की ताकत लगातार घटती रही है। ऐसे में भाजपा से दूरी दिखाने का बड़ा संदेश देने के लिए ही शायद मायावती ने डा. भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र के बहाने उस पर तीखा हमला बोला है। मायावती ने जहां इसे भाजपा सरकार की नाटकबाजी करार दिया है, वहीं दलितों-पिछड़ों की उपेक्षा करने का आरोप भी जड़ा है। माना जा रहा है कि जैसे-जैसे चुनाव करीब आएंगे, वैसे-वैसे बसपा सुप्रीमो के निशाने पर सपा के साथ ही भाजपा भी अब रहेगी।


बसपा प्रमुख मायावती की फाइल फोटो।

भाजपा के भी हित में हैं दूरियां

सपा और बसपा की इस रणनीति का प्रत्यक्ष रूप से भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन सियासी समीकरण यही इशारा करते हैं कि बसपा और भाजपा के बीच तल्खियां या दूरियां भाजपा के भी हित में होंगी। तर्क यही है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सपा के साथ बसपा भी विकल्प रहेगी तो वोटों का बंटवारा होगा। यह एकमुश्त वोट सपा के साथ गया तो यादव-मुस्लिम और बसपा के साथ गया तो दलित-मुस्लिम का मजबूत गठजोड़ कई सीटों पर भाजपा के लिए चुनौती बढ़ा सकता है।

सुवेंदु की सुरक्षा पर ममता सरकार से रिपोर्ट तलब

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा पर ममता बनर्जी की सरकार से रिपोर्ट तलब की है। सरकार को गुरुवार तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।

गौरतलब है कि भाजपा में शामिल होने के कुछ हफ्ते बाद सुवेंदु ने विधानसभा चुनाव से पहले पर्याप्त सुरक्षा की मांग करते हुए हाई कोर्ट में मामला दायर किया था। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इस महीने फिर हाई कोर्ट में शिकायत की कि राज्य सरकार उन्हें संवैधानिक नियमों का अनुपालन करते हुए पर्याप्त सुरक्षा नहीं प्रदान कर रही है। उन्हें अब भी केंद्रीय सुरक्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। इस मामले पर सुनवाई बुधवार को न्यायाधीश शिवकांत प्रसाद की अदालत में हुई। न्यायाधीश ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार के रुख पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

सुवेंदु तृणमूल कांग्रेस में रहते कभी सिंचाई मंत्री तो कभी परिवहन मंत्री रहे। उस वक्त उनको 'जेड प्लस' कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले मंत्रिपद से इस्तीफा दे दिया था।

तीरथ पहुंचे दिल्ली, अटकलों ने पकड़ा जोर

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- चिंतन शिविर के अगले ही दिन केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाया
- उपचुनाव से जोड़ा गया तो परिवर्तन की भी चली अटकल

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर बुधवार को दिल्ली पहुंचते ही एक बार फिर अटकलों का दौर शुरू हो गया। इस दौरे को मुख्यमंत्री के उप चुनाव से तो जोड़ा ही गया, साथ ही उप चुनाव में अड़चन की स्थिति में नेतृत्व परिवर्तन की बात भी राजनीतिक गलियारों में चली। राज्य के दो मंत्रियों की दिल्ली में मौजूदगी को भी इससे जोड़ दिया गया।

दिल्ली पहुंचे खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि वह रामनगर चिंतन शिविर में पार्टी द्वारा तय की गई चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात को दिल्ली आए हैं। हालांकि देर रात तक उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात नहीं हो पाई थी।

मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाए जाने को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा गया तो मुख्यमंत्री के उपचुनाव में आ रही अड़चन से भी। यह बात भी उठी कि यदि उपचुनाव होता है तो मुख्यमंत्री गंगोत्री सीट से शायद ही चुनाव लड़ें, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड को लेकर वहां तीर्थ पुरोहित नाराज चल रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री गढ़वाल संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली किसी विधानसभा सीट को तवज्जो दे सकते हैं। यदि उपचुनाव की स्थिति नहीं बनी तो फिर से नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है।

नेतृत्व परिवर्तन के बाद तीरथ सरकार ने पिछली सरकार में बंटे दायित्वों को निरस्त कर दिया था। दायित्व वितरण के लिए ऐसा फार्मूला निकालने पर जोर दिया जा रहा, जिससे संगठन में कहीं भी असंतोष के सुर न उभरें। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को इस मसले से भी जोड़कर देखा गया। इसके अलावा पार्टी विधायकों और कार्यकर्ताओं की जुबानी जंग सरकार व संगठन को असहज किए है। चर्चा रही कि मुख्यमंत्री इस बारे में केंद्रीय नेतृत्व से विमर्श कर सकते हैं। सियासी गलियारों में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज व राज्यमंत्री डा. धन सिंह रावत के दिल्ली पहुंचने और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से उनकी कथित मुलाकात की भी चर्चा रही। हालांकि, संपर्क करने पर धन सिंह रावत ने कहा कि वह रामनगर से लौट रहे हैं और हरिद्वार में हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से फोन पर संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन बताया गया कि वह रामनगर से ही निजी कार्यक्रम में भाग लेने दिल्ली चले गए थे।

> राष्ट्रीय दलों की सरकारों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का दिल्ली आना-जाना सामान्य बात है। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर कोई अन्य अर्थ नहीं लेना चाहिए।
> – सुबोध उनियाल, सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री।


तीरथ सिंह रावत की फाइल फोटो।

सियासत

राजद के स्थापना दिवस पर लालू की आनलाइन मौजूदगी के प्रयास में जुटे नेता प्रतिपक्ष, महागठबंधन के घटक दलों में भी नई ऊर्जा का संचार होने की संभावना

लालू के सहारे राजद में नया जोश भरने की कोशिश

अरविंद शर्मा, पटना

बिहार में विपक्षी खेमे की राजनीति के लिए लालू प्रसाद प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, लेकिन वह साढ़े तीन वर्ष से अदालती चक्कर में गुम हैं। अब जमानत पर बाहर आए हैं तो राजनीतिक रूप से सक्रिय होने में सेहत का साथ नहीं मिल पा रहा है। फिर भी राजद के 25वें स्थापना दिवस समारोह ने उनके समर्थकों की उम्मीदें जगाई हैं। पांच जुलाई को लालू राजद कार्यकर्ताओं से आनलाइन रूबरू होने वाले हैं। इसी बहाने उन्हें सक्रिय करने की कोशिश है। हालांकि अस्वस्थता की वजह से उनकी भूमिका सीमित ही रहने वाली है। माना जा रहा है कि लालू की सक्रियता से राजद समेत महागठबंधन के साथी दलों में नई ऊर्जा का संचार होगा। पिछले एक हफ्ते से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसी प्रयास में लगे हैं।

बिहार में राजनीति गर्म होने का न तो अभी मौसम है और न माहौल। लोकसभा चुनाव में अभी तीन साल और विधानसभा चुनाव में चार साल का समय है। कोरोना की वजह से राजनीतिक सक्रियता भी बेहद कम हो गई है। इंटरनेट मीडिया के जरिये सिर्फ बयानों का खेल ही चल रहा है।

बैठकों का सिलसिला भी आनलाइन चल रहा है। हालांकि लोजपा में टूट के बाद थोड़ा पारा चढ़ा है। कांग्रेस में तोड़फोड़ के खतरे ने भी सियासी तापमान को बढ़ाया है। ऐसे में लालू प्रसाद की मौजूदगी से विपक्षी दल सुकून महसूस कर सकते हैं।


नई उम्मीदें : तेजस्वी यादव की फाइल फोटो।

सत्ता पक्ष में भी हलचल

जेल से लालू के बाहर आने के बाद से बिहार के सत्ता पक्ष में भी हलचल है तो इसे अकारण नहीं कहा जा सकता है। राजद प्रमुख की गिनती सियासी रणनीतिकार नेताओं में होती है। रांची जेल में रहते हुए भी उन्होंने बिहार में सरकार गिराने की कोशिश की थी। अभी 11 जून को लालू के जन्मदिन पर विधायक तेज प्रताप यादव ने जब जीतनराम मांझी से मुलाकात की थी तो उसे भी लालू के सियासी तिकड़म से जोड़कर देखा गया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर रिहा होने का हवाला देकर लालू प्रसाद की राजनीतिक सक्रियता का विरोध किया है। उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो से संज्ञान लेने का आग्रह भी किया है।

गुजरात में पेपरलेस बनेगी भाजपा, एप से चलेगी

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : गुजरात भाजपा आने वाले दिनों में पूरी तरह पेपरलेस होने जा रही है। एप के माध्यम से पार्टी नेता, सांसद और विधायक अपने काम की जानकारी साझा करेंगे। प्रदेश कार्यालय से इसपर नजर रखी जाएगी। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेश सरकार और पार्टी तैयारियों में जुट गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने दावा किया कि गुजरात में उनकी पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस व आम आदमी पार्टी प्रेस नोट व आरटीआइ कर दफ्तरों से चलने वाली पार्टियां हैं।

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। मंत्रियों को दो-दो जिलों में जाकर लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत होने का निर्देश दिया। मंत्री इसकी रिपोर्ट तैयार कर मंत्रिमंडल की अगली बैठक में उस पर चर्चा करेंगे।

त्रिपुरा में आइपीएफटी विधायक का इस्तीफा नहीं किया गया मंजूर

- संदेशवाहक के माध्यम से भेजा गया था इस्तीफा, लेकिन मुलाकात नहीं की
- विधानसभा अध्यक्ष बोले- यह विधायी प्रक्रिया के विरुद्ध

अगरतला, प्रेट्र : त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष रेबतीमोहन दास ने कहा कि आइपीएफटी विधायक ब्रिशकेतु देबबर्मा का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। सत्ताधारी भाजपा गठबंधन में शामिल इंडिजेनस पीपुल्स फ्रंट आफ त्रिपुरा (आइपीएफटी) के विधायक ने मंगलवार को एक संदेश वाहक के माध्यम से इस्तीफा सौंप दिया और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात नहीं की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह विधायी प्रक्रिया के विरुद्ध है।

दास ने कहा, 'चूंकि विधायी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, इसलिए मैंने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। इस्तीफा सौंपते हुए देबबर्मा ने मुझसे मुलाकात नहीं की। यह उचित प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने पत्र की प्रति अपने पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को अग्रसारित कर दी। यह भी प्रक्रिया के विरुद्ध है।'

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधायक से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनका मोबाइल फोन बंद मिला।

निजी कारणों का हवाला देते हुए मंगलवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा सौंपने वाले सिमाना क्षेत्र से विधायक के तिप्राहा इंडिजेनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस (टीआइपीआरए) में शामिल होने की संभावना है। हाल ही में जिला परिषद चुनाव में यह संगठन विजयी होकर उभरा है। बता दें कि विधायक के इस्तीफे की पुष्टि के लिए विधानसभा अध्यक्ष अपने तरीके से उसकी जांच करते हैं।

300 करोड़ रुपये की लागत से टाटा मेमोरियल के सहयोग से बिहार में बनेगा कैंसर अस्पताल। 15 एकड़ भूमि पर होगा निर्माण, अस्पताल में होंगे सौ बेड।

फर्जी खबरों से बदल जाता है लोगों का व्यवहार



'5जी नेटवर्क की वजह से फैली कोरोना महामारी', 'घर के कोने में प्याज काटकर रखने से सब वायरस उस पर चिपक जाते हैं', 'सूरज की रोशनी आपको कोविड-19 से बचा सकती है'। कोरोना महामारी फैलने के बाद से ही ऐसी कई अफवाहें भी फैली हैं। ऐसी फर्जी सूचनाओं का प्रसार इंटरनेट मीडिया पर इतनी तेजी से हुआ कि अधिकारियों को इसे इन्फोडेमिक की संज्ञा देनी पड़ गई। यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन की कियारा ग्रीन और उनके साथियों ने ऐसी खबरों और सूचनाओं से लोगों के व्यवहार पर पड़ने वाले असर को लेकर अध्ययन किया है। उनके मुताबिक, आंकड़ों के आधार पर व्यवहार में बहुत फर्क तो नहीं दिखता है, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के लिए ऐसी अफवाहें संकट पैदा कर सकती हैं। अध्ययन में एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि फर्जी खबरों को लेकर सरकारों की तरफ से दी जाने वाली चेतावनी का भी लोगों पर असर बहुत कम होता है। ऐसे में इन पर लगाम के लिए सरकारों को ज्यादा प्रभावी तरीका अपनाने की जरूरत है।



क्या है सामान्य धारणा?

माना जाता है कि फर्जी खबरों से लोगों के व्यवहार पर असर पड़ता है। दावा किया जाता है कि इनसे मास्क लगाने के प्रति लोगों की रुचि कम होती है, वैक्सीन लगवाने में लोग आनाकानी करते हैं या अन्य निर्देशों का पालन नहीं करते हैं।

ऐसे किया गया फर्जी खबरों से पड़ने वाले असर पर शोध

कियारा की टीम ने 4,500 से ज्यादा लोगों पर ऑनलाइन सर्वेक्षण किया। लोगों को यह बताया गया कि खबरों से उन पर पड़ने वाले असर पर अध्ययन किया जा रहा है। उन्हें फर्जी खबर के बारे में कुछ नहीं बताया गया। इस दौरान उनके सामने चार सच्ची खबरें और साथ में उनसे मिलती-जुलती दो फर्जी खबरें सुनाई गईं। इनमें कॉफी पीने या मिर्च खाने से कोरोना वायरस से बचाव, टीके के नुकसान और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप से निजता पर खतरे जैसी बातें थीं। इन खबरों को दिखाने के बाद कुछ महीने तक लोगों के व्यवहार पर नजर रखी गई कि क्या उन्होंने ज्यादा कॉफी पी या फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप को डाउनलोड करने से बचने लगे?

यह मिला नतीजा



शोध में पाया गया कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप से निजता के खतरे की खबर पढ़ने वाले लोगों में यह एप डाउनलोड करने की इच्छा अन्य की तुलना में पांच प्रतिशत कम देखी गई। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पहले भी कहीं ऐसी खबरें पढ़ रखी थीं और उन्हें यह याद था। ऐसे लोगों में एप डाउनलोड करने की इच्छा सात प्रतिशत कम पाई गई।

छोटे प्रभाव से भी हो सकता है बड़ा नुकसान

व्यवहार में बदलाव देखने में तो बहुत कम है, लेकिन सामाजिक रूप से इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। इस सदी की शुरुआत में एमएमआर के टीके और ऑटिज्म के बीच संबंध की अपुष्ट खबरें फैल गई थीं। इससे बच्चों के टीकाकरण की दर में करीब 10 प्रतिशत की कमी आई थी। टीकाकरण में इस छोटी सी कमी से ही उस दौरान खसरा (मीजल्स) के मामलों में बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई थी। इससे समझा जा सकता है कि कोरोना महामारी के इस दौर में कोई अफवाह किस तरह से लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकती है।

इनपुट : प्रेट्र जागरण इन्फो

हिजबुल कमांडर समेत तीन आतंकी ढेर

आंतक से लोहा ▶ कुलगाम मुठभेड़ में दो सैन्यकर्मी भी घायल, देर रात तक कार्रवाई

आत्मसमर्पण का मौका देने के बाद भी नहीं माने आतंकी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर में सुरक्षाबल ने अपने आतंकरोधी अभियान को जारी रखते हुए बुधवार को चिम्मर (कुलगाम) में हिजबुल मुजाहिदीन के जिला कमांडर शिराज मौलवी समेत तीन आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ में दो सैन्यकर्मी भी जख्मी हुए हैं।

पुलिस ने मारे गए आतंकियों की पहचान की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों की माने तो एक आतंकी विदेशी है। दो स्थानीय आतंकियों में एक हिजबुल मुजाहिदीन का जिला कमांडर शिराज मौलवी व दूसरा मुदस्सिर है। पुलिस के अनुसार, मुठभेड़स्थल और उसके साथ सटे इलाकों की तलाशी जारी है। मारे गए आतंकियों के शवों को कोविड-19 प्रोटोकाल के तहत सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को पूरा कर उत्तरी कश्मीर में दफनाया जाएगा। जानकारी के अनुसार, पुलिस ने सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों के साथ मिलकर दोपहर को कुलगाम के चिम्मर में छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया। जवान जैसे ही गांव में दाखिल होने लगे तो बाहरी छोर पर स्थित एक बाग के साथ सटे मोहल्ले में छिपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। पहली गोली दोपहर 12:40 बजे चली। आतंकियों को आत्मसमर्पण करने की अपील की, लेकिन उन्होंने फायरिंग जारी रखी।



जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमले के बाद यहां यूएवी (अनमैंड एरियल वेहिकल) से निगरानी की जा रही है। प्रेट्र

ड्रोन का रिमोट कंट्रोल अखबार का बंडल निकला

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू के बाहरी क्षेत्र कालूचक और रत्नूचक में सैन्य शिविर के पास सोमवार तड़के नजर आए ड्रोन की जांच में जुटे अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरे में नजर आई एक वस्तु को ड्रोन का रिमोट कंट्रोल समझा, लेकिन जांच में वह अखबार का एक बंडल निकला।

आतंकियों व अलगाववादियों के मददगार ठेकेदारों पर नकेल

नवीन नवाज, श्रीनगर

आतंकवाद के प्रति जीरो टालरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए जम्मू-कश्मीर में आतंकियों, अलगाववादियों और राष्ट्रविरोधी तत्वों के साथ प्रत्यक्ष-परोक्ष संबंध रखने वाले ठेकेदारों पर नकेल कसी जा रही है। ऐसे सभी ठेकेदारों, सप्लायर व कंपनियों को सरकारी कार्यों के ठेके व आपूर्ति आदेश इत्यादि के आवंटन पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। सरकार ने यह कदम आतंकियों व अलगाववादियों के वित्तीय नेटवर्क को पूरी तरह तबाह करने के लिए उठाया है। प्रदेश सरकार ने पहले ही सरकारी विभागो में बैठे राष्ट्रविरोधी तत्वों की सेवाएं समाप्त कर उन्हें घर भेजने का एक अभियान शुरू कर रखा है।

सूत्रों ने बताया कि पुलिस व खुफिया एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वह उन सभी लोगों व कंपनियों का पता लगाएं, जो प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से राष्ट्रविरोधी गतिविधियों व तत्वों के साथ लिप्त होने के बाद सरकारी योजनाओं के ठेके प्राप्त कर रहे हैं। उनके ठेके रद करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में बीते मई में हुई एक बैठक में इस विषय पर गहन विचार-विमर्श हुआ। उपराज्यपाल ने तत्कालिक मुख्य सचिव और प्रशासनिक सचिवों को ऐसा तरीका खोजने को कहा था जिससे संदिग्ध चरित्र वाले तत्व किसी भी तरह से सरकारी कार्यों को पूरा करने के ठेके प्राप्त न कर सकें। सामान्य प्रशासन विभाग ने 10 मई को एक नोटिस जारी कर कहा था कि वह उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक का संज्ञान लें और उसमें लिए गए फैसले पर रिपोर्ट भी दें।

कई पूर्व आतंकी भी कर रहे हैं ठेकेदारी : सूत्रों के अनुसार, यह फैसला करने में उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया गया है जिनके अनुसार कई पूर्व आतंकी बंदूक छोड़ने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ जुड़ गए हैं और ठेकेदारी कर रहे हैं। इन्हें आराम से कई संवेदनशील कार्य का ठेका भी मिला है। यह ठेकों के जरिए होने वाली कमाई का एक हिस्सा तथाकथित तौर पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए भी उपलब्ध कराते हैं।

हरियाणा में आंदोलनकारियों से क्षति की भरपाई का कानून लागू

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा ने आंदोलनकारियों से संपत्ति को पहुंचे नुकसान की भरपाई का कानून लागू कर दिया है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। सरकार ने गत 28 जून को इसकी अधिसूचना जारी की है, लेकिन इसे एक अप्रैल से लागू माना है। इस फैसले को कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ हरियाणा व दिल्ली की सीमा पर पिछले सात माह से जमे आंदोलनकारियों के प्रति सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है।

इस कानून के तहत आंदोलन के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों से कराने का प्रविधान है। हाई कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार के अनुसार यह कानून किसी भी आंदोलन की आड़ में लोगों की दुकानों, रेहड़ियों, घरों, सरकारी कार्यालयों, गाड़ियों, बसों तथा अन्य सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों पर नकेल डालेगा। नुकसान की विधिवत वसूली कर भरपाई करने का प्रविधान इस कानून में है। इसके लिए एक ट्रिब्यूनल गठित होगा, जो इस प्रकार की शिकायतों की जांच करेगा तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लेगा। बता दें कि हरियाणा में अब तक कई ऐसे आंदोलन हो चुके हैं।

धरनास्थल पर अवांछित हरकतों से सख्त हुई हरियाणा सरकार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले सात माह से चल रहे आंदोलन को पूरी तरह राजनीतिक मानते हुए हरियाणा सरकार अब सख्ती के मूड में है। आंदोलन की वजह से अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है और आसपास के लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। इतना ही नहीं, आंदोलन स्थल आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। सरकार का मानना है कि असल किसानों का इस आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है और वे इसमें शामिल भी नहीं हैं। चंडीगढ़ में पत्रकारों के सवालों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट कहा कि जिस दिन टकराव होगा, उस दिन हमारा संयम भी टूट जाएगा। इसलिए कांग्रेस के हाथों में खेल रहे किसान संगठन तीन कृषि कानूनों को खत्म करने की राजनीतिक जिद छोड़कर वार्ता के लिए आगे आएं। केंद्र सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। यदि किसी को आंदोलन करना भी है तो लिखकर देना होगा।

आंदोलन को बदनाम करने की साजिश : राकेश टिकैत

प्रथम पृष्ठ से आगे

भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने माहौल बिगाड़ते हुए प्रदर्शनकारियों पर हमला किया है। भाजपाई तीन दिन से यहां जुट रहे थे। काले झंडे व हथियार लेकर आए और मारपीट की। खुद ही अपनी कारों के शीशे तोड़ दिए। इस दौरान दो प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं, जिन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीटा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर लग रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया।

जांच के बाद कार्रवाई : पुलिस : एसपी सिटी द्वितीय ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से तहरीर दी गई है। जांच के बाद कार्रवाई होगी। हमला करने वाले आरोपितों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

कुंडली से एक और किशोरी हुई लापता, बंधक बनाने का आरोप

जागरण संवाददाता, सोनीपत : कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ महीनों से चल रहे धरने की जगह के आसपास के इलाकों में महिलाओं के साथ अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। कुंडली थानाक्षेत्र से एक और किशोरी लापता हो गई है। परिवार ने उसको बंधक बनाकर रखने की एफआइआर दर्ज कराई है। पीड़ित परिवार प्याऊ मनियारी के पास की एक कालोनी में रहता है, जो जीटी रोड के किनारे आंदोलन स्थल से लगी हुई है। किशोरी का परिवार उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और रोजी-रोटी के लिए यहां रहता है।

'बासी लड्डू' के विरोध में बंद रही हनुमानगढ़ी

जागरण संवाददाता, अयोध्या

बासी लड्डू चढ़ाए जाने के विरोध में अयोध्या स्थित बजरंगबली की प्रधानतम पीठ हनुमानगढ़ी घंटों विवाद के साये में रही। कोरोना संकट को देखते हुए हनुमानगढ़ी में गत 20 अप्रैल से ही लड्डू या कोई अन्य प्रसाद चढ़ाए जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस बीच हनुमानगढ़ी की रसोई से हनुमान जी को सुबह-शाम जलपान एवं राजभोग प्रस्तुत किए जाने का नियम ज्यों का त्यों चलता रहा। रोक श्रद्धालुओं की ओर से प्रसाद चढ़ाने को लेकर थी।

कोरोना संक्रमण में कमी देखते हुए मुख्य महंत गद्दीनशीन प्रेमदास ने अन्य संतों से विचार-विमर्श के बाद तय किया कि बुधवार से दर्शनार्थियों की ओर से लाए जाने वाले भोग को भी स्वीकार किया जाएगा। बुधवार को यह व्यवस्था घंटे भर भी नहीं चल पाई। भोग लगा रहे पुजारियों ने प्रसाद चढ़ाने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा, भोग के रूप में जो लड्डू आ रहा है, वह बासी है। बासी लड्डू से आजिज अर्चकों ने कुछ देर के लिए हनुमानगढ़ी का मुख्य द्वार बंद कर दिया। इसी बीच कुछ नागा साधु उन दुकानदारों तक पहुंचे, जहां से भोग के रूप में बासी लड्डू बेचे जाने की आशंका थी। नागा साधुओं का कहना था कि 20 अप्रैल को प्रसाद चढ़ाए जाने पर रोक के बाद से जो लड्डू बचे थे, कुछ दुकानदार वही लड्डू बेच रहे हैं। इस बीच कुछ पल के लिए तनातनी भी पनपी और बेचने के लिए दुकान में रखे लड्डू सड़क पर फेंक दिए गए। इसके विरोध में हनुमानगढ़ी के इर्द-गिर्द भोग की सौ के करीब दुकानें बंद कर दी गईं। अफरा-तफरी के बाद जिलाधिकारी अनुजकुमार झा ने गद्दीनशीन महंत प्रेमदास, निर्वाणी अनी अखाड़ा के महासचिव महंत गौरीशंकरदास से चर्चा कर मंदिर का बंद दरवाजा खुलवाया।

अभिनेत्री मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का निधन

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई : अभिनेत्री मंदिरा बेदी के पति और फिल्मकार राज कौशल का बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 49 वर्षीय राज को बुधवार तड़के करीब साढ़े चार बजे दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल ले जाने से पहले घर पर ही उनकी मौत हो गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया गया। राज ने 1989 में बतौर कापीराइटर अपने करियर की शुरुआत साल की थी। उसके बाद बतौर निर्देशक उन्होंने दो फिल्में 'शादी के लड्डू' (2004) और 'एंथोनी कौन है' निर्देशित की।



मुंबई में बुधवार को पति राज कौशल की अंतिम यात्रा के दौरान अभिनेत्री मंदिरा बेदी। प्रेट्र

नसीरुद्दीन की तबीयत पहले से बेहतर, दिलीप कुमार अस्पताल में भर्ती

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई : अभिनेता नसीरुद्दीन शाह बीते दो दिनों से मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि न्यूमोनिया की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके फेफड़ों में एक पैच भी पाया गया है, जिसका इलाज डाक्टर कर रहे हैं। दैनिक जागरण से हुई बातचीत में नसीरुद्दीन शाह के बेटे विवान शाह ने कहा कि पापा की तबीयत पहले से बेहतर है। उधर दिलीप कुमार को फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनुपम खेर ने नसीरुद्दीन की सलामती की दुआ करते हुए शायराना अंदाज में लिखा, 'जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब! कमबख्त न्यूमोनिया इंपोर्टेंस (महत्व) चाह रहा है।

सेवा की आड़ में मतांतरण, 250 परिवार बन गए ईसाई

जागरण संवाददाता, फतेहपुर

उप्र के फतेहपुर जिले में सेवा और मदद की आड़ लेकर हसवा ब्लाक के 25 गांवों में एक मिशनरी संस्था ने करीब दो हजार परिवारों पर मतांतरण का जाल बिछा रखा है। अब तक 250 परिवार ईसाई मत अपनाकर पूजा पद्धति तक बदल चुके हैं, जो इस खेल का बड़ा सुबूत है।

ग्रामीणों के मुताबिक, संस्था की दो टीमों में से एक गरीब बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर उन्हें कापी-किताब, बस्ता, मच्छरदानी, दवा आदि देती है। परिवारों को रोजगार से जोड़ने के लिए सिलाई मशीन व भैंस देने के साथ ही अपने मिशन से जोड़कर नौकरी देती है। कोरोना काल में संस्था ने 414 वृद्ध व विधवा महिलाओं में से प्रत्येक को साढ़े तीन हजार की धनराशि उनके बैंक खाते में भेजी। ब्लाक के 25 गांवों में संस्था का सेवा व मदद का यह अभियान पिछले छह साल से चल रहा है। दूसरी टीम प्रार्थना सभा को हथियार बनाकर परिवारों को मतांतरण के लिए प्रेरित करती है। ब्लाक के गांवों में इस काम में 20 से अधिक लोग लगे हैं।

इन गांवों में चल रहा खेल : हसवा, एकारी, टीसी, मिचकी, छीतमपुर, आकूपुर, कमालीपुर, उसरैना, भभैचा, करीमपुर, अतरहा, सेमरी, आंबापुर, नरई, कैथाहार, छिछनी, बिलारीमऊ, बिलंदा, लतीरपुर, फरीदपुर, हासिमपुर भेदपुर, असवा वक्सपुर, घूरी बुजुर्ग, टीकर व उसरैना।

जांच कराकर होगी कार्रवाई : साध्वी

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री साध्वी निरजंन ज्योति ने कहा कि हसवा ब्लाक में मिशनरियों के लोगों द्वारा नौकरी का लालच देकर मतांतरण कराने की शिकायतें मिल रही हैं। तीन साल पहले टीसी गांव में ऐसी ही शिकायत पर मौके पर जाकर मतांतरण करने वाले परिवारों को गंगाजल से स्नान कराकर व तुलसी दल देकर उनके मत में वापसी कराई थी। पूरे मामले में जांच कराने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं। आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

अभी तक ऐसी कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। एक-दो मामले चर्चा में आए हैं। उनकी जांच कराई जा रही है। जबरन मतांतरण कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। - **अपूर्वा दुबे, डीएम**

दरवाजा बंद कर करते प्रार्थना : छीतमपुर के रामपूजन, भभैचा के संत कुमार तिवारी व टीसी के रामसेनही सिंह आदि ने बताया कि निश्शुल्क सामान बांटने वाली संस्था की गतिविधियों को लेकर शंका है।

पहले भी कई बार उठी आवाज : मिशन मतांतरण के तहत संस्था चुपचाप यह काम कर रही है। आसपास के लोगों से जानकारी होने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कई बार आवाज उठाई। प्रार्थना सभा के नाम पर मतांतरण की शिकायत की गई।

युवती ने ऊधमपुर के परिवार पर लगाया मतांतरण का आरोप

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर : कश्मीर के बाद अब जम्मू संभाग के ऊधमपुर जिले में भी कथित लव जिहाद और मतांतरण का मामला सामने आया है। आरोप लगाने वाली युवती मूलत : पंजाब के जालंधर की है। उसकी ऊधमपुर के शाह परिवार में शादी हुई है। युवती का आरोप है कि उसका बहला-फुसलाकर मतांतरण कराया गया। यही नहीं, उसे ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने और वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश भी की गई। युवती के इन आरोपों पर आरोपित परिवार से जुड़ी संस्था जियो और जीने दो की ओर से बुधवार को सफाई दी गई। अध्यक्ष तारिक शाह ने कहा कि युवती पांच दिन में आरोप साबित करे।

'तेजी से बढ़ रही मतांतरण की घटनाएं, इसे रोकने की जरूरत'

जागरण संवाददाता, मेरठ : मुस्लिम संस्थाएं देश में तेजी से हिंदुओं का मतांतरण कर रही हैं। मतांतरण एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। इसको रोकने के लिए काम करना होगा। साधु-महात्मा, बच्चे व महिलाएं आदि को इनसे बचाना है। इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। केवल सरकार के भरोसे नहीं बैठना है। त्योहारों का स्वरूप बदल गया है। बुधवार को मेरठ पहुंचे विहिप के केंद्रीय मंत्री आचार्य राधा कृष्ण मनौडी ने विश्व गीता संस्थान की ओर से आयोजित बैठक में मंच से संबोधन करते हुए यह बातें कहीं।

गुजरात एटीएस ने एक को किया गिरफ्तार

गांधीनगर, आइएएनएस : गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में मतांतरण करवाने वाले गिरोह में शामिल एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। अहमदाबाद निवासी आरोपित सलाउद्दीन के खिलाफ उत्तर प्रदेश एटीएस ने मुकदमा कायम किया है। मतांतरण रोधी कानून लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। पुलिस के अनुसार, सलाउद्दीन पर गिरोह को धन मुहैया कराने का आरोप है।

कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों से फंडिंग का अंदेशा

आशुतोष गुप्ता, गाजियाबाद : गाजियाबाद के मसूरी के डासना देवी मंदिर में दो जून की रात घुसे दो संदिग्ध विपुल विजयवर्गीय उर्फ रमजान व कासिफ और इन्हें मंदिर में भेजने वाले सलीमुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद पकड़ में आए मतांतरण कराने वाले गिरोह के बाद मामले में लगातार अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस नेटवर्क को तोड़कर गिरोह के सदस्यों पर पकड़ मजबूत कर रही हैं। मतांतरण के खेल में कश्मीर में सक्रिय कुछ आतंकी संगठनों द्वारा फंडिग का अंदेशा जताया जा रहा है। इन संगठनों द्वारा एक ट्रस्ट के माध्यम से फंडिंग किए जाने का अंदेशा है।

मिसाल

बच्ची की मदद को 1.20 लाख में खरीदे 12 आम

जमशेदपुर की तुलसी के लिए फरिश्ता बने मुंबई के अमिय हेटे, आनलाइन पढ़ाई को फोन खरीदने के लिए आम बेचने की बात जानी तो स्मार्टफोन व नकद पैसे भेजे

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर

अपनी पढ़ाई जारी रखने के उद्देश्य से सड़क किनारे आम बेचकर स्मार्टफोन के लिए पैसे जमा कर रही जमशेदपुर की 12 साल की तुलसी के सपनों को अब नया आयाम मिल गया है। मुंबई स्थित कंपनी वैल्यूएबल एडुटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमेया हेटे तक उसकी पुकार पहुंची तो हेटे ने तुलसी के एक दर्जन आम एक लाख 20 हजार रुपये में खरीदकर मदद की। हेटे ने नकद पैसों के साथ तुलसी को एक स्मार्टफोन भी भेजा है। साथ ही, उसमें दो साल तक के लिए इंटरनेट पैक भी डलवा दिया है।

पिता की नौकरी छूटी तो बढ़ गई दिक्कत: जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित बागमती रोड इलाके में एक सरकारी बंगले के आउटहाउस में तुलसी का परिवार रहता है। कोरोना काल में तुलसी के पिता की नौकरी छूट गई और उसका स्कूल भी बंद हो गया। तुलसी पढ़-लिखकर अफसर बनना चाहती है, लेकिन आनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन जरूरी था। पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह तुलसी के लिए स्मार्टफोन खरीद सकें। ऐसे में सड़क किनारे के पेड़ों से पक कर गिरे आम बेचकर वह स्मार्टफोन के लिए पैसे जमा करने लगी, लेकिन पांच-10 हजार रुपये जमा करना उसके लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही थी।

स्थानीय युवती ने इंटरनेट मीडिया पर डाली जानकारी: जमशेदपुर की वर्षा जहांगीरदार को पता चला कि तुलसी आम बेच रही है, ताकि कम से कम पांच हजार रुपये जुटाकर पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन खरीद सके। वर्षा ने तुलसी की तकलीफ को इंटरनेट मीडिया पर साझा किया। मुंबई की एक कंपनी के प्रबंध निदेशक अमेया हेटे तक बात पहुंची तो उन्होंने तुलसी का फोन नंबर पता किया और उसके पिता से कहा कि वह तुलसी से एक दर्जन आम 1.20 लाख रुपये में खरीद रहे हैं। तुलसी और परिवार के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हेटे ने तुलसी के पिता के बैंक खाते में रुपये भेज दिए।



अमेया हेटे, जिन्होंने तुलसी के एक दर्जन आम एक लाख 20 हजार रुपये में खरीदे। एएनआइ

तुलसी ने दिया धन्यवाद

तुलसी ने अमिय हेटे को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब उसकी पढ़ाई शुरू हो गई है। यूट्यूब और गूगल से भी कई जानकारियां मिल रही हैं। इस संबंध में हेटे ने कहा कि तुलसी के मन में पढ़ाई के प्रति ललक ने उन्हें प्रभावित किया। उनकी कंपनी आनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में काम करती है। हम सदैव ऐसे लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। बेटियां पढ़ेंगी तो देश बढ़ेगा।

मप्र के मंत्री बोले- 'मरना है तो मर जाओ'

नईदुनिया, भोपाल

'मेरे सामने किसी की नेतागीरी नहीं चलेगी। आपको जो करना है, करो। मरना है तो मर जाओ।' यह बोल हैं मध्य प्रदेश सरकार में स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार के।

दरअसल, मंगलवार को पालक महासंघ, मध्य प्रदेश के पदाधिकारी उनसे मिलने पहुंचे थे। पालक संघ की मांग थी कि स्कूल बंद होने के बाद भी एक अप्रैल से आनलाइन कक्षाओं की फीस वसूली जा रही है। यह फीस कम की जाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। पहले शांति से बात सुन रहे मंत्री इंदर सिंह परमार पदाधिकारियों द्वारा आंदोलन की बात कहने पर उखड़ गए और कैबिनेट बैठक में जल्द पहुंचने का हवाला देकर अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगे। इस पर पालक संघ के पदाधिकारियों ने कहा- 'हम क्या करें? क्या हम मर जाएं?' इसके जवाब में मंत्री ने कहा- 'मरना है तो मर जाओ, जो करना है, करो, लेकिन नेतागीरी मत करो।' पूरा घटनाक्रम मप्र की राजधानी भोपाल स्थित मंत्री के श्यामला हिल्स स्थित सरकारी बंगले पर हुआ। इसके बाद पालक संघ ने मंत्री के इस बयान का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया।

स्कूलों की मनमानी रोकने व आनलाइन कक्षा के नाम पर मनमानी फीस न लिए जाने की मांगें लेकर मंत्री से मिलने पहुंचे थे। उन्हें हाई कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया, जिसमें कहा गया था कि महामारी तक फीस में बढ़ोतरी न की जाए। किंतु, मंत्री ने कह दिया कि -'मरना है तो मर जाओ।' उनका यह व्यवहार ठीक नहीं है।
- **कमल विश्वकर्मा, अध्यक्ष, पालक महासंघ, मध्य प्रदेश**

जिस न्यायालयीन आदेश का वे हवाला दे रहे थे, वह पिछले वर्ष का है। अधिनियम में दस फीसद वृद्धि का प्रविधान है। इससे अधिक फीस बढ़ाने पर शिकायत कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी कमेटी से की जा सकती है। बाद में वे अभद्रता करने लगे, तो मैं भी आवेश में आ गया था, इसलिए ऐसे शब्द निकल गए।
- **इंदर सिंह परमार, स्कूल शिक्षा मंत्री, मप्र**

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बढ़ी फीस वसूलने पर बोर्डों से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोविड-19 की वजह से स्कूलों के बंद होने और केवल आनलाइन शिक्षण होने के बावजूद तमाम स्कूलों द्वारा बढ़ी हुई फीस वसूले जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश (यूपी बोर्ड), आइसीएसई और सीबीएसई बोर्ड से जवाब मांगा है। साथ ही इसी मामले में पहले से दाखिल कई याचिकाओं के साथ इस याचिका को भी संबद्ध करने का निर्देश दिया है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने बुधवार को मुरादाबाद पेरेंट्स आफ आल स्कूल एसोसिएशन (अनुज गुप्ता व नौ) तथा अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। सरकारी वकील ने बताया कि सभी बोर्ड के लिए शुल्क विनियमन के आदेश जारी किए गए हैं जिसमें ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस पर रोक लगा दी गई है।

10 फीसद से ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों में हो सख्ती

निर्देश ▸ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 14 राज्यों को लिखा पत्र, उपायों के बारे में बताया

परिस्थितियों का बेहतर तरीके से आकलन करने के बाद ही प्रतिबंधों को उठाने और छूट देने को कहा

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना महामारी की दूसरी लहर में सुधरते हालात के बीच केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अत्यधिक सावधान रहने को कहा है। राजस्थान, त्रिपुरा, असम, केरल और बंगाल समेत 14 राज्यों को लिखे पत्र में केंद्र ने कहा है कि जिन जिलों में 21-27 जून के बीच कोरोना संक्रमण की दर 10 फीसद से ज्यादा थी, वहां रोकथाम के उपायों को सख्ती के साथ लागू किया जाए।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि मामलों में कमी आने के साथ ही निगरानी बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। उन्होंने जिला और तहसील स्तर पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। नए मामलों वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जिला नोडल अधिकारी जिलाधिकारी/ नगर आयुक्त के साथ मिलकर काम करें। साथ ही जरूरत के हिसाब से जरूरी रोकथाम के उपायों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

भूषण ने 29 जून को लिखे पत्र में कहा है कि हालात सुधरने के साथ ही प्रतिबंधों को उठाया जा रहा है और उनमें छूट दी जा रही है, लेकिन इसका फैसला बहुत ही सोच समझकर, सावधानीपूर्वक और परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद किया जाना चाहिए। भूषण ने उपरोक्त राज्यों के अलावा मणिपुर, सिक्किम, पुडुचेरी, ओडिशा, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को भी पत्र लिखा है।

भूषण ने अपने पत्र में गृह मंत्रालय के 29 अप्रैल के आदेश का भी जिक्र किया है, जिसमें कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी राज्यों से सख्त उपाय करने को कहा गया था। भूषण ने कहा है कि ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों में हालात में सुधार करने के लिए सख्त उपाय किए जाने जरूरी हैं। उन्होंने संबंधित राज्यों में 10 फीसद से ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों का भी जिक्र किया है।

14 दिनों तक सख्ती लागू रखें : भूषण ने कहा कि जो जिला प्रशासन संक्रमण दर को देखते हुए पाबंदियां लगाने का फैसला करता है तो उसे 14 दिनों तक प्रभावी रखा जाए। जिले के जो इलाके कंटेनमेंट जोन में नहीं हों, वहां प्रतिबंधों में छूट दी जा सकती है या पाबंदियों को हटाया जा सकता है। इससे तीसरी लहर को रोकने में मदद मिलेगी।



कोरोना संक्रमण के खिलाफ मुंबई में रेलवे स्टेशन पर सतर्कता बरकरार है। स्टेशन पर यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। बुधवार को एक स्टेशन पर इस महिला यात्री का भी कोरोना टेस्ट के लिए स्वैब सैंपल लिया गया। प्रेट्र

बुधवार सुबह आठ बजे तक कोरोना की स्थिति	
कुल मामले	3,03,62,848
मौतें	817
कुल मौतें	3,98,454
स्वस्थ	60.729
कुल स्वस्थ	2,94,27,330
दैनिक संक्रमण दर	2.34 फीसद
जांचें (मंगलवार)	19,60,757
कुल जांचे (मंग.तक)	41,01,00,044

मामले साढ़े पांच लाख से नीचे

जेएनएन, नई दिल्ली : कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। संक्रमण के नए मामले कम हो रहे हैं और ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट आ रही है और इनकी संख्या साढ़े पांच लाख से नीचे आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में सक्रिय मामले कुल संक्रमितों का 1.77 फीसद रह गए हैं। लगातार तीसरे दिन मृतकों की संख्या हजार से नीचे रही है। वास्तव में 81 दिन बाद सबसे कम 817 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 50 हजार से कम नए केस मिले हैं, हालांकि, एक दिन पहले की तुलना में नए मरीजों की संख्या कुछ ज्यादा है। परंतु, मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.92 फीसद हो गई है।

डेल्टा वैरिएंट को प्रभावी ढंग से असरहीन करती है कोवैक्सीन

वाशिंगटन, प्रेट्र : भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर अमेरिका से बहुत अच्छी खबर आई है। अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान यानी एनआइएच ने कोवैक्सीन को कोरोना वायरस के सबसे खतरनाक वैरिएंट डेल्टा के खिलाफ बहुत अधिक प्रभावी बताया है। अमेरिकी संस्था के मुताबिक कोवैक्सीन अल्फा वैरिएंट के खिलाफ भी कारगर है।

एनआइएच ने कहा है कि कोवैक्सीन लेने वाले लोगों के ब्लड सीरम को लेकर दो अध्ययन किए गए। दोनों ही अध्ययनों में यह देखने को मिला कि वैक्सीन मजबूत एंटीबाडी पैदा करती है जो अल्फा यानी बी.1.1.7 और डेल्टा यानी बी.1.617 दोनों वैरिएंट को प्रभावी तरीके से असरहीन करती है। अल्फा वैरिएंट इंग्लैंड में और डेल्टा वैरिएंट भारत में सबसे पहले सामने आया था। अमेरिका के इस शीर्ष स्वास्थ्य शोध संस्थान का भारत के साथ विज्ञान के क्षेत्र में निकट संबंधों का लंबा इतिहास रहा है। एनआइए ने कहा कि उसकी आर्थिक मदद से एक सहायक पदार्थ विकसित किया गया था, जिसने कोवैक्सीन को और प्रभावी बना दिया। भारत समेत दुनिया के विभिन्न देशों में कोवैक्सीन अब तक ढाई करोड़ से ज्यादा को लगाई जा चुकी है।

लक्षण वाले मरीजों में 78 फीसद प्रभावी

संस्थान के मुताबिक तीसरे चरण के परीक्षण के अंतरिम रिपोर्ट में वैक्सीन लक्षण वाले मरीजों में 78 फीसद कारगर पाई गई है। जबकि, कोरोना के गंभीर लक्षणों के खिलाफ यह सौ फीसद प्रभावी है। वहीं, बिना लक्षण वाले संक्रमितों में यह 70 फीसद प्रभावी मिली है।

निष्क्रिय कोरोना वायरस से बनी है वैक्सीन : कोवैक्सीन में सार्स-कोव-2 के निष्क्रिय वायरस का इस्तेमाल किया गया है। यह निष्क्रिय वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद अपनी प्रतिकृति तो पैदा नहीं कर सकता, लेकिन उसके खिलाफ एंटीबाडी पैदा हो जाती है।

एनआइएच ने कहा कि कोवैक्सीन के दूसरे चरण के परीक्षण के नतीजे प्रकाशित हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और वायरस के खिलाफ बेहतर प्रतिरक्षा प्रदान करती है। संस्थान के मुताबिक कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण का सुरक्षा संबंधी डाटा इस साल के अंत तक उपलब्ध होगा।

न्यूज गैलरी

हरियाणा सरकार के कोरोनिल किट खरीदने पर रोक नहीं

चंडीगढ़ : योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा निर्मित कोरोनिल किट खरीदने के हरियाणा सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में खरीद पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मालूम हो कि हरियाणा सरकार ने एक लाख कोरोनिल किट खरीदकर कोरोना रोगियों को मुफ्त में वितरित करने का फैसला किया है। (राब्यू)

श्री अमरनाथ यात्रा शुरू कराने की मांग हुई तेज

चंडीगढ़ : अमरनाथ बर्फानी लंगर आर्गेनाइजेशन (सबलो) ने श्री अमरनाथ यात्रा रद करने के निर्णय को गलत बताते हुए कोरोना नियमों का पालन करते हुए इसे शुरू करने की मांग की है। इतना ही नहीं, इस मांग को लेकर गुरुवार से प्रदर्शन करने का एलान किया है। यहां प्रेस क्लब में श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर आर्गेनाइजेशन के महासचिव राजेंद्र ने सवाल उठाया कि जब माता वैष्णो देवी मंदिर खुला तो श्री अमरनाथ यात्रा बंद क्यों है? जबकि, कोरोना की दूसरी लहर के बाद सबकुछ खुल रहा है। (राब्यू)

जम्मू-कश्मीर में स्वजन के लिए 'सक्षम' योजना

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को कोरोना महामारी में अपने एकमात्र कमाऊ स्वजन को गंवाने वाले परिवारों के साथ सहानुभूति जताते हुए ऐसे परिवारों के लिए विशेष सहायता योजना 'सक्षम' शुरू की। उन्होंने कोविड-19 के कारण बेसहारा हुए बच्चों व परिवारों में सक्षम योजना के तहत छात्रवृत्ति और पेंशन प्रमाणपत्र भी बांटे। उन्होंने कहा कि यह लोग बिना किसी वित्तीय दिक्कत एक सम्मानजनक जिंदगी बसर कर सकें, इसके लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। (राब्यू)

यूपी में सबसे कम उम्र की बच्ची पर वैक्सीन का ट्रायल

कानपुर : कोरोना वायरस की तीसरी लहर में छोटे बच्चों के प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) बच्चों की वैक्सीन लाने की तैयारी में जुटा है। उत्तर प्रदेश में कानपुर समेत देश के छह स्थानों पर 02-06 वर्ष की उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो गया। कानपुर में आर्यनगर स्थित प्रखर हास्पिटल में सूबे की सबसे छोटी ढाई साल की वालंटियर बच्ची को वैक्सीन लगाई गई। (जासं)

बाबा रामदेव को निर्देश, एलोपैथी पर अपना मूल बयान पेश करें

▸ योग गुरु ने की है सभी शिकायतों को दिल्ली स्थानांतरित किए जाने और कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग

▸ पटना और रायपुर चैप्टरों ने रामदेव के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थीं

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बाबा रामदेव को निर्देश दिया कि वह कोरोना महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल पर अपने बयान का मूल रिकार्ड पेश करें।

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश राय की पीठ ने रामदेव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा, 'वह मूल चीज क्या है जो उन्होंने कही थी? आपने पूरी चीज सामने नहीं रखी है।' इस पर रोहतगी ने कहा कि वह ट्रांस्क्रिप्ट के साथ मूल वीडियो दाखिल करेंगे। पीठ ने इस पर सहमति जताते हुए मामले की सुनवाई पांच जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। शीर्ष अदालत रामदेव की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कोरोना महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के खिलाफ उनकी टिप्पणी पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) द्वारा बिहार और छत्तीसगढ़ में दर्ज कराई गईं विभिन्न एफआइआर के सिलसिले में कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है। आइएमए के पटना और रायपुर चैप्टरों ने रामदेव के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थीं जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी टिप्पणियों से कोरोना नियंत्रण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और महामारी के खिलाफ लोग समुचित उपचार लेने से परहेज कर सकते हैं।

याचिका में बाबा रामदेव ने पटना और रायपुर में दायर शिकायतों को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग भी की है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के दौरान रोहतगी ने पीठ को बताया कि रामदेव प्रख्यात शख्सियत हैं और योग व आयुर्वेद के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम के दौरान रामदेव ने उन्हें भेजा गया वाट्सएप संदेश पढ़ा था। रामदेव ने स्पष्ट कर दिया था कि उनके मन में डाक्टरों या किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। रोहतगी ने कहा कि पिछले साल जब पतंजलि 'कोरोनिल' लेकर आई थी तो एलोपैथिक डाक्टर उनके खिलाफ हो गए थे। उन्होंने कहा, 'वह उनके खिलाफ नहीं हैं। वह विभिन्न स्थानों पर क्यों जाएं, हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।'

वैक्सीन की कमी से कई राज्यों में टीकाकरण प्रभावित

जागरण टीम, नई दिल्ली

देश में टीकाकरण अभियान में तेजी आई है। साथ ही टीकाकरण के सापेक्ष में वैक्सीन की आपूर्ति न हो पाने से कई राज्यों में अभियान प्रभावित हुआ है। कई केंद्रों पर वैक्सीन खत्म होने के चलते लोगों को लौटना पड़ा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उप्र व हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में यही स्थिति है। बंगाल सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए दावा किया कि बंगाल को छोटे राज्यों से भी कम वैक्सीन दी गई है। उनका आरोप है कि वैक्सीन की कमी के चलते राज्य में टीकाकरण अभियान प्रभावित हो रहा है।

यूपी में चार लाख टीके ही लगेंगे : यूपी में भी कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान की चाल वैक्सीन की कमी के कारण अब सुस्त हो गई है। गुरुवार से प्रतिदिन 10 लाख टीके और पूरे जुलाई महीने में तीन करोड़ टीके लगाए जाने के लक्ष्य को झटका लगा है।

झारखंड में बंद रहे ज्यादातर केंद्र, महज 15 हजार को लगा टीका : झारखंड में वैक्सीन का स्टाक खत्म होने से टीकाकरण पूरी तरह प्रभावित हुआ है। बुधवार को जिलों में बची-खुची ही वैक्सीन लग सकी।



वैक्सीन उपलब्ध नही होने से देश के कई राज्यों में टीकाकरण केंद्र बंद हो गए है। झारखंड के रांची शहर में बुधवार को बंद पड़ा एक सेंटर। एएनआइ

धीमा हुआ टीकाकरण, लगातार दूसरे दिन 50 लाख से कम लगे टीके

जेएनएन, नई दिल्ली : कोरोना वायरस के खिलाफ 21 जून से शुरू हुए टीकाकरण के महाभियान में अब सुस्ती नजर आने लगी है। वजह चाहें वैक्सीन की कमी की हो या कुछ और पिछले दो दिनों से 50 लाख से भी कम डोज लगाई जा रही हैं। को-विन एप के मुताबिक बुधवार रात नौ बजे तक मात्र 27,07,151 डोज ही लगाई जा सकी थीं। जबकि, मंगलवार को 36.35 लाख डोज लगाई गई थीं। इन सभी को मिलाकर अब तक कुल 33.04 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं।

छत्तीसगढ़ में सिर्फ 900 कोविशील्ड मौजूद : छत्तीसगढ़ के राज्य टीकाकारण अधिकारी डा. अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि जिलों में टीका वितरण करने के बाद राज्य के वैक्सीन भंडार गृह में सिर्फ 900 कोविशील्ड मौजूद है। **राजस्थान में दो फीसद केंद्रों पर ही टीकाकरण :** राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की जरूरत के मुताबिक केंद्र सरकार से आपूर्ति नहीं होने के कारण बुधवार को कई वैक्सीनेशन सेंटर बुधवार को बंद रहे। करीब दो फीसद केंद्रों पर ही टीकाकरण हो सका।

कोवैक्सीन की बूस्टर डोज के नतीजे नवंबर तक आ सकते हैं

नई दिल्ली, एएनआइ : अगर सबकुछ ठीक रहा तो इस साल के आखिर तक देश को कोरोना वायरस के खिलाफ देसी टीके की बूस्टर डोज भी मिल जाएगी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की तीसरा यानी बूस्टर डोज का ट्रायल चल रहा है और इसके नतीजे इस साल नवंबर तक आने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि कोवैक्सीन की बूस्टर डोज मई में लांच हुई थी। उसके बाद दिल्ली और पटना के एम्स में इसका परीक्षण शुरू हुआ था। इस समय देश के 12 केंद्रों पर कोवैक्सीन की बूस्टर डोज का परीक्षण चल रहा है।

कोवैक्सीन के लिए ब्राजील से करार नियमों के मुताबिक

हैदराबाद, एएनआइ : भारत बायोटेक ने स्पष्ट किया है कि ब्राजील के साथ कोवैक्सीन को लेकर हुए करार में सभी नियमों का पालन किया गया है। 29 जून तक उसे ब्राजील से न तो कोई अग्रिम भुगतान ही मिला है और न ही उसने टीके की आपूर्ति ही की है। ब्राजील ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद बुधवार को कोवैक्सीन की दो करोड़ डोज के 2332.8 करोड़ रुपये को निलंबित करने का एलान किया।

केंद्र ने फर्जी कोरोना टीकाकरण शिविर मामले में बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बंगाल सरकार से कोलकाता के कुछ इलाकों में कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से कोरोना टीकाकरण शिविर आयोजित करने के मामले की जांच कर अगले दो दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बंगाल के मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी को पत्र लिखकर मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।

भूषण द्वारा लिखे गए पत्र में बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के 25 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को लिखे गए उस पत्र का संदर्भ दिया गया है, जिसमें कथित तौर पर अनधिकृत लोगों द्वारा टीकाकरण शिविर लगाए जाने को लेकर ध्यान आकर्षित कराया गया था। भूषण ने पत्र में कहा कि कोलकाता नगर निगम के कुछ इलाकों में लगाए गए टीके में किसी भी लाभार्थी को कोविन के जरिये टीकाकरण प्रमाण-पत्र नहीं मिला है, जिससे इन शिविरों के वास्तविक होने पर आशंका पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि इसलिए अनुरोध किया जाता है और इस मामले की तुरंत जांच की जाए और जरूरी हो तो मामले में उचित एवं सख्त कदम उठाए जाए। यह भी अनुरोध किया जाता है कि इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट अगले दो दिनों में मंत्रालय को भेजी जाए। गौरतलब है कि कोलकाता पुलिस इस मामले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें फर्जी आइएएस अधिकारी देबांजन देब भी शामिल है, जो शहर में फर्जी कोविड टीकाकरण शिविरों के आयोजन का मास्टरमाइंड था। वह खुद को कोलकाता नगर निगम का संयुक्त आयुक्त बताता था।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी उठाए सवाल : दूसरी ओर, कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल में फर्जी टीकाकरण शिविर के मास्टरमाइंड देबांजन देब के मामले में बंगाल सरकार से उठाए गए कदमों के बारे में सवाल उठाते हुए हलफनामा मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ का नेतृत्व करते हुए मामले में तीन में से दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकारी वकील अनिर्बान राय से पूछा कि मामले का मुख्य आरोपित कैसे नीली बत्ती वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा था।

ममता भड़कीं, भाजपा की भूमिका पर जताया संदेह

इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगे जाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई और भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इस मामले में भाजपा की ही भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह बंगाल की छवि खराब करने की साजिश रच रही है। भाजपा के कुछ लोग फर्जी वैक्सीन घोटाले में शामिल हैं। सारी जानकारी समय पर सामने आ जाएगी। उन्होंने संदेह जताया कि कहीं यह भाजपा की साजिश तो नहीं है। ममता ने इस दौरान स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

केंद्र की दलील ठुकराई

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

केंद्र सरकार ने याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामे में कहा था कि कोरोना अन्य महामारियों से भिन्न है और एकमुश्त अनुग्रह राशि देने के बजाय सरकार की प्राथमिकता उस पैसे को अस्पताल और स्वास्थ्य के ढांचागत संसाधन बढ़ाने, टेस्टिंग, टीकाकरण आदि पर खर्च की है। सरकार ने कोरोना महामारी की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए कोर्ट से अनुरोध किया था कि कानून में दिए शब्द 'शैल' यानी जरूरी को 'मे' यानी विवेकाधिकार की तरह पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने यह तर्क ठुकराते हुए कहा कि कानून का मंतव्य एकदम स्पष्ट है और इसका मतलब साफ है। लाभकारी प्रविधानों का अक्षरशः मतलब निकाला जाना चाहिए ताकि कानून का उद्देश्य पूरा हो, न कि निष्फल। अगर 'शैल' को 'मे' पढ़ा जाएगा तो कानून का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा।

हजारों परिवारों को मिलेगी आदेश से राहत : शीर्ष अदालत के इस आदेश से उन परिवारों को कुछ राहत मिलेगी जिन्होंने कोरोना महामारी मे अपनों को खोया है और आर्थिक संकट में फंस गए हैं। अभी तक देश में कोरोना से 3,85,000 मौतें हो चुकी हैं और यह संख्या बढ़ सकती है।

'अदालत ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया'

▸ कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को 10 लाख रुपये देने की मांग की

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस ने बुधवार को दावा किया कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने नरेंद्र मोदी सरकार को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया है। कम से कम अब सरकार को मुआवजे की सही राशि तय करके पीड़ितों को राहत देनी चाहिए। यह सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।' पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना प्रभावित परिवारों के साथ खड़े नहीं होकर एक बार फिर देश को निराश किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि अब कोरोना मुआवजा कोष की स्थापना की जाए और कोरोना के कारण जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपये की मदद दी जाए। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार लोगों की मदद करने से पीछे हट गई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वह पूरी तरह बेनकाब हो गई है। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री राजधर्म का पालन करें और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकारण के मुखिया के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि वह महामारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति सहानुभूति दिखाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना पीड़ित परिवारों को मुआवजे से वंचित करने की दृष्टि से कांग्रेस/संप्रग द्वारा बनाए गए कानून को कमजोर करने के मोदी सरकार के प्रयास को भी अदालत ने खारिज कर दिया है।

पेट्रो मूल्य वृद्धि को लेकर भी बोला हमला

राहुल गांधी ने पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'सार्वजनिक परिवहन के लिए लंबी-लंबी असुविधाजनक कतारें सिर्फ कोरोना प्रतिबंधों की वजह से नहीं हैं। सही कारण जानने के लिए अपने शहर में पेट्रोल और डीजल के दामों को देखिए।'

सेवा

ओम दिव्य दर्शन संस्थान के जरिये हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी व गया में कराएंगे श्राद्ध, कोरोना संक्रमण के चलते अस्थियां विसर्जित नहीं कर पाने वालों को मिलेगा सहारा

अब अस्थि विसर्जन करेगा डाक विभाग

शिव सोनी, बिलासपुर

लाकडाउन व कोरोना संक्रमण के चलते मृत स्वजन की अस्थियां गंगाजी में प्रवाहित नहीं करा सके लोगों के लिए राहत वाली खबर है। डाक विभाग ने अस्थि विसर्जन योजना शुरू की है, जिसमें स्पीड पोस्ट से अस्थियों को ट्रेन डाक के जरिये हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी व गया भेजा जाएगा। वहां ओम दिव्य दर्शन सामाजिक संस्था द्वारा श्राद्ध कराया जाएगा। इस पुनीत कार्य के लिए डाक विभाग व संस्था के बीच अनुबंध हुआ है।

कोरोनाकाल में अनेक लोगों ने अपनों को खो दिया। उस समय हालात ऐसे नहीं थे कि मृत स्वजन की अस्थियों को पवित्र नदियों में प्रवाहित कर सकें। अब भी अस्थियां घर या मुक्तिधाम में बनाए लाकर में सुरक्षित रखी गई हैं। स्वजन विसर्जन करना चाहते हैं, पर कोरोना संक्रमण के भय से विसर्जन व श्राद्ध अनुष्ठान के लिए नहीं जा पा रहे हैं। उन्हें परिस्थितियां सामान्य होने का इंतजार है। इसे देखते हुए ही डाक विभाग आगे आया है। योजना के तहत अस्थि विसर्जन करने वाले स्वजन को संस्था की वेबसाइट ओमदर्शनडाट ओआरजी पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस दौरान भरे गए फार्मेट के अनुसार संबंधित स्थलों के पंडित का नाम, पता, मोबाइल नंबर व श्राद्ध की तिथि मैसेज के माध्यम से आवेदक को मिल जाएगा। इसी पते पर डाकघर में जाकर स्पीड पोस्ट करना होगा। डाकघरों में अस्थियां पहुंचने के बाद तत्काल भेजने की व्यवस्था की गई है। देश के सभी प्रमुख डाकघरों में इस सुविधा को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्राथमिकता के साथ सेवा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

वजन व दूरी के आधार पर शुल्क : बिलासपुर संभागीय डाक अधीक्षक केपी वर्मा ने बताया कि इस पुनित कार्य को खास प्राथमिकता से करने के निर्देश हैं। स्पीड पोस्ट का शुल्क अस्थियों के वजन व गंतव्य स्थान की दूरी के अनुसार होगा। स्पीड पोस्ट को संबंधित पते पर महज 72 घंटे में पहुंचा दिया जाएगा। हालांकि, संबंधित जगह यदि लाकडाउन है तो इसमें पांच से सात दिन लग सकते हैं।



अंतिम यात्रा में देंगे साथ। फाइल

लाइव दिखाएंगे श्राद्ध, घर भी पहुंचेगा गंगाजल

डाक अधीक्षक वर्मा का कहना है कि शोक संतप्त परिवार के लिए श्राद्ध कार्यक्रम लाइव वेबकास्ट किया जाएगा, ताकि स्वजन संतुष्ट हो सकें। श्राद्ध के बाद डाक विभाग संबंधित स्वजन को एक बोतल गंगाजल पहुंचाएगा। इस सेवा के एवज में किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

आज से फूलों की घाटी का दीदार कर सकेंगे

संवाद सहयोगी, गोपश्वर(चमोली)

कोरोना के तेजी से सामान्य होते हालात के बीच चमोली जिले में समुद्रतल से 12995 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज गुरुवार से पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। फूलों की घाटी खुलने से पर्यटन कारोबारियों में उत्साह है। वन विभाग की ओर से भी फूलों की घाटी जाने वाले पैदल मार्ग व पुलों की मरम्मत का कार्य लगभग पूरा कर दिया है।

कोरोना संक्रमण के चलते बीते वर्ष एक अगस्त को फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोली गई थी। तब 942 पर्यटकों ने घाटी का दीदार किया था। बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष घाटी को 45 दिन पहले खोला जा रहा है। हालांकि, सामान्य परिस्थितियों में घाटी को खोलने की निर्धारित तिथि एक जून है। लेकिन, कोरोनो संक्रमण के चलते इस बार भी यह संभव नहीं हो पाया।

इस बीच नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अधिकारी घाटी में व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं। पार्क के प्रभारी निदेशक अमित कंवर ने बताया कि इस समय घाटी में तकरीबन 50 प्रजाति के फूल खिले हुए हैं। बताया कि कोविड गाइडलाइन के साथ उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों के पर्यटक भी घाटी के दीदार को आ सकते हैं।

जम्मू और कटड़ा से चलेंगी आधा दर्जन ट्रेन

जागरण संवाददाता, जम्मू : भारतीय रेलवे ने जम्मू-कश्मीर को देश के विभिन्न राज्यों से जोड़ने वाली आधा दर्जन रेलगाड़ियों को जुलाई के पहले सप्ताह से चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेन जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटड़ा से चलेंगी। बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे तक की रिवर्स ट्रांस्क्रिप्शन पालीमरेस चेन रिएक्सन (आरटीपीसीआर) निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के कोरोना टेस्ट का इंतजाम भी किया गया है। ट्रेन चलाए जाने से पर्यटन गतिविधियों में तेजी आएगी।

अंतरराष्ट्रीय यात्री विमानों का निलंबन 31 जुलाई तक बढ़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना वायरस के कारण निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री विमानों पर लागू निलंबन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। विमानन नियामक डीजीसीए ने बुधवार को यह जानकारी दी।

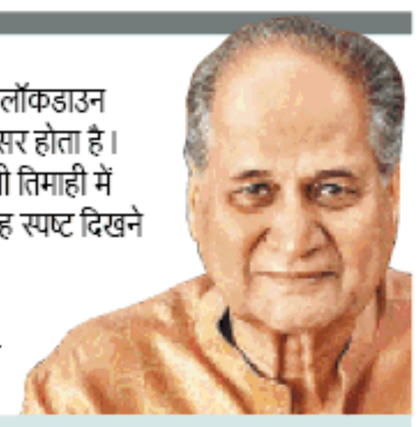
चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य खुले

राज्य ब्यूरो, देहरादून : उत्तराखंड में चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के दरवाजे सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं। वन विभाग ने संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों से प्रतिबंध हटा दिया है। अलबत्ता, वर्षाकाल में रास्ते खराब होने के कारण कार्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला और राजाजी नेशनल पार्क के चीला, मोतीचूर, रानीपुर पर्यटक जोन बंद रहेंगे। राज्य के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जेएस सुहाग के अनुसार कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ढिकाला को छोड़कर अन्य पर्यटक जोन खोल दिए गए थे।

जेट के कर्जदाताओं की डूबेगी 95 फीसद रकम

नई दिल्ली : बंद पड़ी विमानन कंपनी जेट एयरवेज की समाधान योजना के तहत उसके कर्जदाताओं की करीब 95 फीसद रकम डूब जाएगी। कंपनी के लिए जालान-कालरॉक कंसोर्टियम ने जो समाधान योजना पेश की और जिसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने मंजूरी दी, उसके तहत वित्तीय कर्जदाताओं को सिर्फ 380 करोड़ रुपये मिलेंगे। इन कर्जदाताओं की 7,807 करोड़ रुपये की मांग मंजूर की गई थी। (प्रेट्र)

कारोबार पर लॉकडाउन का गंभीर असर होता है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनियों के प्रदर्शन यह स्पष्ट दिखने का अंदेशा है।
– राहुल बजाज, पूर्व चेयरमैन, बजाज ऑटो



सेंसेक्स	52,482.71	▼ 66.95
निफ्टी	15,721.50	▼ 26.95
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 45,783	▼ ₹264
चांदी प्रति किलोग्राम	₹67,532	▼ ₹60
डॉलर	₹74.32	▲ ₹0.09
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 74.87	

कोर सेक्टर का उत्पादन करीब 17 फीसद बढ़ा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: कोरोना की दूसरी लहर के चरम के बावजूद मई में कोर सेक्टर का उत्पादन पिछले वर्ष समान अवधि के मुकाबले 16.8 फीसद बढ़ा है। हालांकि पिछले वर्ष मई में भी कोरोना की वजह से कमोबेश देशभर में लॉकडाउन जैसी स्थिति थी।

इस वर्ष मई में कच्चे तेल और खाद को छोड़ अन्य सभी सेक्टर के उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई। कोर सेक्टर के तहत आठ प्रमुख उद्योग कोयला, बिजली, खाद, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, स्टील व रिफाइनरी उत्पाद शामिल हैं।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष मई में कोयले का उत्पादन 6.9 फीसद, कच्चे तेल का 6.3 फीसद और खाद का उत्पादन 9.6 फीसद गिरा। मई में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 20.1 फीसद, रिफाइनरी उत्पाद में 15.3, स्टील में 59.3, बिजली में 7.3 और सीमेंट के उत्पादन में 7.9 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

साढ़े तीन लाख गांवों में पहुंचेगा ब्रॉडबैंड इंटरनेट

हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के सात राज्य शामिल

कैबिनेट के फैसले

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: जल्द ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व हिमाचल प्रदेश समेत 16 राज्यों के 3.61 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का काम शुरू होने जा रहा है। इन राज्यों में केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल के अलावा पूर्वोत्तर भारत के सातों राज्य शामिल हैं। इस काम के लिए सरकार सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) मॉडल अपनाएगी। इसके लिए 19,041 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस राशि का इस्तेमाल वाएबिलटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के रूप में होगा। निजी कंपनियां गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के साथ उनके रखरखाव एवं संबंधित कार्य करेंगी। वैश्विक बोली के आधार पर कंपनी का चयन होगा और उन्हें वीजीएफ से मदद दी जाएगी। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई।

संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि अब तक 1.56 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है।

ईसीएलजीएस के विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी

जाब्यू, नई दिल्ली : कोरोना से प्रभावित सेक्टर की मदद के लिए लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड एफेक्टेड सेक्टर्स को बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके तहत लोन देने के लिए 50,000 करोड़ का फंड रखा गया है। पहले से चल रही इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत 1.5 लाख करोड़ की अतिरिक्त लोन की सुविधा को भी मंजूरी दी गई।

मर्जी से फंड नहीं खर्च कर पाएंगे मंत्रालय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण माने जाने वाले 19 मंत्रालयों व विभागों को छोड़कर अन्य सभी मंत्रालयों व विभागों के खर्च को सीमित करने का कदम उठाया गया है। इनमें से कई विभागों को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर, 2021) के लिए सालाना आवंटन का अधिकतम 20 फीसद ही खर्च करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 से उपजी स्थिति को देखते हुए कुछ एहतियाती कदम उठाने पड़ रहे हैं। बुधवार को ही अप्रैल-मई के राजकोषीय घाटे के आंकड़े भी सामने आए हैं। इन दोनों महीनों में सरकार का कर संग्रह ठीक कहा जा रहा है। दूसरी तिमाही में सरकार को यह तेजी बने रहने की उम्मीद नहीं है।

डिस्कॉम की दशा सुधारने को सरकार लाई नया कार्यक्रम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राज्यों की बदहाल बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की दशा व दिशा सुधारने की एक और कोशिश का आगाज केंद्र सरकार ने किया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में डिस्कॉम के लिए पांच वर्षों तक चलने वाले सुधार आधारित कार्यक्रम का एलान किया गया है। सरकार का कहना है कि कार्यक्रम के तहत डिस्कॉम को कुल 3.03 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया जा सकता है। एनडीए के कार्यकाल में यह तीसरा मौका है जब डिस्कॉम की हालात सुधारने के लिए इस तरह का शर्त आधारित सुधार कार्यक्रम घोषित किया गया है। वैसे, कैबिनेट की मंजूरी से पहले इस फैसले के बारे में दो दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा कर दी थी और उसके पहले आम बजट 2021-22 में भी इसी तरह का एलान किया गया था।

बिजली मंत्री आरके सिंह ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बताया, अभी तक डिस्कॉम के लिए जो योजना लागू थी, उसमें सभी के लिए नियम समान थे। अब राज्यों के लिए अलग-अलग नियम होंगे। योजना पर केंद्र की तरफ से 97,000 करोड़ का आवंटन होगा। केंद्र से फंड हासिल करने के लिए राज्यों को हर वर्ष समय पर ऑडिटेड खाता-बही पेश करना होगा, बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी का इंतजाम अपने बजट से करना होगा।

...क्योंकि आज पहली तारीख है

जागरण डेस्क, नई दिल्ली : मानसून के साथ यह माह कई बदलाव लेकर आएगा। इस महीने से बैंकिंग से लेकर टीडीएस संबंधी कई प्रक्रियाओं में ऐसे बदलाव हैं, जो करदाताओं से लेकर आम आदमी और खाताधारकों को प्रभावित करेंगे। गुरुवार से होने वाले अहम बदलावों में ये प्रमुख हैं:

- एसबीआइ के बेसिक सेविंग्स अकाउंट धारकों को बैंक एटीएम और ब्रांच से सिर्फ चार मुफ्त निकासी की अनुमति होगी। उसके बाद प्रत्येक नकद लेनदेन पर 15 रुपये चार्ज लगेगा, जिस पर जीएसटी भी देना होगा।
- एसबीआइ में हर वित्त वर्ष में अब सिर्फ 10 चेक वाली एक चेकबुक का मुफ्त उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद इतने ही चेक वाली चेकबुक के लिए 40 रुपये और 25 पन्नों की चेकबुक के लिए 75 रुपये (प्लस जीएसटी) देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों को इस शुल्क के दायरे से बाहर रखा गया है।
- सिंडिकेट बैंक का पुराना आइएफएससी कोड और चेकबुक गुरुवार से अमान्य हो जाएंगे।
- आइडीबीआइ बैंक 20 पन्नों वाली एक चेकबुक मुफ्त देगा। उसके बाद पांच रुपये प्रति चेक के हिसाब से चेकबुक के लिए चार्ज लिया जाएगा।
- कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक में विलय कर दिया गया है। दोनों बैंकों के ग्राहकों को अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से युक्त नई चेकबुक लेने को कहा गया है।
- करदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। जिन करदाताओं ने पिछले दो वर्षों से आइटीआर दाखिल नहीं किया है, उनसे अधिक टीडीएस लिया जाएगा। यह नियम उन करदाताओं के लिए है, जिनके लिए टीडीएस देनदारी 50,000 रुपये से अधिक है।
- घर बैठे ही लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकेगा। पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा, फिर घर से ही टेस्ट देना होगा। टेस्ट में पास होने के बाद लर्निंग लाइसेंस आपके घर पहुंच जाएगा।
- अमूल दूध की कीमत में उसके सभी ब्रांडों के लिए दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जाएगी।

दिसंबर तक रिफाइंड पाम ऑयल आयात से प्रतिबंध हटा

नई दिल्ली, प्रेट्र: सरकार ने रिफाइंड पाम ऑयल पर लगा प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से दिसंबर तक के लिए हटा लिया है। इससे घरेलू बाजार में खाद्य तेलों के दाम घटेंगे। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने अपनी अधिसूचना में स्पष्ट किया कि केरल के किसी भी बंदरगाह से आयात की अनुमति नहीं होगी। प्रतिबंधित कैटेगरी की वस्तुओं के आयात के लिए कारोबारियों को डीजीएफटी से लाइसेंस लेना पड़ता है।

सरकार ने इस सप्ताह मंगलवार को क्रूड पाम ऑयल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी या शुल्क इस वर्ष सितंबर अंत तक के लिए घटाकर 10 फीसद कर दिया था। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन कदमों से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों के दाम में कमी आएगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह दाम की दैनिक निगरानी करेगा।

निवेशकों की संपत्ति 25 .46 लाख करोड़ रुपये बढ़ी

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना की दूसरी लहर ने कारोबार जगत को भले ही नुकसान पहुंचाया हो, घरेलू शेयर बाजारों पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं दिखा है। इस वर्ष पहली अप्रैल से 30 जून तक की अवधि यानी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान इक्विटी निवेशकों की कमाई में 25,46,954.71 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। पहली तिमाही के आखिर तक बीएसई का 30-शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक 2,973.56 अंक मजबूत हो चुका है।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान घरेलू शेयर बाजारों की यह उपलब्धि इसलिए और महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से राज्यों में इस तिमाही का बड़ा हिस्सा लॉकडाउन में बीता है। इसी तिमाही में बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 15 जून को 2,31,58,316.92 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंचा। इस अवधि में 24 मई को बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण पहली बार तीन लाख करोड़ डॉलर यानी करीब 220 लाख करोड़ रुपये के पार गया। 25 जून को बीएसई का सेंसेक्स 52,925.04 पर बंद हुआ और 28 जून को इंट्रा-डे में 53,126.73 के शीर्ष स्तर तक पहुंचा।

पिछले वित्त वर्ष के दौरान बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में एक वर्ष पहले के मुकाबले 90,82,057.95 करोड़ बढ़कर 2,04,30,814.54 करोड़ हो गया था।

2,31,58,316.92 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंचा बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 15 जून को

53,126.73 के शीर्ष स्तर तक पहुंचा 28 जून को इंट्रा-डे में सेंसेक्स

जीएसटी व्यवस्था में टैक्स दरें घटीं, अनुपालन बढ़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र : 2017 में पहली जुलाई को जीएसटी लागू होने के बाद से देश में टैक्स की दरें कम हुई और अनुपालन बढ़ा है। जीएसटी व्यवस्था के चार वर्ष पूरे होने के मौके पर वित्त मंत्रालय ने एक के बाद एक ट्वीट में कहा, इस व्यवस्था के तहत देशभर में पिछले चार वर्षों के दौरान 66 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार, जीएसटी लागू होने के बाद करदाताओं में टैक्स का अनुपालन भी बढ़ा है। उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क तथा मूल्यवर्धित कर (वैट) समेत 17 स्थानीय टैक्स और 13 सेस को खत्म कर 2017 में पहली जुलाई को जीएसटी व्यवस्था लागू की गई थी। वित्त मंत्रालय ने कहा, जीएसटी ने टैक्स अनुपालन को आसान कर दिया है। कोरोना के बीच जीएसटी काउंसिल ने कारोबारियों की राहत के लिए कई स्पष्टीकरण भी जारी किए हैं।

जीएसटी के तहत 40 लाख रुपये तक सालाना राजस्व वाले कारोबारियों को दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं, डेढ़ करोड़ तक राजस्व वाले कारोबारी कंपोजिट स्कीम चुनकर सिर्फ एक फीसद जीएसटी देकर कारोबार कर सकते हैं। सेवा क्षेत्र में 20 लाख तक सालाना राजस्व वाले कारोबारियों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। उससे अधिक व 50 लाख तक राजस्व वाले सेवा क्षेत्र के कारोबारी कंपोजिट स्कीम के तहत छह फीसद जीएसटी का निचला स्तर चुन सकते हैं।

देश की आर्थिक व्यवस्था में मील का पत्थर : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को देश की आर्थिक व्यवस्था में मील का पत्थर करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे टैक्स की संख्या में कमी आई है, अनुपालन बढ़ा है और आम आदमी पर टैक्स की देनदारी घटी है। जीएसटी के चार वर्ष पूरे होने पर मोदी ने कहा कि जीएसटी के बाद पारदर्शिता और टैक्स संग्रह में भी मजबूती देखी गई है। पीएम ने कैबिनेट द्वारा बुधवार को लिए गए फैसलों को भी देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला बताया।

समय पर जीएसटी चुकाने वाले 54,000 कारोबारी होंगे सम्मानित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : समय पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न फाइल करने और भुगतान करने वाले कारोबारियों को सरकार ने सम्मानित करने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय के निर्देश पर केंद्रीय परोक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने 54,439 ऐसे कारोबारियों की पहचान की है, जिन्होंने जीएसटी की सफलता में अहम योगदान दिया है। सम्मानित होने वाले करदाताओं में सबसे अधिक 15,131 महाराष्ट्र से हैं, जबकि 7,254 करदाताओं के साथ कर्नाटक दूसरे और 5,589 करदाताओं के साथ तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश आठवें नंबर पर है, जहां के सिर्फ 2,179 उद्यमियों को सम्मानित किया जा रहा है। बता दें कि चार साल पहले पहली जुलाई को ही जीएसटी प्रणाली लागू की गई थी।

सीबीआइसी के मुताबिक, सम्मानित होने वालों में 88 फीसद करदाता एमएसएमई सेक्टर के हैं। इनमें 36 फीसद हिस्सेदारी माइक्रो इंटरप्राइजेज, 41 फीसद स्माल और 11 फीसद हिस्सेदारी मीडियम इंटरप्राइजेज की है। इन करदाताओं का चयन सीबीआइसी को मिलने वाले डाटा के आधार पर किया गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सीबीआइसी इन करदाताओं के सम्मान में प्रशस्ति पत्र जारी कर रहा है, जिसे जीएसटी नेटवर्क के जरिये उन्हें ई-मेल से भेजा जाएगा। पिछले आठ महीने से जीएसटी की वसूली एक लाख करोड़ से अधिक हो रही है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि सरकार करदादाताओं की सुविधा को लेकर प्रतिबद्ध है।

जीएसटी पंजीकरण में अब नहीं होगा पैन का फर्जीवाड़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र : जीएसटी पंजीकरण में पैन कार्ड के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने नई व्यवस्था शुरू की है। टैक्स चोरी के लिए किसी और के पैन नंबर के जरिये पंजीकरण हासिल करने की बहुत सी शिकायतें सामने आई हैं। जीएसटी पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था शुरू की गई है जिसमें पैन नंबर डालते ही पता चल जाएगा उससे कोई पंजीकरण हुआ है या नहीं। इसके तहत व्यक्ति को खुद पहल करनी होगी और उसे जीएसटी पोर्टल पर जाकर पता करना होगा कि किसी ने उसके पैन का दुरुपयोग तो नहीं किया है। जीएसटीएन ने कहा, अगर किसी को पता चलता है कि जीएसटी पंजीकरण के लिए किसी और ने उसके पैन का दुरुपयोग किया है तो वह जीएसटीएन के माध्यम से शिकायत कर सकता है। शिकायतों को संबंधित टैक्स अधिकारी को भेज दिया जाएगा, जिसके कार्यक्षेत्र में धोखाधड़ी से पंजीकरण हुआ है।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

जम्मू-कश्मीर में 'दरबार मूव' पर लगाम

जम्मू : जम्मू-कश्मीर में दो राजधानियों की व्यवस्था पर एक अहम फैसला लिया गया है। गर्मियों की राजधानी श्रीनगर व सर्दियों की राजधानी जम्मू होने के कारण सारा सरकारी अमला व दस्तावेज एक शहर से दूसरे शहर ले जाए जाते थे। 'दरबार मूव' नाम से प्रचलित यह व्यवस्था अब खत्म हो जाएगी। (राब्यू)

बंगाल में 'स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड' योजना, 10 लाख तक लोन

कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना एक और चुनावी वादा निभाते हुए बुधवार को विद्यार्थियों के लिए 'स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड' योजना को लांच किया। इस क्रेडिट कार्ड के जरिये विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन ले पाएंगे। 40 साल तक की आयु का कोई भी शख्स इसका लाभ उठा सकेगा। लोन की वापसी के लिए 15 साल तक का समय मिलेगा। (राब्यू)

हिमाचल में थप्पड़ प्रकरण में डैमेज कंट्रोल की तैयारी

शिमला : कुल्लू में वीआइपी सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के बीच थप्पड़ व लात प्रकरण को तूल देने की बजाय हिमाचल सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) रैंक के अधिकारी बृजेश सूद को जांच रिपोर्ट और घटना के दौरान बरते धैर्य के कारण क्लीन चिट दी जा सकती है। (जासं)

बनना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून : साध्वी ऋतंभरा

उज्जैन: उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए बुधवार को पहुंची साध्वी ऋतंभरा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। समान नागरिकता होना आवश्यक है। (नईदुनिया)

नकली दवा मामले में मेडिल्योड मेडिकामेंट का लाइसेंस रद

कटक : कटक में 70 लाख रुपये की नकली दवा बरामदगी के मामले में ओडिशा के राज्य ड्रग्स कंट्रोलर ने मेडिल्योड मेडिकामेंट प्राइवेट लिमिटेड के लाइसेंस को रद कर दिया है। (जासं)

तेंदुआ के हमले में केक ने बचा ली दो भाइयों की जान

नईदुनिया, इंदौर

- पंजा लगने से केक का बाक्स फटा तो ठिठक गया तेंदुआ, मौका पा बाइक की गति बढ़ाई तो बच गए प्राण
- मप्र के बुरहानपुर जिले में हुई अनूठी घटना, बाद में बच्चे की जन्मतिथि के साथ मनाया जान बचने का जश्न

साहस को जब किस्मत का साथ मिल जाता है तो चमत्कार हो जाता है। ऐसा ही वाकया मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में हुआ। इसे किस्मत का खेल ही कहा जाएगा कि तेंदुआ के हमले में केक के कारण दो भाइयों की जान बच गई। उसका ताकतभरा पंजा केक के बाक्स पर पड़ा, जिससे वह फट गया और केक खराब हो गया, लेकिन इसी कारण तेंदुआ ठिठक गया और दोनों भाई तेजी से बाइक दौड़ाकर तेंदुआ के चंगुल से दूर निकल गए। घटना रविवार शाम करीब छह बजे की है। जान बच जाने की खुशी में दोस्तों ने फिर नए केक का प्रबंध किया और खुशियां मनाईं।

बुरहानपुर जिले की नेपानगर तहसील के गांव गोराडिया निवासी फिरोज मंसूरी अपने बेटे शोएब की जन्मतिथि के लिए नेपानगर से केक लेकर बाइक से गांव लौट रहे थे। उनके साथ भाई साबिर मंसूरी भी थे। शाम करीब छह बजे पलासुर-सांईखेड़ा-डाभियाखेड़ा तिराहे पर गन्ने के खेत से अचानक छलांग मारकर तेंदुआ ने उन पर हमला बोल दिया। साबिर बताते हैं कि तेंदुआ दहाड़ मारता हुआ हमारी ओर लपका। उसने बाइक के पीछे पंजा मारा तो मैंने भी हाथ में पकड़ा हुआ केक का बाक्स उसके आगे कर दिया। पंजे के वार से बाक्स फट गया और केक तेंदुआ के पंजे में लग गया। इससे तेंदुआ पलभर के लिए ठिठक गया। तभी फिरोज भाई ने बाइक की गति बढ़ा दी तो तेंदुआ भी गति बढ़ाकर हमारे पीछे दौड़ा। हम चिल्ला रहे थे और वह दहाड़ रहा था। तभी मैंने दूसरे हाथ में रखी फलों और सब्जियों से भरी थैली उसके मुंह पर जोर से मार दी। थैली छूट गई, मगर वजनदार थैली मुंह पर पड़ते ही तेंदुआ रुक गया। बस यही क्षण था, जिसने हमें बचा लिया। हमने बाइक की गति और बढ़ा दी। हम लोग जैसे-तैसे घर पहुंचे और पूरा घटनाक्रम दोस्तों और पड़ोसियों को बताया। भतीजे की जन्मतिथि का केक खराब होने का मलाल था, लेकिन खुशी थी कि जान बच गई। दोस्तों ने कुछ ही देर में नए केक का प्रबंध कर दिया। भतीजे से केक कटवाया और जिंदगी बचने का जश्न जन्मतिथि की पार्टी के साथ मनाया। स्वजन भी पहले तो रोए, फिर हमारी जान बच जाने का जश्न मनाया।



नए केक के साथ भतीजे शोएब (बीच में बच्चे के साथ), चाचा साबिर मंसूरी और स्वजन।

पानी व भोजन की तलाश में रिहायशी इलाके में आते हैं वन्यजीव : नेपानगर क्षेत्र में घना वन होने के कारण यहां बाघ, तेंदुआ सहित अन्य वन्य प्राणियों की उपस्थिति रहती है। वन विभाग के नावरा क्षेत्र की रेंजर विमला कहती हैं कि क्षेत्र में मादा तेंदुए के साथ दो शावकों के घूमने की जानकारी सामने आ रही है।

बैंक में तीन रातों तक छिपी रही महिला, लूट के प्रयास में गिरफ्तार

- हथौड़ा, आरी व खाने-पीने का सामान लेकर घुसी थी मेघालय के ग्रामीण बैंक में
- सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाया और नकदी निकालने का प्रयास किया

शिलांग, आइएएनएस : मेघालय में एक विचित्र घटनाक्रम में पुलिस ने 40 वर्षीय महिला को बैंक लूट के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया है। वह तीन रातों तक बैंक के भीतर संदिग्ध अवस्था में छिपी थी।

एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि इसाबेला मायरबोह शिलांग स्थित मेघालय ग्रामीण बैंक की विष्णुपुर शाखा में छिपी हुई थी। सोमवार को जब बैंक खुला तो उसे एक प्रयोग में न आने वाले कमरे में छिपा हुआ पाया गया। वह गत शुक्रवार को कुछ रुपये जमा करने बैंक आई थी और किसी प्रकार छुपने में कामयाब रही। महिला अपने साथ खाना, साफ्ट ड्रिंक व ओआरएस आदि भी लाई थी, जिससे जाहिर होता है कि वह बैंक में रात में रुकने के इरादे से आई थी। उसके पास से हथौड़ी व आरी भी बरामद हुई है।

पुलिस व बैंक के कर्मचारियों का कहना है कि इसाबेला ने शायद सोचा होगा कि वह अगली सुबह बैंक से बाहर आ जाएगी। उसे शनिवार व रविवार की छुट्टी का अंदाजा नहीं रहा होगा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बैंक आवासीय क्षेत्र में है। महिला ने कोई शोर नहीं मचाया। उसने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाया और काउंटर से कुछ नकदी निकालने का भी प्रयास किया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला शहर में ही भोजनालय चलाती थी। कोविड महामारी की वजह से अन्य लोगों के साथ-साथ वह भी प्रभावित हुई। इसाबेला के स्वजन का कहना है कि उसकी हरकत के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस का कहना है कि इसाबेला को कुछ दिन क्वारंटाइन में रखने के बाद स्थानीय कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।

आटा-साटा कुप्रथा से परेशान होकर विवाहिता ने कुएं में कूद कर दी जान

जागरण संवाददाता, जयपुर

- राजस्थान के नागौर का मामला, पत्र लिख कुप्रथा बंद करने का किया आग्रह
- सुसाइड नोट में लिखा-कुप्रथा के नाम पर लड़कों के बदले बेची जाती हैं लड़कियां

राजस्थान में सदियों से चली आ रही कुप्रथा 'आटा-साटा' के कारण एक विवाहिता ने कुएं में कूद कर जान दे दी। राज्य में नागौर जिले के हेमपुरा गांव निवासी 21 वर्षीय विवाहिता ने आत्महत्या करने से पहले अपने परिजनों को एक पत्र लिखकर 'आटा-साटा' की कुप्रथा को बंद करने की पहल करने का आग्रह भी किया है। उसने लिखा 'आटा-साटा' की कुप्रथा ने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी मौत का कारण भी समाज में चल रही यह कुप्रथा ही है।

जानकारी के मुताबिक सुमन का विवाह पास के ही गांव में हुआ था। पति विदेश में रहता था। सुमन के पति की बहन का विवाह उसके भाई से किया गया था। इसी के बदले उसको ब्याह दिया गया था। पति अनपढ़ था, मगर कुप्रथा के चलते सुमन को अपनी मर्जी के खिलाफ उससे शादी करनी पड़ी थी। पति के विदेश में रहने के कारण ससुराल वालों ने उसे रखा नहीं और वह आठ माह से अपने पीहर (मायके) में रह रही थी। हालांकि, उसके चाचा नारूराम ने पुलिस में दर्ज करवाई रिपोर्ट में कहा है कि वह कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान थी, जिसके कारण वह घर के पास एक कुएं में गिर गई। अस्पताल ले जाने के बाद डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

यह लिखा सुसाइड नोट में : सुमन ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मरना गलत है, पर मैं मर रही हूं। मेरे मरने की वजह समाज है, जिसने 'आटा-साटा' नाम की कुप्रथा चला रखी है। इसमें लड़कियों को जिंदा मौत मिलती है। लड़कियों को लड़कों के बदले बेचा जाता है। 17 साल की लड़की का विवाह 70 साल के व्यक्ति के साथ कर दिया जाता है। लड़की पैदा होते ही तय कर देते हैं कि इसका किसके बदले विवाह करना है। पढ़ी-लिखी लड़कियों का विवाह अनपढ़ व उम्रदराज के साथ कर दिया जाता है। यह कुप्रथा बंद होनी चाहिए।

अफस्पा के तहत नगालैंड और छह माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूरे नगालैंड राज्य को और छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा) बढ़ा दिया गया है और यह कानून सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और किसी को भी बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है। इस कानून के तहत दिसंबर के अंत तक पूर्वोत्तर का यह पूरा राज्य अशांत क्षेत्र माना जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा है कि सरकार की राय है कि क्षेत्र जिसमें पूरा नगालैंड राज्य शामिल है, वह इस तरह की अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिसमें नागरिक शक्तियों की सहायता में सशस्त्र बलों का इस्तेमाल आवश्यक है। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से हत्याएं, लूट और फिरौती के मामले सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए वहां काम कर रहे सुरक्षा बलों की सुविधा के लिए यह कार्रवाई जरूरी हो गई थी।

फ्रास्ट इंटरनेशनल की 185 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 14 बैंकों के कंसोर्टियम से कथित तौर पर 3,592 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुंबई स्थित एक समूह की 185 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की है।

ईडी ने बुधवार को बताया कि फ्रास्ट इंटरनेशनल लिमिटेड व इस समूह की अन्य कंपनियों ग्लोबिज एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड, एनएसडी निर्माण प्राइवेट लिमिटेड, आरएस बिल्डर्स व अन्य कंपनियों तथा निदेशकों की संपत्तियों को प्रिवेंशन आफ मनी लॉड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जब्त करने का आदेश जारी हुआ था। केंद्रीय एजेंसी की तरफ से कानपुर, दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, कोलकाता व तमिलनाडु के कुछ शहरों में जब्त की गई संपत्तियों की कीमत करीब 185 करोड़ रुपये आंकी गई है। ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की तरफ से पिछले साल जनवरी में आरोपितों के खिलाफ दर्ज मुकदमे के आधार पर कार्रवाई शुरू की थी।

सृजन घोटाले में जब्त की चार करोड़ से अधिक की संपत्ति

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार में हुए सृजन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 .10 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली। इस संपत्ति के मालिक सृजन महिला विकास सहयोग समिति की सचिव मनोरमा देवी, उनके रिश्तेदार और कुछ सरकारी अफसर-कर्मी हैं। ईडी ने 3 .09 करोड़ रुपये मूल्य के 12 फ्लैट, 87 लाख रुपये मूल्य के पांच प्लाट, कुछ मकान, 11 लाख से अधिक मूल्य की स्कार्पियो कार और 1.20 लाख जमा वाले बैंक खाते को जब्त किया है। कार्रवाई भागलपुर, पटना, सीतामढ़ी व देवघर के साथ देश के अन्य हिस्सों में की गई। जो संपत्ति जब्त की, उसमें मुख्य आरोपी मनोरमा देवी के रिश्तेदारों के अलावा आरोपित अफसरों-कर्मियों के नाम फ्लैट, प्लाट व घर शामिल हैं।

ज्ञानवापी मामले में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दायर की याचिका

जागरण संवाददाता, वाराणसी : ज्ञानवापी मामले में सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) आशुतोष तिवारी के पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के आदेश के खिलाफ बुधवार को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से जिला जज ओमप्रकाश त्रिपाठी की अदालत में निगरानी याचिका दायर की गई है। जिला जज ने इस याचिका की ग्राह्यता पर सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तिथि तय की है।

गौरतलब है कि 1991 में प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरनाथ तथा अन्य पक्षकारों ने ज्ञानवापी में मंदिर निर्माण व हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने को लेकर मुकदमा दायर किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ने पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की अदालत से अपील की थी। इस साल आठ अप्रैल को वाद मित्र की अपील मंजूर हो गई। इस आदेश के खिलाफ उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से जिला जज की अदालत में निगरानी याचिका दायर की है।

दैनिक जागरण
जनहित सबसे ऊंचा उद्देश्य है

चुनाव बाद हिंसा की जांच

कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच करने गई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने अपनी रपट उसे सौंप दी। अभी यह स्पष्ट नहीं कि यह टीम किस नतीजे पर पहुंची है, लेकिन उसके साथ जिस तरह हाथापाई करने की कोशिश की गई, उससे यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि यह रपट क्या कह रही होगी? इसकी एक झलक इस टीम के एक सदस्य के उन बयानों से मिलती है जिसके तहत उन्होंने जले हुए घरों और बेघर भाजपा कार्यकर्ताओं का उल्लेख किया। इसके अलावा सिविल सोसायटी की एक तथ्य खोजी समिति की ओर से तैयार की गई रपट भी बहुत कुछ कह रही है। इस समिति के अनुसार चुनाव बाद सुनियोजित तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से हिंसा की गई। अकेले 16 जिलों में 15 हजार से अधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया। इस दौरान कई लोगों की हत्या की गई और तमाम महिलाओं से दुष्कर्म किया गया। इसका मतलब है कि राजनीतिक द्वेष और कलुष से भरी हुई तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को जंगलराज में तब्दील कर दिया। निःसंदेह ऐसा इसीलिए संभव हो सका, क्योंकि पुलिस के साथ-साथ ममता सरकार भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। यह बेहद शर्मनाक और अकल्पनीय है कि एक महिला मुख्यमंत्री अपने समर्थकों की ओर से राजनीतिक विरोधियों की महिलाओं से किए जाने वाले दुष्कर्म की घटनाओं से भी अविचलित बनी रहे।

चुनाव बाद हिंसा की भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं तृणमूल कांग्रेस ही नहीं, बंगाल को भी शर्मसार करने वाली हैं। यदि ऐसी भीषण हिंसा किसी अन्य राज्य और खासकर भाजपा शासित राज्य में हुई होती तो उसे राष्ट्रपति शासन लगाने का उपयुक्त मामला बताया जा रहा होता, लेकिन यह देखना दयनीय है कि तथाकथित बुद्धिजीवी और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा मौन धारण किए हुए है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच रपट का अध्ययन करने के बाद ऐसी कार्रवाई करे, जो एक नजीर साबित हो और बंगाल को राजनीतिक हिंसा के उस दुष्चक्र से निकालने में मददगार बने, जिसमें वह बुरी तरह फंस गया है और राष्ट्र के लिए चिंता का कारण है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि संकीर्ण हितों को पूरा करने के फेर में ममता बनर्जी ने राज्य के राजनीतिक माहौल में जानबूझकर जहर घोल दिया है। यह संभव ही नहीं कि किसी दल के कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के उकसावे के बिना विरोधी दल के प्रति इस हद तक नफरत से भर जाएं कि उसके नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कुचल देने पर आमादा हो जाएं।

पहाड़ों की सैर

हर कोई प्रकृति को निहारना चाहता है। व्यस्त जिंदगी में कुछ समय निकाल कर कई लोग सुकून के कुछ पल बिताने के लिए हिमाचल प्रदेश की सैर के लिए आते हैं। वैश्विक महामारी ने लोगों को काफी समय तक घरों में कैद कर रखा था। सब कुछ बंद था। चाहकर भी लोग पहाड़ों की सैर नहीं कर पा रहे थे। अब कुछ राहत मिली है। स्थानीय व अन्य राज्यों के लोगों ने पहाड़ों का रुख किया है। दो सप्ताह में राज्य में ढाई लाख से अधिक वाहन आए हैं। पहली जुलाई से अन्य राज्यों के लिए भी बस सेवा शुरू हो जाएगी। इसके बाद अन्य राज्यों से आने वालों की संख्या में और वृद्धि होगी। लोगों को पहाड़ों की सैर के दौरान अधिक सावधानी बरतनी होगी। जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रैकिंग इत्यादि के लिए जाते हैं वे ऐसे क्षेत्रों में कतई न जाएं जिनके बारे में जानकारी न हो। रात्रि ठहराव भी सुरक्षित स्थानों पर ही करना चाहिए। मंडी जिला में ऐसा ही हादसा सामने आया है। चार युवक ट्रैकिंग के लिए गए थे।

सुरक्षित रहने के लिए जरूरी है कि पहाड़ की सैर के लिए निकलते समय खतरे को न्योता न दें

रात को दो युवक शौच के लिए गए, इस दौरान एक युवक खाई में गिर गया, इसे बचाते दूसरा भी गिर गया। साथ गए युवकों ने निकटवर्ती गांव के लोगों की मदद से उन्हें खाई से निकाल कर अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उधर कांगड़ा के नगरोटा बगवां में भी अन्य राज्य का युवक रात को कूहल में गिर गया। स्वजन उसे ढूंढते रहे, लेकिन कोई पता नहीं चला। रविवार को कूहल में उसका शव बरामद हुआ। हिमानी चामुंडा गए श्रद्धालु और लेह से मनाली आ रहे मध्य प्रदेश के व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। अधिक गर्मी पड़ने पर अन्य राज्यों से आने वाले लोग नदियों में उतर जाते हैं। ऐसा कर भी अपनी जान को जोखिम में डाल लेते हैं। बरसात का मौसम शुरू हो गया है। पहाड़ों पर बारिश होने से अचानक नदियों में जलस्तर बढ़ जाता है। सभी को चाहिए कि अपनी जिंदगी को जोखिम में न डालें। सुकून के पल बिताने निकले हैं तो हर समय नियमों का पालन करें और सावधान रहें।

चीन के खिलाफ मजबूत कड़ी बनता भारत

हर्ष वी पंत



जब वैश्विक शक्तियां चीन की चुनौती के खिलाफ एकजुट हो रही हैं तब उन्हें भारत के रूप में एक मजबूत और भरोसेमंद मित्र दिख रहा है

चीन के दिनोंदिन उभार के कारण वैश्विक ढांचे में उथल-पुथल जारी है। जब भी बड़ी शक्तियों का उदय या अस्त होता है तब ऐसी हलचल स्वाभाविक है, लेकिन मौजूदा मामले में दिलचस्प यह है कि उसमें आमसहमति एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर केंद्रित हो रही है। पिछले वर्ष की शुरुआत तक पश्चिमी देशों में नीति नियंता आश्वस्त थे कि बीजिंग के साथ कड़ियां जोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन को लेकर कड़े रुख का वे उपहास उड़ाया करते थे। अब ट्रंप की वे कोशिशें आखिर कामयाब होती दिख रही हैं, जिसमें वह कोविड-19 के लिए चीन पर निशाना साधते थे। शायद वह पड़ाव आ गया है, जब दुनिया यह महसूस कर रही है कि महामारी के लिए चीन से जवाब तलब किया जाए। यकायक सर्वसम्मति की दिशा बदल गई। जानकार अब चीन-अमेरिका के बीच संघर्ष के आसार तक देखने लगे हैं। अतीत में संवाद की बात करने वालों के आकलन बदल रहे हैं। कुछ जानकार मान रहे थे कि बाइडन प्रशासन चीन को लेकर संभवतः ट्रंप पूर्व दौर के स्तर पर जाएगा, लेकिन अमेरिका-चीन संबंधों के मामले में इसका उलटा ही दिख रहा है। चाहे जी-7 समूह हो या नाटो का मंच, सभी के निशाने पर अभी चीन है। दो साल पहले तक ऐसी स्थिति की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। आखिर पश्चिम की नींद टूट ही गई। अमेरिका और यूरोप, दोनों को दशकों तक चीन की अनदेखी करने की कीमत महसूस होने लगी है। पश्चिमी देशों में अब चीन को लेकर पुरानी नीतियों पर गंभीरता से पुनर्विचार किया जा रहा है। चीन के मसले पर समान विचारधारा वाले देशों में तत्परता की भावना भी बलवती हुई है। इसी कड़ी में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन के लिहाज से भारत वैश्विक आकर्षण की धुरी के रूप में उभरा है।

जहां दुनिया भर के नीति-नियंता भारत को साधने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, वहीं वैश्विक मीडिया के एक वर्ग में बड़ी अजीबोगरीब दलील दी जा रही है, जिसमें नए वैश्विक संतुलन की खोज में भारत को कथित कमजोर कड़ी बताया जा रहा है। यह धारणा कोविड की दूसरी लहर से निपटने में भारत की नाकामी पर आधारित है, जिसने भारतीय राज्य की अक्षमताओं को उजागर किया। यह दलील एक ऐसे दौर में प्रचारित की जा रही है, जब भारत वास्तव में उन सबसे मुखर आवाजों में से एक के रूप में उभरा है, जो चीन से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर जिम्मेदारी से पेश आने की मांग कर रही हैं। यह अचानक ही घटित नहीं हुआ है, बल्कि कई वर्षों से उसकी पूर्वपीठिका तैयार हुई है। चीनी आक्रामकता



अवधेश राजपूत

के खिलाफ नीतिगत सर्वसम्मति में नई दिल्ली की भूमिका को अनदेखा करने वालों का रुख भारत की क्षमताओं की जानकारी से कम इस बात को अधिक इंगित करता है कि या तो उन्हें भारत की चीन नीति के बारे में नहीं मालूम या फिर वे हालिया वैश्विक रुझानों से अनभिज्ञ हैं। कोविड की दूसरी लहर से निपटने में भारत की मुश्किलों में कुछ भी नया नहीं है। जब भी भारत के उदय की बात आती है तो उसमें देश की क्षमताओं का अभाव हमेशा से एक अवरोध रहा है, लेकिन बीते कुछ महीनों से चीजें बहुत बदली हैं। भारत ने दिखाया है कि आपदाओं से निपटने में उसकी क्षमताएं बेहतर हो रही हैं। उसने कोविड की पहली लहर का कई विकसित देशों के मुकाबले कहीं बेहतर तरीके से सामना किया। फिर दूसरी लहर को भी काफी कम समय में काबू कर लिया। वास्तव में भारत का प्रदर्शन तो उन चुनौतियों के बीच होना चाहिए, जिसका सामना बेहतर स्वास्थ्य ढांचे वाले देश अभी भी कर रहे हैं।

जबसे दूसरी लहर ने भारत में दस्तक दी तबसे वैश्विक और भारतीय बुद्धिजीवियों के एक वर्ग ने कहना शुरू कर दिया कि अब तो भारत की कहानी खत्म। इस विमर्श में इस पहलू को अनदेखा किया गया कि पिछले डेढ़ साल से भारत जहां एक ओर महामारी से निपट रहा है वहीं दूसरी ओर उसने सीमा पर चीनी आक्रामकता को जवाब दिया। जब महामारी से निपटने को लेकर अमेरिका जैसे दिग्गज देश अपने देश से बाहर नहीं देख पा रहे थे तब भारत उससे जुड़े वैश्विक विमर्श के केंद्र में था। साथ ही साथ अपनी सीमा पर चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देने में भी लगा था।

चीन के खिलाफ भारत का कड़ा रुख पिछले कुछ अर्से से भारतीय सामरिक भाव-भंगिमा का अहम भाग रहा है। यहां तक कि जब पश्चिम बीजिंग से गलबहियां करने में लगा था, उस दौरान भी नई दिल्ली कई मोर्चों पर चीन को चुनौती देने में जुटी थी। भारत ही दुनिया का पहला बड़ा देश था जिसने शी चिनफिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना को हिंसक एवं आक्रामक परियोजना करार देकर उसका विरोध किया था। भारत की आलोचना आज इस परियोजना को लेकर वैश्विक सहमति का हिस्सा बन गई है। इसी तरह चीन के कड़े विरोध के बावजूद अगर हिंद-प्रशांत को व्यापक स्वीकृति मिली तो यह भारत के उत्साही प्रयासों के बिना संभव नहीं थी। यदि नई दिल्ली ने विदेश नीति विकल्पों को लेकर सोच स्पष्ट न की होती तो क्वाड की संकल्पना सिरे नहीं चढ़ पाती।

स्पष्ट है कि भारत ने कई मोर्चों पर चीन को कड़ी चुनौती दी और महामारी का वैश्विक समाधान निकालने में दुनिया को दिशा भी दिखाई। निःसंदेह इसमें भारत के राष्ट्रीय हितों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, परंतु उसने वैश्विक समुदाय को प्रेरित भी किया। जब विश्व की बड़ी शक्तियां चीन की चुनौती के खिलाफ एकजुट हो रही हैं तब उन्हें भारत के रूप में एक मजबूत और भरोसेमंद मित्र दिख रहा है। वैश्विक मीडिया के कुछ तबकों को भले ही यह असहज लगे, लेकिन विश्व की जो बड़ी शक्तियां, जिनका पहले से ही भारत की ओर झुकाव है, वे अवश्य उसे एक सम्मोहक साझेदार के रूप में देखती हैं।

अपनी तमाम घरेलू चुनौतियों के बावजूद भारत चीन के खिलाफ खड़ा होकर एक वैश्विक लीडर के रूप में अपनी अपेक्षित भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। यही इस दौर की हकीकत है। वैश्विक सामरिक समीकरणों को वह पहले से ही चुनौती दे रहा है। उभरते वैश्विक शक्ति संतुलन में इसका गहरा प्रभाव होगा। इस आकलन में भारत एक मजबूत कड़ी है, जो लगातार और मजबूत होती जाएगी।

(लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं)

response@jagran.com

नजीर न माना जाने वाला फैसला



अजय खेमरिया

सवाल जमानत देने पर नहीं, बल्कि जमानत आदेश के साथ दिए गए 133 पेज के दृष्टांत पर है

दिल्ली दंगों में आरोपित तीन छात्रों की जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय के जमानत आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने एक बार फिर हमारी न्यायिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते साल फरवरी में हुए दिल्ली दंगों के आरोप में जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा, जेएनयू की छात्राएं नताशा और देवांगना तिहाड़ जेल में बंद थीं। तीनों पर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए एवं अन्य धाराओं में मामले दर्ज थे। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों इन तीनों को जमानत दे दी। सवाल जमानत देने पर नहीं, बल्कि जमानत आदेश के साथ दिए गए 133 पेज के दृष्टांत पर है। यह न केवल उच्च न्यायालय की अधिकारिता से बाहर है, बल्कि अनपेक्षित भी। शीर्ष अदालत ने इस आदेश पर रोक नही लगाई, लेकिन उसे नजीर मानने पर प्रतिबंध लगाकर इस बहस को जन्म दे दिया कि क्या हाई कोर्ट मनचाहे निर्णय देने के लिए स्वतंत्र है?

जब देश का सर्वोच्च न्यायालय ही यह मानकर चल रहा है कि इस निर्णय की तार्किक समीक्षा की जाएगी, तब सवाल यह उठता है कि क्या हाई कोर्ट के निर्णयों की समीक्षा ट्रायल कोर्ट की भांति नहीं होनी चाहिए? एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या देश में सत्ता से असहमति और देश के विरुद्ध नियोजित षड्यंत्र में कोई अंतर परिभाषित नही होना चाहिए? असहमति के नाम पर मौलिक अधिकार क्या किसी प्रायोजित षड्यंत्र को आकार देने की अनुमति दे सकते हैं? दिल्ली उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने 133 पेज का जो निर्णय दिया, वह न्यायपालिका की प्रामाणिकता को कठघरे में खड़ा करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अचंभा भरा, लंबा और परिधि से परे निरुपित किया। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि देश के बौद्धिक जगत और खासकर अंग्रेजी मीडिया में तीनों छात्रों की जमानत का यह आदेश तो चर्चा का केंद्रीय विषय बना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को विमर्श में कोई जगह नहीं मिली। हाई कोर्ट के जमानत आदेश का सहारा लेकर ऐसा प्रचारित किया गया कि मोदी सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को देशद्रोही गतिविधियों के साथ घालमेल कर रही है।

दिल्ली के कड़कड़डूमा ट्रायल कोर्ट ने नताशा, देवांगना और आसिफ इकबाल की जमानत खारिज



दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को जांचेगा सुप्रीम कोर्ट। फाइल

की थी। स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश ने चार्जशीट के आधार पर जो कुछ लिखा, उसे प्रकाश में लाना जरूरी है। उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया था कि विघटनकारी चक्का जाम एक पूर्व-निर्धारित साजिश थी, जिसके परिणामस्वरूप दंगों में लोगों की मौत हुई, सैकड़ों घायल हुए और संपत्ति नष्ट हुई। इसके अलावा अदालत ने माना कि दिल्ली में हुई हिंसा की शुरुआत सबसे पहले पुलिसकर्मियों पर हमला करने से हुई। न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की कि नागरिकता संशोधन कानून की आड़ में मुखर आंदोलन का उद्देश्य भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करना था।

चार्जशीट के अनुसार आसिफ इकबाल तन्हा ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम खरीदा, फिर उसका इस्तेमाल चक्का जाम, दंगे की योजना आदि में किया। इसी नंबर से वाट्सएप ग्रुप बनाए। बाद में यह सिम जामिया की छात्रा सफूरा जरगर को दे दिया। नताशा, देवांगना इस गिरोह के मास्टरमाइंड उमर खालिद, शर्जील इमाम के साथ शाहीन बाग के प्रदर्शन में सक्रिय रहीं। चार्जशीट में वाट्सएप ग्रुप्स की चैट्स भी प्रस्तुत हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे के समय जानबूझकर भारत सरकार को दुनियाभर में बदनाम करने की योजना की तस्दीक करतीं हैं। इन तथ्यों को दरकिनार कर दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देते समय असहमति और आतंकी गतिविधियों की परिभाषा को एक कर दिया। यानी एक तरफ असहमति और आतंकी गतिविधियों पर 133 पेज का दृष्टांत जारी किया जाता है और दूसरी तरफ असहमति के नाम पर दंगों की साजिश, भारत के विरुद्ध युद्ध को उचित मान लिया गया।

आखिर यह कैसी अभिव्यक्ति और असहमति की स्थापना दिल्ली उच्च न्यायालय करना चाहता है, जो हिंसा और दंगे की इजाजत देता है? यूएपीए कानून पर जिस तरह अनावश्यक निर्णय सुनाने का काम किया गया, वह अपने आप में एक खतरनाक घटनाक्रम है। जमानत देना एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यही प्रचलित है कि जमानत देते समय प्रकरण की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती। तीनों छात्रों को जमानत दी जाती तो किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन जिस तरह ट्रायल कोर्ट के विश्लेषण को खारिज किया गया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कोई अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट के ऐसे निर्णय के बाद ट्रायल को तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर अंतिम निर्णय तक ले जा सकेगा? तब जबकि ट्रायल कोर्ट उच्च न्यायालय के अधीन रहते हुए काम करते हैं? एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब ट्रायल कोर्ट के अपीलीय मामलों में हाई कोर्ट कड़ी निगरानी और समीक्षा कर सबंधित जजों के विरुद्ध कारवाई करता है, तब इस मामले में भी क्या सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के आदेश की समीक्षा कर पाएगा? सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह बेहतर अवसर है। वह उच्च न्यायालयों की कार्यविधि को संवैधानिक जबाबदेही की सीमा में बांध सकता है। अभी हाई कोर्ट में जजों की जबाबदेही का कोई प्रविधान नहीं है, जबकि निचली अदालतें इन्हीं हाई कोर्ट के अधीन हैं। अगर हाई कोर्ट के जज गलत या अनधिकृत निर्णयन के दोषी होते हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट केवल चेतावनी देने या ट्रांसफर से आगे कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उन्हें हटाने के लिए केवल महाभियोग का प्रविधान है, जो आज तक किसी जज के विरुद्ध अमल में नहीं लाया जा सका। दूसरी तरफ निचली अदालतों से प्रतिवर्ष दो दर्जन से अधिक जज निर्णयों की समीक्षा के नाम पर हाई कोर्ट द्वारा घर बिठा दिए जाते हैं।

(लेखक नीति विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सफलता के सूत्र

सफलता प्राप्त करना मानव जीवन का एक सर्वमान्य लक्ष्य है। जीवन चुनौतियों और अवसरों से भरा है, लेकिन केवल उन्हीं लोगों के लिए जो वास्तव में अवसरों को प्राप्त करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए संघर्ष करते हैं। कड़ी मेहनत और समर्पण सफलता की यात्रा का एकमात्र मंत्र हैं। कड़ी मेहनत के बिना कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सफल होने के लिए कुछ आधारभूत गुणों को विकसित करने और उन्हें निरंतर निखारने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले, आपको अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को जानना चाहिए। एक लक्ष्य निर्धारित कर उस दिशा में प्रयत्न करना होता है। नियमित रूप से लगातार परिश्रम करना पड़ता है। हमारा मन भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, उन पर ध्यान न देते हुए पूरी एकाग्रता से किया हुआ परिश्रम ही हमें अपेक्षित सफलता दिला सकता है।

जब तक आप सफल न हो जाएं, तब तक प्रयास करते रहना चाहिए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी गति धीमी है। अगर आप प्रयासरत हैं तो जीत संभव है। इतिहास साक्षी है कि मनुष्य ने कठोर परिश्रम द्वारा असंभव को भी संभव कर दिखाया है। किसी भी सफलता का आरंभ प्रयास करने से ही होता है। इसी संदर्भ में एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा कि अगर भाग्य पहले ही लिखा जा चुका है तो प्रयास करने से क्या मिलेगा? इस पर चाणक्य ने जवाब दिया कि क्या पता किस्मत में जो लिखा हो, वह प्रयास करने से ही मिले। सफलता के सूत्रों में स्वामी विवेकानंद का एक कथन भी मील का पत्थर माना जाता है। उन्होंने कहा था कि जीवन में सफलता चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के भीतर सबसे पहला गुण आत्मविश्वास का होना चाहिए। विवेकानंद का कहना था कि जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता, वह बलवान होकर भी दुर्बल ही बना रहता है। वहीं आत्मविश्वास से ओतप्रोत व्यक्ति सफलता प्राप्त कर ही लेता है।

नृपेंद्र अभिषेक नृप

धरती के भगवान को नमन

योगेश कुमार गोयल

राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस

कोरोना का यह क्रूर काल हमें चिकित्सकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का और बड़ा आधार प्रदान करता है

चिकित्सकों को उनके कार्य के लिए 'दूसरा भगवान' भी कहा जाता है। उनके समर्पण एवं प्रतिबद्धता का आभार व्यक्त करने के लिए ही देश में प्रति वर्ष एक जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का आयोजन किया जाता है। चिकित्सक दिवस मनाने का मूल उद्देश्य चिकित्सकों की बहुमूल्य सेवा, भूमिका और महत्व के संबंध में आमजन को जागरूक करना, चिकित्सकों के सम्मान करने के साथ ही चिकित्सकों को भी उनके पेशे के प्रति जागरूक करना है। देश में चिकित्सक दिवस की परंपरा वर्ष 1991 में आरंभ हुई थी। बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और जाने-माने चिकित्सक डॉ. बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में इसका आयोजन आरंभ हुआ। डॉ. रॉय जाने-माने चिकित्सक, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वर्ष 1948 से लेकर 1962 तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे।

वास्तव में कोरोना का यह क्रूर काल हमें चिकित्सकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का और भी बड़ा आधार प्रदान करता है। पूरी दुनिया डेढ़ साल से भी ज्यादा समय से कोरोना महामारी से जूझ रही है। इस दौरान विश्व की 18 करोड़ से भी ज्यादा आबादी कोरोना संक्रमित हो चुकी है। करीब 40 लाख लोग जान गंवा चुके हैं। भारत में अब तक कोरोना संक्रमण के तीन करोड़ से भी ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से करीब चार लाख की मौत हो चुकी है। तस्वीर का दूसरा पहलू देखें तो देश में कोरोना संक्रमितों की इतनी बड़ी संख्या में से 2.93 करोड़ से भी ज्यादा को ठीक करने में बड़ी सफलता मिली है और इस सफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वे हैं हमारे चिकित्सक। जिस प्रकार दुनिया भर में आज चिकित्सक अपनी जान की परवाह किए बिना करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे में वे वाकई सम्मान के सबसे बड़े हकदार हैं। आंकड़ों के अनुसार कोरोना ड्यूटी के दौरान देश में 700 से भी ज्यादा चिकित्सकों की मौत हो चुकी है।

ऐसे सेवाभाव के बावजूद देश के तमाम इलाकों से इन कोरोना योद्धाओं के साथ दुर्व्यवहार और हमले की खबरें भी आती रही हैं। यह सर्वथा निंदनीय हैं। इसी वजह से पिछले दिनों इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सहित कुछ संगठनों के आह्वान पर कोरोना काल में चिकित्सकों पर हुए हमलों के विरोध में रोष व्यक्त करते हुए सरकार से मांग की गई कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। महामारी के इस बुरे दौर में चिकित्सकों का मनोबल बनाए रखने हेतु यह समय की मांग भी है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान तो बहुत से चिकित्सकों को अपनी छुट्टियां रद कर प्रतिदिन लंबे-लंबे समय तक कार्य करना पड़ा है। ऐसे बहुत से चिकित्साकर्मी महीनों-महीनों तक अपने परिवार और छोटे बच्चों से भी दूर रहे हैं। उन्हें चिकित्सक दिवस पर नमन करना तो बनता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

मूल सिद्धांतों से न हों विमुख

'अफगानिस्तान में नाकाम होता अमेरिका' शीर्षक से लिखे आलेख में विवेक काटजू कहते हैं कि कूटनीति में न तो कोई स्थायी शत्रु होता है और न मित्र। इसी सिद्धांत के आधार पर वह कहते हैं कि भारत को भी अफगानिस्तान में फिर से ताकतवर हो रहे तालिबान के साथ वार्ता की पींगें बढ़ानी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि कूटनीति क्या, जीवन के तमाम क्षेत्रों में व्यावहारिकता का तकाजा कई बार सिद्धांतों से विचलन की मांग करता है, लेकिन कुछ सिद्धांत मूलभूत होते हैं। क्या व्यावहारिकता के लिए उनकी तिलांजलि भी दे दी जानी चाहिए? आखिर दुनिया में आतंकवाद के सबसे बड़े भुक्तभोगी देश के रूप में भारत को क्या तालिबान जैसे अमानवीय, क्रूर और हिंसक विचार के पैरोकार तबके से कोई बात करनी चाहिए? इसके बजाय बेहतर यही होगा कि भारत तालिबान विरोधी गुटों को और सशक्त बनाकर अफगानिस्तान में स्थायी शांति एवं स्थायित्व के लिए जमीन मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाए। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को भी यही रणनीति अपनानी चाहिए।

गुंजन शर्मा, नई दिल्ली

तकनीकी संस्थान हो सकते हैं सहायक

संपादकीय पेज पर आसमानी आतंक नामक टिप्पणी पढ़ी। आतंकवाद निरंतर अपने चेहरे बदल रहा है। इस बार उसका नया हथियार ड्रोन है। आतंक का यह रूप बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे निपटने के लिए अभी हमारे सुरक्षाबलों के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। एक ओर जहां ड्रोन का उपयोग दवाई, खाने की होम डिलीवरी, फसलों की देखभाल और विवाह समारोह को रिकार्ड करने में किया जाता है, वहीं इन आतंकियों ने अब इस नई तकनीक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। हमारे देश में नेशनल एंटी ड्रोन नियम तो हैं, मगर उनका कड़ाई से पालन करना जरूरी है। आइआइटी जैसे संस्थान तकनीक की सहायता से सुरक्षाबलों की मदद कर सकते हैं ताकि समय रहते हमलावर ड्रोन को पकड़ा जा सके। सरकार को ऐसी छोटी कंपनियों को भी बढ़ावा देने की जरूरत है, जो इस दिशा में आगे बढ़कर काम करने को तैयार हैं।

बाल गोविंद, नोएडा

बेरोजगारी की मार

भारत में आत्महत्या करना या आत्महत्या करने की कोशिश करना भी जुर्म माना जाता है। वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों की मानें तो दिन-प्रतिदिन आत्महत्या करने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आखिर आत्महत्या में लगातार वृद्धि क्यों हो रही है। पिछले डेढ़ साल में संक्रमण के कारण लोगों की नौकरियां छिन गईं, तनख्वाहें कम हो गईं। दबाव के चलते लोग आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हैं। आज बेरोजगारी दर नौ से दस फीसद के करीब जा पहुंची है। वहीं दिहाड़ी मजदूर के आंकड़े 23.4 फीसद पर जा पहुंचा है। ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुल आत्महत्या में 10.1 फीसद आत्महत्या बेरोजगारी की वजह से हो रही है। इस आत्महत्या में 15.4 फीसद गृहिणी भी शामिल हैं। आने वाले समय में आत्महत्या का खराब चलन भयानक रूप धारण कर सकता है। ऐसे में इससे उबरने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। बेरोजगारी दर कम करने के लिए सरकार को अर्थव्यवस्था मजबूत करनी होगी। जनता को जागरूक करते हुए उन्हें सीधे मदद करने का कोई उचित प्रबंध करना चाहिए। राज्यों को भी गांवों में छोटे-छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा देने पर विचार करने की जरूरत है।

रितिक सविता, दिल्ली विश्वविद्यालय

यमुना पर गंभीरता से हो काम

दिल्ली में यमुना की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। सैकड़ों छोटे-बड़े नाले इस नदी में जाकर गिरते हैं। सवाल यह है कि इतने खर्च के बाद भी इस पर रोक नहीं लगाई जा सकी। यमुना में अमोनिया की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। इससे आस-पास का भू-जल भी प्रदूषित होता जा रहा है। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए जरूरी है कि शहर की नदियों को भी साफ रखा जाए। दिल्ली सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

अमन माहेश्वरी, दिल्ली विश्वविद्यालय

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) - विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

1928 में स्कॉटिश चिकित्सक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। इससे संक्रामक रोगों से लड़ने में काफी मदद मिली।

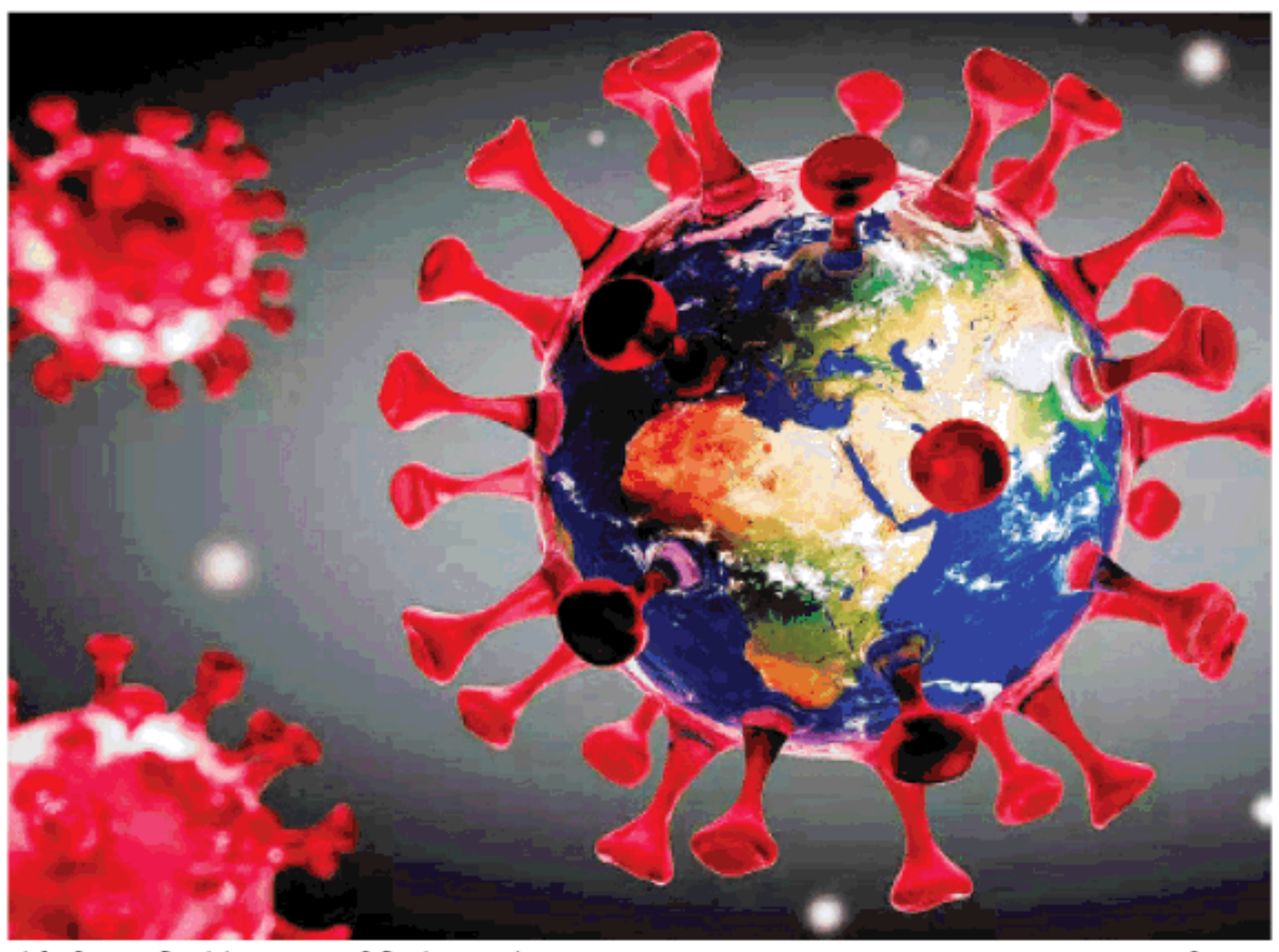
आजकल

कैसे टूटेगा संक्रमण का यह सिलसिला

डेढ़ साल पहले दुनिया में जब कोरोना वायरस का प्रसार शुरू हुआ था तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोरोना के नए और खतरनाक वैरिएंट सामने आएंगे, पर इसके संक्रमण की रफ्तार, संहारक क्षमता और रूप बदलने की प्रवृत्ति ने दुनिया और मेडिकल साइंस की अब तक की तरक्की को सकते में डाल दिया है। अब वक्त आ गया है, जब पूरी दुनिया को ठहरकर सोचना चाहिए कि वह आखिर ऐसा क्या करे, जिससे कोरोना जैसी महामारियां दोबारा लौटकर न आ पाएं



डॉ. संजय वर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर, बेनेट यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा


कोई नहीं जानता कि कोरोना वायरस अभी कितने रूप बदलेगा। प्रतीकात्मक

मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों हुआ इलाज-यह एक चर्चित कहावत है। इधर कोरोना वायरस से पैदा महामारी कोविड-19 के संदर्भ में कुछ ज्यादा ही सटीक बैठ रही है। पूरी दुनिया में एक ओर इसके टीकाकरण के अभियान रफ्तार पकड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ कोरोना के नए से नए स्वरूप (वैरिएंट्स) आम लोगों, विज्ञानियों, चिकित्सकों और सरकारों तक को चिंता में डाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि इलाज और टीकाकरण के प्रयासों के बीच कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा है। वायरसों के संदर्भ में इसे म्यूटेशन (उत्परिवर्तन) कहते हैं। खतरा सिर्फ नए वैरिएंट सामने आने का नहीं है, बल्कि यह है कि अपने भाई-बंदों के मुकाबले ये नए रूप ज्यादा खतरनाक साबित न हों। इसलिए आशंकाओं का दौर जोरों पर है। तीसरी लहर का संकट आसन्न माना जा रहा है। हमारे ही देश में कहा जा रहा है कि कोरोना का नया रूप 'डेल्टा प्लस' तीसरी लहर का कारण बन सकता है। दावों के मुताबिक भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह कोरोना वायरस का डेल्टा वैरिएंट (म्यूटेशन से पैदा हुआ नए किस्म का कोरोना वायरस) था। अब आठ से दस राज्यों में अपनी पहुंच बना चुका इसका नया संस्करण डेल्टा प्लस नई चिंताओं के केंद्र में है। कोई नहीं जानता कि ग्रीक वर्णमाला के आधार पर किए जा रहे कोरोना वायरस के नए रूपों के नामकरणों की यह सूची अभी कहां तक जाएगी। फिलहाल बात डेल्टा और लेम्डा तक पहुंच चुकी है। डेढ़ साल पहले दुनिया में जब कोरोना वायरस का प्रसार शुरू हुआ था तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोरोना के नए और खतरनाक वैरिएंट सामने आएंगे, पर इस संक्रमण की रफ्तार, संहारक क्षमता और रूप बदलने की प्रवृत्ति ने दुनिया और मेडिकल साइंस की अब तक तरक्की को सकते में डाल दिया है।

संक्रमणों के पिछले तीन दशकों के इतिहास पर नजर डालें तो पता चल रहा है कि दुनिया में एक वायरस का खौफ थमता है और दूसरा कोई अन्य संक्रामक रोग कई गुना ज्यादा ताकत के साथ आ धमकता है। इस तरह दो सवाल पैदा होते हैं। एक, नए वायरस क्यों पैदा हो रहे हैं और क्या हमारे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास नए संक्रमणों को रोकने का कोई तरीका है? दो, वायरसों का म्यूटेशन क्यों होता है और उसे कैसे रोका जाए? करीब सौ साल पहले दुनिया में पेनिसिलिन के आविष्कार के साथ यह माना जाने लगा था कि मानव सभ्यता को अब संक्रामक रोगों से निजात पाने में कोई मुश्किल नहीं होगी, बल्कि यह राय बनी कि रोगाणुओं (विषाणुओं-जीवाणुओं) को अब अपनी मांद में चले जाना होगा, क्योंकि इंसान को इलाज की एक ऐसी मुकम्मल विधि मिल गई है, जिसमें रोग पनप ही नहीं सकते। स्कॉटिश चिकित्सक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन का आविष्कार करके संक्रामक रोगों से लड़ने और उन पर काबू पाने का जो रास्ता सुझाया था, वह चेचक, पोलियो, फ्लू सरीखे कई संक्रामक रोगों के टीके और दवाएं विकसित करने का जरिया बना। इस उपलब्धि के बावजूद समय के साथ साबित हुआ है कि मनुष्य ने संक्रमणों के खिलाफ जितने हथियार बनाए, वायरसों के नए रूपों ने सारे उपायों को बौना साबित कर दिया।

जोर वायरस मारने पर, प्रक्रिया समझने पर नहीं : आधुनिक विज्ञान ने संक्रामक रोगों (विषाणुओं) को खत्म करने पर तो जोर दिया, लेकिन रोगाणुओं (माइक्रोब्स) के जीवनचक्र को समझने की कोशिश नहीं की। यह जीवनचक्र बताता है कि किसी संक्रमण के लंबे समय तक जीवित रहने, एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में छलांग लगाने और उत्परिवर्तन की कार्यप्रणाली क्या होती है। इसका परिणाम यह निकला कि संक्रमण की श्रृंखला टूटने के बजाय वह और मजबूत होती चली गई। शायद यही वजह है कि बीते चार दशकों में बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला, मलेरिया, डेंगू बुखार, जीका और एचआइवी-एड्स आदि से होने वाली मौतों में कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। दावा यह भी है कि 1970 के बाद से 30 नई संक्रामक बीमारियों ने मानव समुदाय को घेर लिया है। कोरोना वायरस को इस गिनती में सबसे नया ठहराया जा सकता है। चूंकि वायरस म्यूटेशन का रुख अपना रहे हैं। यानी हालात के मुताबिक खुद को समायोजित कर लेते हैं और अपना स्वरूप बदल लेते हैं। इससे उनके मुकाबले को बनी दवाइयां और टीके कारगर नहीं रह पाते हैं। हालांकि इसके पीछे फार्मा कंपनियों की साजिश का भी एक आरोप लगाया जाता है। दावा किया जाता है कि दवा कंपनियां खुद नहीं चाहतीं कि कोई वायरस इतनी जल्दी धरती से विदा हो जाए या उनका म्यूटेशन हमेशा के लिए रुक जाए। इस दावे का आधार यह है कि शोध-अनुसंधान का हवाला देकर उन्हें पहले से कई गुना महंगी दवाएं और टीके बेचने का मौका मिल जाता है। एक और बड़ा कारण रोग-निदान या उपचार का सही तरीका विकसित किए बगैर दवाओं और टीकों की बमबारी करना भी है। खास तौर से एंटीबायोटिक दवाओं के अंधाधुंध इस्तेमाल ने वायरसों को खत्म करने के बजाय उन्हें और मजबूत ही बनाया है। कोरोना से निपटने में जिस तरह विभिन्न दवाओं का बिना यह जाने ताबड़तोड़ इस्तेमाल हुआ कि वे कोई असर करेंगी भी या नहीं, स्थितियां बिगाड़ी ही हैं।

बिगड़ती जीवनशैली भी गुनहगार : पिछले चार दशकों में अगर संक्रामक बीमारियों ने रफ्तार पकड़ी है तो इसके लिए शहरीकरण और लोगों की बिगड़ती जीवनशैली भी एक अहम वजह प्रतीत होती है। कोरोना से पहले भी इसकी चर्चा दुनिया भर में थी कि खराब जीवनशैली हर साल लाखों लोगों को मौत के मुंह में धकेल रही है। कोरोना के प्रकोप के दौरान यह जोखिम और बढ़ गया है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के शोध में बताया गया है कि शारीरिक श्रम की कमी और निष्क्रिय जीवनशैली ने कोरोना संक्रमण की जद में आने वालों में वायरस के गंभीर लक्षण पैदा किए और उनकी मृत्यु का जोखिम दूसरों के मुकाबले अधिक रहा। निष्क्रिय जीवनशैली के साथ धूमपान, मोटापा और उच्च रक्तचाप ने कोरोना की मार में काफी ज्यादा इजाफा कर दिया। हो सकता है कि आगे चलकर यह तथ्य भी पर्याप्त डाटा मिलने पर सामने आए कि ग्रामीणों के मुकाबले कोरोना ने उन शहरियों पर ज्यादा कहर ढाया है, जो सुविधाजनक जीवनशैली के आदी हो गए हैं। वातानुकूलित कमरों में रहने के कारण उनके फेफड़े कमजोर पड़ गए जिससे वे कोरोना की आसान चपेट में आ गए।

चार साल पहले सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने भी अपनी रिपोर्ट 'बॉडी बर्डन' में चेताया था कि भारत में होने वाली कुल मौतों में से 61 फीसद खराब जीवनशैली और गैर संचारी रोगों की वजह से होती हैं। कैंसर, हृदयरोग और मधुमेह के अलावा हमारे शहरों में लोगों के फेफड़े वायु प्रदूषण और शारीरिक निष्क्रियता के चलते कमजोर होते जा रहे हैं। दिल्ली में हर तीसरे बच्चे के फेफड़े प्रभावित हैं और 2016 में भारत में 3.5 करोड़ लोग अस्थमा के गंभीर मरीज पाए गए थे। अफसोस कि इस रिपोर्ट के महत्व को गंभीरता से नहीं समझा गया और कोरोना के दौर में हम भारतीयों के फेफड़े गंभीर संकट में फंस गए।

अब वक्त आ गया है, जब पूरी दुनिया को ठहरकर सोचना चाहिए कि वह आखिर ऐसा क्या करे, जिससे कोरोना जैसी महामारियां दोबारा लौटकर न आ पाएं। सरकारें जनता को कम कीमत पर अच्छे इलाज की सहूलियतें देने के साथ जागरूक करें कि बीमार होने से बेहतर है कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाई जाए। उन पर्यावरणीय कारणों की तह में भी जाना होगा, जो नए वायरसों की पैदावार, कई पुराने वायरसों की वापसी और उनके उत्परिवर्तन की वजह बन रहे हैं। ऐसे प्रबंध किए जाएं, ताकि भविष्य में किसी भी संक्रमण को हावी होने का मौका नहीं मिले।

कहानी 'कप्पा' और 'डेल्टा' की

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहा और उनके सहयोगी (माइक पोंपियो) ने इसे बाकायदा वुहान वायरस कहकर पुकारा तो सबसे पहली आपत्ति चीन की तरफ से ही आई। वैसे वायरस के ऐसे नामकरण को लेकर कोई भी देश एतराज कर सकता है। यही वजह है कि डब्ल्यूएचओ ने इसकी एक व्यवस्था बनाई है। इसके तहत कोरोना वायरस सार्स-कोव-2 के विभिन्न नामकरण किए गए हैं। चूंकि वक्त के साथ और म्यूटेशन के कारण कोरोना वायरस के व्यवहार और संहारक क्षमता में तब्दीली हो रही है, इसलिए नाम में भी परिवर्तन किया जा रहा है। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि इन बदलावों का एक असर वायरसों के गुणों पर पड़ता है। परिवर्तनों के बाद कोई वायरस आसानी से फैल सकता है या बीमारी-महामारी की गंभीरता को प्रभावित कर सकता है अथवा बचाव की वैक्सीनों को धता बता सकता है। ऐसे में नए वायरस की पहचान सुनिश्चित कर उससे बचाव के तौर-तरीके में भी तब्दीली लानी पड़ती है। यह परिवर्तन अलग-अलग देशों में वहां की जलवायु और वायरस के म्यूटेशन की प्रवृत्तियों के आधार पर होता है। जैसे भारत की बात करें तो यहां अक्टूबर 2020 में पहली बार सामने आए कोरोना वायरस के नए स्वरूप बी.1.617.1 को डब्ल्यूएचओ ने 'कप्पा' नाम का लेबल दिया, जबकि एक अन्य वैरिएंट बी.1.617.2 को डेल्टा नाम दिया। डेल्टा नाम दिए जाने से पहले दुनिया में बी.1.617.2 को भारतीय या कोरोना का बंगाल वायरस कहा जाने लगा था। इस पर भारत ने आपत्ति जताई थी।

वायरस की नई पहचान के लिए डेल्टा आदि अक्षर ग्रीक वर्णमाला से लिए गए हैं। इस सिलसिले में ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए वैरिएंट बी.1.1.7 को अल्फा, दक्षिण अफ्रीका में मिले वैरिएंट बी.1.351 को बीटा और ब्राजील में मिले पी.1 को गामा नाम दिया है। ये सभी वे वैरिएंट हैं जिन्हें वैरिएंट ऑफ कंसर्न (वीओसी) की श्रेणी में रखा गया है। जबकि वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट (वीओआइ) की श्रेणी में रखे अमेरिका में पहली बार मिले वैरिएंट बी.1.427/बी.1.429 को एप्सिलोन, ब्राजील में मिले पी.2 को जीटा, कई अन्य देशों में मिले वैरिएंट बी.1.525 को ईटा, फिलीपींस में मिले पी.3 को थीटा, बी.1.526 को लोटा नाम दिया गया है। जोखिम के स्तर को देखते हुए कोरोना के नए रूपों को वीओआइ और वीओसी दो भागों में बांट दिया है।

खरी-खरी

फिल्मों में साहित्य

विनय मोघे

साहित्य कुमार जी चिंतित हैं। उनकी चिंता का कारण है फिल्मों से लुप्त होता साहित्य। उनके अनुसार आजकल की फिल्मों में साहित्य सिरे से नदारद है। यदि यही हाल रहा तो लोगों में साहित्य के प्रति रुचि कैसे पैदा होगी। पहले की फिल्मों में कुछ तो साहित्य था। किसी दृश्य में किताबों की शेल्फ दिखाई जाती थी। किसी दृश्य में हीरोइन और हीरो आपस में टकराते थे और हीरोइन के हाथों से किताबें गिरती थीं। किसी दृश्य में हीरो-हीरोइन एक-दूसरे को प्रेम पत्र लिखते। यह छिछला साहित्य ही सही, मगर कम से कम कुछ लिखा तो जाता था। साहित्य कुमार जी चाहते हैं कि जिन फिल्मों में साहित्य नहीं है, उनमें साहित्य डालकर उन फिल्मों का पुनर्निर्माण किया जाए। इसके लिए वे अपनी तरफ से तैयारियां भी कर रहे हैं। फिल्मों के नाम के साथ उन्होंने शुरुआत की है। पर जब उन्होंने फिल्मों के नाम पर गौर किया तो पाया कि कई फिल्मों के नाम ऐसे हैं, जो कहीं न कहीं साहित्य से जुड़े हैं।

उनमें कुछ इस प्रकार हैं। पगलैट : यह एक साहित्यिक नाम है। कम या ज्यादा, हर लेखक थोड़ा पगलैट होता ही है। थप्पड़: हर लेखक को लगता है कि वह जो लिख रहा है, वह समाज के गाल पर करारा थप्पड़ ही है। ये बात और है कि समाज उस लेखक की रचना को न पढ़कर उल्टा उसे ही करारा थप्पड़ जड़ देता है। अतः थप्पड़ नाम भी साहित्यिक ही माना जाना चाहिए। पंगा : बिना पंगा लिए साहित्य की दुनिया एक कदम नहीं चल सकती। एक-दूसरे की टांग खींचे बिना कोई किसी के उपन्यास को बर्दाश्त कर ले, यह देखे बरसों हो गए। मलाल : यदि किसी ने अच्छा लिख लिया तो बाकी लिखने वालों को गहरा मलाल हो जाता है। और जो अच्छा नहीं लिख पाता, उसे न छपने का मलाल सताता रहता है। साहित्य में जिसे अकादमियों की मलाई न मिली, वह भी मलाल सिंह मालवीय बनकर अकादमियों की समालोचना में डूब जाता है। लुका-छिपी: संपादक और लेखक के बीच चलने वाली लुका-छिपी में जो साहित्य का दर्द छुपा है...उसका कहना ही क्या। वांटेड: वांटेड यानी चाहना/चाहा गया। अब लेखक को पाठक और पुरस्कार चाहिए। कुल मिलाकर फिल्मों में साहित्य भोत है भिया...चिंताने की कोई जरवत ही नहीं है।

ट्वीट-ट्वीट

शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं! शादी के प्रलोभन में धर्मांतरण करना नहीं।
मीनाक्षी जोशी@IMinakshiJoshi

हमारे समाज में अधिकांश समस्याएं इस वजह से कायम हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चों को दर्शन, अध्यात्म और रचनात्मकता नहीं पढ़ाई-सिखाई जाती।
विवेक रंजन अग्निहोत्री@vivekagnihotri



प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की, लेकिन गांधी परिवार में किसी ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलना गवारा नहीं समझा। यही बात काफी कुछ बता देती है।
पल्लवी घोष@_pallavighosh

अब दूध की कीमतों में इजाफा हो गया है। पेट्रो उत्पादों की कीमतें बढ़ना रोज की बात हो गई है। कई आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। आम लोगों की मुश्किलें बढ़ने पर हैं। गरीबों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार नकदी हस्तांतरण और मुफ्त फूड किट्स प्रदान करे।
सीताराम येचुरी@SitaramYechury

नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किसमें क्या देखते हैं, यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है।
अरुण गोविल@arungovil12

कोरोना वायरस ने मेरी स्मृतियों को नष्ट कर दिया है। अच्छी बात है कि अपने संस्मरणों से जुड़ी सात किताबें मैंने कोरोना के आने से पहले ही लिख ली थीं।
तसलीमा नसरीन@taslimanasreen

हिमाचल प्रदेश डायरी

थप्पड़ और लात से आगे सीखने की बात



नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

यह ठीक है कि किसी एक अवांछित घटनाक्रम से किसी संस्था के बारे में बनी धारणा को समग्रता नहीं दी जा सकती, लेकिन घटना घटी है तो दर्ज होगी ही। मर्यादा के मानक रघुनाथ जी की नगरी कुल्लू में अपने ही निशाने पर आई पुलिस को ऐसे जख्म मिले हैं, जो जल्द नहीं सूखेंगे। कुछ पृष्ठभूमि थी, कुछ अवांछित शब्द थे, अप्रिय भंगिमाएं थीं, फिर पुलिस अधीक्षक कुल्लू की ओर से मुख्यमंत्री सुरक्षा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक थप्पड़ था, फिर कुछ सवाल थे और अंततः मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लंबे समय से तैनात सहायक उपनिरीक्षक की ओर से पुलिस अधीक्षक के लिए लात थी। बेशक यह केवल एक दिन की बात थी, मगर इस बहाने सबको कुछ न कुछ मिल गया। राजनीतिक लोगों को राजनीति के बिंदु, आम जनता को सवालों के सिंधु और शासन-प्रशासन के हिस्से आलोचना आई। इस घटनाक्रम के मुख्य किरदार तीन ही थे, लेकिन पुलिस महानिदेशक की ओर से जारी एक पत्र कहता है कि मामला समग्र बल के लिए कितना अभूतपूर्व था। कई स्तरों पर जांच हुई, रपटें बनीं। एसपी कुल्लू और लात चलाने वाले पीएसओ निलंबित हो चुके हैं।

सवाल यह है कि प्रमुख लोगों की सुरक्षा में पुलिस स्टाफ की तैनाती का मानक क्या है? पात्रता अगर विश्वासपात्र होना है तो गलत क्या है? अंततः एक परस्पर समझ और विश्वास में क्या बुरा है? लेकिन विश्वासपात्रता इस संदर्भ में पात्रता का विकल्प नहीं हो सकती। जाहिर है जब एसपी का थप्पड़ उठा होगा तो किसी चुनौती या उत्तेजक कारण से उठा होगा। एक पीएसओ को भी अपनी लात के 'वजन' पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह भी चली और एसपी पर चली। यह अपनी प्रतिष्ठा या अपनों के लिए विश्वास का प्रतीक तो है, लेकिन पात्रता पर प्रश्नचिह्न है। आमतौर पर मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री जैसे प्रतिष्ठित लोगों के दौरे से पूर्व उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समन्वय बनाते हैं। यहां तक कि दोनों एक ही गाड़ी में होते हैं, जिनके निरंतर संपर्क में मुख्यमंत्री का सुरक्षा दस्ता भी रहता है। प्रतीति यह है कि कुल्लू प्रकरण में कोई किसी के समुचित संपर्क में नहीं था। पुलिस लगातार निशाने पर है, लेकिन यह सवाल नहीं उठा कि उपायुक्त उस समय कहां थे? अगर वह स्थानांतरणाधीन थे तो क्या उनका तबादला दो दिन के लिए रोका नहीं जा सकता था। यदि तबादला ही अनिवार्य था तो उनका प्रभार जिनके पास था, वह कहां थे? सभी पक्ष परस्पर संपर्क में होते तो कौन-सी गाड़ी किस क्रम पर चलेगी जैसी छोटी बातें स्वतः तय हो गई होतीं। जहां समन्वय होता है, वहां किसी उपायुक्त को यह असुरक्षा नहीं होती कि सुरक्षा दस्ते के लोग तो एसपी के लोग हैं।


केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कुल्लू दौरे के दौरान भुंतर एयरपोर्ट के समीप भिड़ते मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मी और कुल्लू के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह। वीडियो ग्रैब

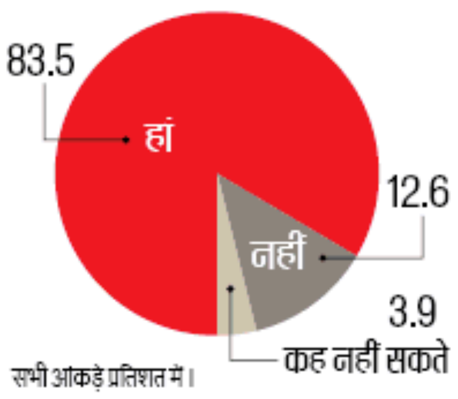
हिमाचल के इतिहास में मुख्यमंत्रियों को कतिपय लोग ऐसे और इतने पसंद आए कि उन्होंने सेवाकाल तो पूरा मुख्यमंत्री के साथ ही काटा, वर्षों का सेवाविस्तार पाकर भी उन्हीं के साथ रहे। यह पुलिस की नई पौध में भरोसेमंद लोगों का संकट था या इनके भरोसे की दीवार इतनी मजबूत थी कि कोई फांद नहीं पाया। एक सुयोग्य सुरक्षा अधिकारी जानता है कि किस व्यक्ति को देखकर साहब प्रसन्न होंगे या अप्रसन्न होंगे। वह यह भी जानता है कि किसको कब, कैसे और कहां मिलवाना है। उसे यह भी पता है कि वह बेशक वीवीआइपी का सुरक्षा अधिकारी है, लेकिन जिले का एसपी उसका वरिष्ठ अधिकारी है। वह यह भी जानता है कि वीवीआइपी की किसी मुखमुद्रा का क्या संदेश है। आइएएस, आइपीएस हों या मुख्यमंत्री के सुरक्षा दस्ते से जुड़े लोग, उनका वास्तविक प्रशिक्षण तो इन साहबों के साथ या धरातल पर होता है, अकादमियों में केवल अकादमिक प्रशिक्षण ही मिलता है।

इस घटना ने पुलिस के लिए इस विमर्श के द्वार खोल दिए हैं कि सुरक्षा दस्ते के लिए अधिकारी या कर्मचारी का चयन पसंद के आधार पर होना चाहिए या नहीं? क्या उनका कार्यकाल वीवीआइपी की प्रसन्नतापर्यंत होना चाहिए या कुछ ढाई या तीन वर्ष की अवधि होनी चाहिए? वे केवल सुरक्षा दस्ते के सदस्य नहीं, अपितु वीवीआइपी और जनता के मध्य सेतु भी हैं, इस विषय का प्रशिक्षण क्या नियमित रूप से मिलना नहीं चाहिए? वीवीआइपी के संदेश वीवीआइपी के होते हैं, संदेशवाहक की शालीनता इस पक्ष में होती है कि वह स्वयं को वीवीआइपी समझे बगैर संदेश को अग्रसारित करे। व्यवस्था या संवाद में जब-जब खाइयां निकलेंगी, उद्देश्यों के कदम लड़खड़ाएंगे। कुल्लू में लक्ष्य क्या था और हुआ क्या, यह प्रत्यक्ष दिखा है। यह संवाद का समय है। यह बताने का समय है कि पुलिस की जरूरत सबको है, लेकिन क्या पुलिस पर भी पुलिस बिठानी पड़ेगी? दायरा तो हर पद के साथ जुड़ा है, फिर जहां समूहगान अपेक्षित था, वहां तीन किरदारों ने अपनी-अपनी डफली और अपना-अपना बेसुरा राग क्यों चुना? दंड और उसका तरीका तो शासन ही तय करेगा, लेकिन सबसे जरूरी उन कारणों को खत्म करना है जिनसे ये घटनाएं होती हैं।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या केंद्रीय स्तर पर मतांतरण रोधी कानून बनाने की आवश्यकता है?



सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या एक के बाद एक एफआइआर दर्ज होने से ट्विटर पर कुछ असर पड़ेगा?

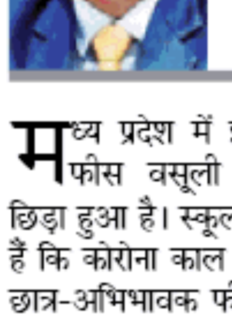
परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

ट्वीटर की गुस्ताखियां होतीं अपरम्पार,
जाने कब वह जोड़ दे कहीं का कहीं तार।
कहीं का कहीं तार शार्ट सर्किट हो जाए,
तो वह सॉरी बोल पुनः रस्ते पर आए!
खींचा जाए कान रहे तब हद के भीतर,
वरना चढ़कर शीश नाच दिखलाए ट्वीटर।
– ओमप्रकाश तिवारी

मध्य प्रदेश डायरी

फीस वृद्धि पर तकरार, उलझन में सरकार



संजय मिश्र
स्थानीय संपादक, नवदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश में इन दिनों स्कूलों में फीस वसूली को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। स्कूलों के प्रबंधक चाहते हैं कि कोरोना काल के पूर्व की तरह ही छात्र-अभिभावक फीस देते रहें, जबकि अभिभावक सवाल कर रहे हैं कि जब एक साल से स्कूल खुले ही नहीं तो फीस किस बात के लिए दी जाए। इस बीच स्कूलों ने नए सत्र के नाम पर बीस से चालीस फीसद तक फीस बढ़ा दी है। सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग इस विवाद में कोई स्पष्ट राय नहीं बना पा रहा है। कभी वह स्कूल प्रबंधकों की तरफ लुढ़कता दिखता है तो कभी अभिभावकों वाली बात कह देता है। मंगलवार को इसी विषय को लेकर राजधानी भोपाल में एक ऐसी घटना हुई जिसने शिक्षा विभाग में बनी अनिर्णय की स्थिति को उजागर कर दिया। फीस वृद्धि के प्रस्ताव के विरोध में तर्क दे रहे अभिभावकों के एक समूह को स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार ने झुंझलाहट में कह दिया कि 'मैं क्या करूं, मरना हो तो मर जाओ, जो करना हो करो।' मंत्री के इस रूखे व्यवहार ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। कांग्रेस ने इसे असंवेदनशील टिप्पणी ठहराया है। अभिभावकों का संगठन भी इस बयान के विरोध में आंदोलन की तैयारी कर रहा है। फीस वृद्धि को लेकर स्कूल प्रबंधकों एवं अभिभावकों के बीच विवाद को दूर करने के लिए सरकार को जल्द ही कड़े कदम उठाने होंगे।

वैसे तो कोरोना काल शुरू होने के साथ ही एक साल से स्कूल-कालेज बंद हैं। छात्रों की आवाजाही पूरी तरह ठप है। स्कूलों में सन्नाटा बढ़ गया है, पर उनकी जिम्मेदारी में कमी नहीं आ पाई है। स्कूलों ने शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन देने के लिए अपने तरीके से फार्मूला निकाल रखा है। कहीं आधा वेतन मिल रहा है तो कहीं नाम मात्र का। उनकी दलील है कि पूर्व की तरह पूरी फीस नहीं मिल रही है, इसलिए पूरा वेतन नहीं दे पाएंगे। सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग उनकी बातों से लगभग सहमत होते हुए पूरा वेतन देने का दबाव नहीं बना पा रहा है। इसे अनिर्णय की स्थिति ही कहेंगे कि वह एक तरह से दो पाटों में पिस रहा है। एक तरफ अभिभावक दलील दे रहे हैं कि कोरोना काल में उनके बच्चे स्कूल नहीं गए और उनके रोजगार पर भी संकट खड़ा हो गया, ऐसे में वे मनमाना फीस क्यों चुकाएं। दूसरी तरफ स्कूलों के प्रबंधक तर्क दे रहे हैं कि यदि फीस नहीं बढ़ाई गई तो स्कूल आगे चला पाना मुश्किल है।

फीस वृद्धि न करने और केवल ट्यूशन फीस ही लिए जाने की मांग को लेकर अभिभावक काफी दिनों से स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों और मंत्री का दरवाजा खटखटा रहे हैं। सुनवाई नहीं हुई तो मंगलवार को अभिभावकों का एक समूह राज्यमंत्री परमार के बंगले पर पहुंच गया। उसने अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया तो राज्यमंत्री भी तैश में आ गए। उनकी टिप्पणी ने फीस वृद्धि के विवाद को अब और गहरा कर दिया है।

राज्यमंत्री की झुंझलाहट के दो प्रमुख कारण चर्चा में हैं। पहला यह कि स्कूल चाहते थे कि एक जुलाई से शैक्षणिक गतिविधियां शुरू की जाएं। इससे शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं खुद राज्यमंत्री भी सहमत थे। प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजा, लेकिन उन्होंने हरी झंडी नहीं दी। कोरोना काल में छात्रों की सुरक्षा को सबसे जरूरी मानते हुए मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव लौटा दिया। दूसरा कारण यह कि फीस कम नहीं करने को लेकर निजी स्कूल संचालकों का शिक्षा विभाग पर दबाव है। राज्यमंत्री चाहते हैं कि कोई रास्ता निकले, ताकि स्कूलों की व्यवस्था भी चलती रहे।

फीस का विवाद नवंबर 2020 में जबलपुर हाई कोर्ट के समक्ष भी उठा था। तब जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पांच नवंबर, 2020 को कहा था कि स्कूल तब तक छात्रों से सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे, जब तक सरकार यह घोषणा नहीं करती है कि कोरोना महामारी खत्म हो चुकी है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों के वेतन का नियमित भुगतान किया जाए। जरूरी होने पर उनके वेतन में अधिकतम 20 फीसद की कटौती की जा सकती है। इसके बावजूद स्कूल शिक्षकों एवं कर्मचारियों को 50 फीसद तक ही वेतन दे रहे हैं। कई स्कूल 30 फीसद से भी कम वेतन दे रहे हैं।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने भी दिशानिर्देश जारी किया था, जिसके कारण स्कूलों ने अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस ली थी। अब स्कूलों की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि ऐसा करने से उन्हें 20 से 35 फीसद का नुकसान हुआ है। इसलिए नए सत्र में ट्यूशन फीस के साथ ही अन्य शुल्क (भवन मरम्मत, लाइब्रेरी, लैब, स्पोर्ट्स, बस किराया आदि) भी लेना चाहते हैं। उन्होंने नए शैक्षणिक सत्र में 20 से 40 फीसद तक फीस बढ़ा भी दी है, जिसका अभिभावक विरोध कर रहे हैं। प्रदेश में एक दशक की कवायद के बाद निजी स्कूलों के लिए फीस नियंत्रण कानून वर्ष 2017 में बनाया गया और इसके नियम जनवरी 2021 में जारी किए गए, लेकिन समस्या यह है कि अब तक उसे उचित ढंग से लागू नहीं किया जा सका है।


मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार की टिप्पणी ने विपक्ष को शिवराज सिंह सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। फाइल

24 जुलाई को व्यास पूर्णिमा के दिन पहलगाम में होगा भगवान श्री अमरेश्वर की पवित्र छड़ी मुबारक का ध्वजारोहण और भूमि पूजन। इस बार कोविड-19 प्रोटोकाल के तहत यात्रा को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया है, सिर्फ छड़ी मुबारक ही पवित्र गुफा के लिए रवाना होगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 1 जुलाई, 2021

बंगाल

हाई कोर्ट की कड़ी फटकार

महानगर में फर्जी टीकाकांड को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाशीध ने साफ कहा कि महानगर में इतनी भड़ी फर्जीवाड़ा होने की जिम्मेदारी से सरकार नहीं बच सकती। साथ ही सवाल यह उठाया गया कि फर्जी आइएएस अफसर बन कर देबांजन देब कैसे लंबे समय नीली बत्ती लगी गाड़ी से महानगर में घूमता रहा और यहां तक कि कोलकाता नगर निगम को भी होश नहीं आया। जस्टिस राजेश बिंदल ने यहां तक कह दिया कि इस तरह की फर्जीवाड़ा बंगाल में ही संभव है।

इस मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से हलफनामा तलब किया है। क्योंकि इस कांड को लेकर हाई कोर्ट में चार जनहित याचिका दायर हुई है। जिसमें इस कांड की सीबीआइ जांच की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ममता सरकार से फर्जी टीकाकांड पर आगामी दो दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बंगाल के मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी है। भूषण द्वारा लिखे गए पत्र में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को फर्जी टीकाकांड को लेकर लिखे गए पत्र का भी संदर्भ दिया गया है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी कोलकाता पुलिस से मुकदमा से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं, ताकि केंद्रीय एजेंसी भी जांच शुरू कर सके। इस मामले में ममता सरकार की इसीलिए भी अधिक किरकिरी हो रही है, क्योंकि फर्जी टीकाकरण शिविर लगाने वाले फर्जी आइएएस अधिकारी देबांजन देब की कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वह पुलिस से लेकर तृणमूल के कई नेता, मंत्रियों के साथ दिख रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ गई है।

> ममता की इसलिए भी अधिक किरकिरी हो रही है, क्योंकि फर्जी टीकाकरण शिविर लगाने वाले फर्जी आइएएस अधिकारी की कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वह तृणमूल के नेताओं के साथ दिख रहा है

बुधवार को मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को भाजपा की साजिश बताने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह भाजपा की सुनियोजित साजिश हो सकती है। परंतु यहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने यह सवाल उठाया है कि इस कांड के सरगना की तस्वीरें तृणमूल नेताओं के साथ है और साजिश किसी और की? खैर जो भी हो सियासी आरोप-प्रत्यारोप अपने जगह पर है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो पूछा है वह गंभीर सवाल है और ममता सरकार को बताना होगा कि यह फर्जीवाड़ा आखिर हुआ कैसे?

पंजाब

मजबूत सुरक्षा तंत्र की जरूरत

पाकिस्तान सीमा से लगते पंजाब के इलाकों में अतिरिक्त चौकसी बरतने और गांवों व सड़कों पर जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला समय की मांग है। डीजीपी ने इस संबंध में निर्देश देकर उचित ही किया है। जम्मू में वायुसेना के टेक्निकल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद डीजीपी दिनकर गुप्ता की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीमा सुरक्षा बल और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है। डीजीपी का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि केंद्रीय व प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों में तालमेल बहुत जरूरी है। कोई भी इनपुट तत्काल साझा किया जाना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि पठानकोट एयरबेस परिसर और गुरदासपुर के दीनानगर में दो बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन के माध्यम से हथियार और हेरोइन इत्यादि भेजने की कोशिशें जारी हैं। कई बार बीएसएफ के जवानों ने फायर करके ड्रोन को लौटा दिया, लेकिन अमृतसर व तरनतारन के सीमावर्ती क्षेत्रों में हथियार व हेरोइन के पैकेट मिल चुके हैं। भारत के ही कुछ तस्कर


अत्याधुनिक संसाधनों के माध्यम से सुरक्षा चुनौतियों से निपटा जा सकता है। फाइल

> सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों व सड़कों पर सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे लगाना बहुत जरूरी है। डीजीपी की ओर से निर्देश दिए जाने के बाद यह काम यथाशीघ्र किया जाना चाहिए

पाकिस्तानी तस्करों से मिलकर पैसों के लालच में हथियार व हेरोइन मंगवाते हैं और अपने देश से गद्दारी करते हैं। पंजाब को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान में बैठे असामाजिक तत्व हमेशा सक्रिय रहते हैं। डीजीपी भी मानते हैं कि 20 महीनों में सीमावर्ती क्षेत्रों में 60 से अधिक बार ड्रोन की गतिविधियां देखी जा चुकी हैं। जैसा कि डीजीपी ने कहा है कि सीमा से लगते इलाकों में यदि कोई अजनबी या संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो ग्रामीणों को इसकी सूचना तत्काल सुरक्षा बलों को देनी ही चाहिए। पंजाब की करीब साढ़े पांच सौ किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से लगती है। इतनी लंबी सीमा पर सीसीटीवी कैमरे लगाना आसान नहीं है, लेकिन संवेदनशील क्षेत्रों में तो कैमरे यथाशीघ्र लगाए ही जाने चाहिए। चूंकि प्रदेश में गैंगस्टरों व नशा तस्करों का गठजोड़ बन चुका है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह गठजोड़ तोड़ना बहुत बड़ी चुनौती है। इनमें से कुछ का संबंध आतंकियों से भी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में खुफिया तंत्र को मजबूत करने के साथ ही अत्याधुनिक संसाधनों के माध्यम से ही चुनौतियों से निपटा जा सकता है।

हरियाणा

किसानों के कल्याण की चिंता

प्रदेश सरकार को किसान उत्पादक समूहों के बड़ी संख्या में गठन पर ध्यान देना चाहिए, यद्यपि प्रदेश में 486 किसान उत्पादक समूह बनाए जा चुके हैं और 76,855 किसानों को इन समूहों से जोड़ा जा चुका है, लेकिन किसान उत्पादक समूहों की संख्या और बढ़ाई जानी चाहिए। वैसे प्रदेश सरकार का लक्ष्य भी 1000 किसान उत्पादक समूह बनाने का है। यदि प्रदेश में एक हजार किसान उत्पादक समूह बन जाएंगे तो इससे छोटी जोत वाले किसानों को बड़ा लाभ होगा। किसान उत्पादक समूह वैसे तो सभी किसानों के लिए उपयोगी हैं, लेकिन छोटी जोत वाले किसानों के लिए उनकी महती आवश्यकता है। होता यह है कि छोटी जोत वाले किसान जो भी उपजाते हैं, उसको बेचने की व्यवस्था भी उन्हें करनी पड़ती है। अपने उत्पाद को बाजार ले जाना ही उनके लिए समस्या होती है। किसी तरह ले भी गए तो क्रेता उसका मूल्य भी कम लगाता है, क्योंकि क्रेता को ज्ञात होता है कि विक्रेता के लिए अपने उत्पाद को फिर गांव ले जाना दुष्कर होगा। लेकिन जब वह कृषि उत्पादक समूह से जुड़ जाता है तो वह सीधा कृषि बाजार और उपभोक्ताओं से जुड़ जाता है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कृषि उत्पादक समूह ऐसे किसानों का एक समूह है, जो कृषि उत्पादन कार्य में लगे होते हैं। यह समूह कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां भी चलाते हैं और कंपनी अधिनियम के तहत इनके पंजीयन की भी व्यवस्था है।


किसानों के हित में है किसान उत्पादक समूह का बनना। फाइल

> किसान उत्पादन समूहों का बड़ी संख्या में गठन कर किसानों को उनसे जोड़ने का प्रयास होना चाहिए

समूह के सदस्य यह तय कर सकते हैं कि उनके समूह में किस फसल का उत्पादन कितना है, उस उत्पाद का विपणन कैसे किया जाएगा। इससे कम जोत वाले किसान अनेक समस्याओं से बच जाते हैं। उपभोक्ता भी सीधे किसान समूहों से संपर्क कर वांछित उत्पाद क्रय कर लेता है। यदि किसान उत्पादक समूहों से छोटी जोत वाले किसान जुड़ते हैं तो केवल उनका ही लाभ नहीं होता, उपभोक्ताओं का भी लाभ होता है, क्योंकि वे बिचौलियों के बजाय सीधे किसानों से उनके उत्पाद खरीदते हैं तो वह अपेक्षाकृत सस्ता होता है। इसलिए प्रदेश सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि अधिक से अधिक किसान समूहों का गठन किया जाए और अधिक से अधिक किसानों को उनसे जोड़ा जाए।

उत्तराखंड

प्रदेश में बढ़ता साइबर क्राइम

उत्तराखंड में साइबर क्राइम के बढ़ते मामले चिंता बढ़ाने वाले हैं। पिछले कुछ समय से ऐसे मामलों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। आधुनिक तकनीक ने जीवनशैली को आसान तो बनाया है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी उसी तरह से बढ़ रहा है। हैरत यह है कि ठगे जाने वाले ज्यादातर लोग शिक्षित तबके के हैं। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी भी शामिल हैं। दरअसल देखा जाए तो यह मानवीय स्वभाव है कि व्यक्ति कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहता है और ठगी को अंजाम दे रहे लोग इसी मनोवृत्ति को निशाना बनाते हैं। इसके अलावा मदद मांगने के नाम पर भी ठगी के मामले सामने आए हैं। यह भी मानवीय संवेदना ही है कि जो मदद के लिए प्रेरित करती है और ठग इसका लाभ उठाते हैं। इन व्यक्तियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि यह जानी-मानी शख्सियतों के नाम पर भी ठगी को अंजाम दे रहे हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक के नाम पर राजस्थान के गैंग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में कई व्यक्तियों को चूना लगा दिया। अच्छी बात यह है कि पुलिस और विशेष टास्क फोर्स ने इसके साथ ही कई अन्य मामलों में तेजी दिखाते हुए बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से 14 आरोपितों को गिरफ्तार किया। इनमें सर्वाधिक राजस्थान के भरतपुर से थे। पुलिस के अनुसार इस तरह के गिरोह की गतिविधियां झारखंड के जामताड़ा और हरियाणा के मेवात इलाके से संचालित की जा रही हैं। पुलिस के लिए यह एक बड़ी कामयाबी है। इसके लिए पुलिस टीम को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक की यात्राएं करनी पड़ीं। निश्चित ही इस कार्रवाई के लिए उत्तराखंड पुलिस की सराहना की जानी चाहिए। अब तक पूछताछ में सामने आए तथ्यों के मुताबिक ये अपराधी प्रदेश के सात जिलों में वारदात को अंजाम देकर करीब 15 लाख रुपये हड़प चुके हैं। यह सही है कि साइबर क्राइम के मामलों में अपराधी तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि कुछ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है कि अपराध हो ही नहीं। इसके लिए पुलिस के साथ ही आम आदमी की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। आम आदमी को भी सोचना पड़ेगा कि अनजान लिंक पर सक्रियता दिखाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और अन्य इंटरनेट माध्यमों पर आने वाले संदेशों को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है। यह समझना होगा कि कमाई के लिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हालांकि प्रदेश में कई जगह साइबर थाने खोल दिए गए हैं, लेकिन कई बार देखने में आता है कि पुलिस मामलों में मुकदमा दर्ज करने में रुचि नहीं दिखाती।

> साइबर क्राइम को लेकर पुलिस की ताजा कार्रवाई उम्मीद तो जगाती है, पर आम जन को भी सजग रहना होगा। ठग भी लालच की मनोवृत्ति को ही निशाना बना रहे हैं

विदेश में लाखों का पैकेज छोड़कर लौटे गांव, मछली पालन को बनाया व्यवसाय

जागरण विशेष

मोदीनगर के रजनीश कुमार ने 12 एकड़ से शुरुआत कर तीन साल में 100 एकड़ तक बढ़ाया मछली पालन का कारोबार

हसीन शाह • गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश के मोदीनगर के पतला गांव निवासी रजनीश कुमार इंजीनियर बन चुके थे। इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे देशों में नौकरी की। इंग्लैंड में 30 लाख के पैकेज पर अच्छी नौकरी थी, लेकिन एक भारतीय के मन में अपने देश का मोह और गांव की छांव की हूक रहती ही है। रजनीश के साथ भी वही हुआ और वह अपने गांव लौट आए। गांव में रहकर ही मछली पालन की शुरुआत की, जिसके विषय में कुछ नहीं जानते थे। आज उनका अच्छा व्यवसाय है और मछली पालन के बारे में औरों को भी निश्शुल्क प्रशिक्षित कर रहे हैं।


रजनीश कुमार के पतला गांव स्थित तालाब से मछली निकाल कर ले जाते हुए कामगार • सौजन्यः स्वयं

> मैंने फरवरी, 2020 में रजनीश कुमार के गांव में मछली पालन का प्रशिक्षण लिया था। अब अपने गांव में साढ़े चार एकड़ तालाब में मछली पालन कर रही हूं। कोई समस्या होती है तो उनसे फोन पर बात कर लेती हूं। मेरे साथ कई कामगारों को भी काम मिल गया है।
> **मंजू पटेल**, निवासी गांव अंजोरा, दुर्ग, छत्तीसगढ़

> मैंने पतला गांव में तीन दिन का प्रशिक्षण लिया था। अब अपने गांव में 12 बीघा तालाब में मछली पालन कर रहा रहा हूं। धीरे-धीरे काम बढ़ने लगा है तो इसके लिए कुछ भूमि और लीज पर ले ली है। कोई परेशानी आती है तो रजनीश सर से मदद लेता हूं।
> **अभिषेक श्रीवास्तव**, खूझी गांव, प्रयागराज

> जमीन से जुड़ाव था, जब विदेश में था तो अपने घर में रहकर ही कुछ करने की भावना हमेशा रहती थी। निर्णय लिया, सफलता मिली अब खुशी है कि दूसरों को भी रोजगार मिल पा रहा है।
> **रजनीश कुमार**, इंजीनियर, पतला, मोदीनगर

एक पंथ दो काजः इस पहल से उन्होंने रोजगार के अवसर भी तलाशे और जल संरक्षण की दिशा में भी कदम बढ़ाया। रजनीश कुमार कहते हैं कि जब मैं इंग्लैंड से नौकरी छोड़कर आया तो सोचा था कि अब गांव में ही कुछ करूंगा जिससे आय के साधन भी बनें और पानी की बड़ी समस्या का भी कुछ निदान हो सके। दिल्ली-एनसीआर में वैसे भी लगातार जल स्तर नीचे जा रहा है। तब मछली पालन सबसे बेहतर विकल्प नजर आया क्योंकि इसके जरिये तालाब के माध्यम से बारिश का पानी भी संरक्षित हो जाता है। बताते हैं कि मछली पालन का अनुभव नहीं था। लिहाजा इसके लिए कई राज्यों में घूमे, प्रशिक्षण लिया। साल 2018 में 12 एकड़ में मछली पालन की शुरुआत की। अच्छा मुनाफा हुआ तो झलावा व मसूरी गांव में भी मछली पालन शुरू कर दिया। आज 100 एकड़ भूमि पर मछली पालन कर रहे हैं, देशभर में मछली आपूर्ति होती है।

कई किसानों को आत्मनिर्भर बनायाः रजनीश कुमार ने बताया कि वह जम्मू, गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्यों के 200 से अधिक किसानों को मछली पालन का प्रशिक्षण दे चुके हैं। यह प्रशिक्षण वह निश्शुल्क देते हैं। प्रशिक्षण के दौरान किसानों के ठहरने के लिए गांव में ही व्यवस्था की है। खाने व रहने का मामूली शुल्क लिया जाता है। कई किसान हैं जो प्रशिक्षण के बाद अपने यहां इसकी शुरुआत कर मुनाफा कमा रहे हैं।

पानी की टेस्टिंग व तकनीक की देते जानकारीः प्रशिक्षण के दौरान किसानों को पानी की टेस्टिंग, भोजन, मछली पालन की तकनीक आदि के बारे में बताया जाता है। कम जगह में ज्यादा मुनाफा कमाने की तकनीक भी सिखाई जाती है। रजनीश कहते हैं कि जिस तकनीक का खुद इस्तेमाल करता हूं, वही किसानों को भी सिखाता हूं।

आधुनिक तकनीक से मछली पालनः सरकार किसानों की आमदनी में इजाफा करने को परंपरागत खेती के साथ व्यावसायिक खेती के लिए उन्हें प्रेरित कर रही है। ऐसे में रजनीश ने भी कृषि भूमि पर व्यावसायिक खेती पर ध्यान दिया है। सालभर तालाब पानी से भरा रहता है। तालाब में वर्षा जल संचयन भी होता है। भूजल स्तर में सुधार हो रहा है। वह सरकार की जल सरंक्षण मुहिम में सहयोग कर रहे हैं। मछली पालन विधि के बारे में वह कहते हैं कि यह इग्लैंड की फिश फार्मिंग विधि है। इसमें पानी का कम इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बायोफ्लाक व रास तकनीक से कम से कम पानी व कम जगह पर आसानी से इस काम को किया जा रहा है। कम लागत में मुनाफा ज्यादा मिलता है।

अविभाजित पैतृक संपत्ति में नहीं दे सकते कब्जे का समादेश


इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अधिकारियों को भी संपत्ति का बंटवारा अधिकार नहीं।

जासं, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अविभाजित पैतृक संपत्ति के खास हिस्से पर कब्जा सौंपने के संबंध में मेंटीनेंस एंड वेलफेयर आफ पैरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत समादेश जारी नहीं किया जा सकता। अधिकारियों को भी संपत्ति का बंटवारा करने का अधिकार नहीं है। सिविल वाद दायर कर बंटवारा किया जा सकता है।

कोर्ट ने जिलाधिकारी प्रयागराज को याची की अर्जी तय करने का निर्देश देने से इन्कार करते हुए बंटवारा वाद दायर कर विवाद निपटाने का विकल्प सुझाया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने करछना निवासी जय प्रकाश तिवारी की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उसके पैतृक निवास में वह दो भाइयों के साथ रह रहा है। मकान का बंटवारा नहीं किया गया है और भाई उसके हिस्से का अतिक्रमण कर निर्माण करा रहे हैं। विवाद पर पुलिस ने धारा 107/116 के तहत चालान कार्यवाही की है। थानाध्यक्ष उसके कब्जे में जबरन हस्तक्षेप कर रहे हैं। वह वरिष्ठ नागरिक हैं। जिलाधिकारी उसकी अर्जी तय नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह याचिका दायर की गई थी।

फिल्मसिटी के कायाकल्प के लिए आगे बढ़ी उद्धव सरकार

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने मुंबई स्थित फिल्म सिटी के विकास के लिए एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट (ईओआइ) के आवेदन आमंत्रित किए हैं। पहले की तुलना में इस बार शुरुआत छोटे पैमाने पर हो रही है ताकि निवेशक रुचि दिखाएं और काम शुरू हो सके। महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. (एमएफएससीडीसी) की ओर से जारी ईओआइ में फिल्म सिटी की 22 एकड़ भूमि पर बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए फिल्म व मीडिया एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में अनुभव रखनेवाले विकासकर्ताओं से आवेदन मंगाए गए हैं। इन बुनियादी ढांचों में स्टूडियो फ्लोर्स, आउटडोर लोकेशन्स, पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाएं इत्यादि तैयार करने की इच्छा जताई गई है।

एमएफएससीडीसी की संयुक्त प्रबंध निदेशक आंचल गोयल के अनुसार 1977 में स्थापित फिल्म सिटी में 16 इनडोर स्टूडियो हैं, जबकि ओटीटी प्लेटफार्म आ जाने के बाद इनडोर व आउटडोर स्टूडियो की जरूरतें बढ़ गई हैं। फिल्मों में काम करने वाले ज्यादातर लोग मुंबई में रहते हैं। उन्हें नजदीक स्टूडियो की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए 80 और स्टूडियो तैयार करने की योजना बनाई है। इसके अलावा पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाएं तैयार की जाएंगी।

पिछली देवेंद्र फड़नवीस सरकार में एमएफएससीडीसी ने फिल्म सिटी के कायाकल्प की वृहद योजना तैयार की थी। 2,550 करोड़ की उस योजना के लिए दो बार ईओआइ के आवेदन आमंत्रित किए गए थे। पहली बार किसी ने रुचि ही नहीं दिखाई। दूसरी बार तीन कंपनियों ने रुचि दिखाई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी।

▸ जल्द ही 80 और स्टूडियो बनाने की तैयारी, एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट आमंत्रित

फड़नवीस सरकार में फिल्म सिटी के उपाध्यक्ष रहे अमरजीत मिश्र, उद्धव सरकार की पहल पर पुनः आमंत्रित किए जा रहे ईओआइ आवेदन पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि सिर्फ 22 एकड़ के लिए ही आवेदन क्यों आमंत्रित किए जा रहे हैं? इस सवाल पर आंचल गोयल का कहना कि फिल्म सिटी की कुल भूमि के सिर्फ 40 फीसद हिस्से पर ही विकास कार्य किया जा सकता है। पिछली योजना बहुत वृहद होने से ज्यादा लोगों ने उसमें रुचि नहीं दिखाई। अब 22 एकड़ में पहले चरण की शुरुआत हो रही है। इसमें सफलता के बाद अगले चरण की योजना बनाई जाएगी।

बता दें कि कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई आकर फिल्म जगत की कई शीर्ष हस्तियों से मुलाकात की थी। उन्होंने ग्रेटर नोएडा में 780 एकड़ पर फिल्म सिटी निर्माण का खाका भी निर्माताओं के सामने पेश किया था, जिसमें फिल्म निर्माण की सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। योगी की इस योजना के सामने आने के बाद कई सप्ताह तक यह एक राजनीतिक मुद्दा बना रहा।

पिछले बजट में वित्तमंत्री अजीत पवार ने फिल्मसिटी के विकास में विशेष रुचि दिखाते हुए इसके लिए बजट में न केवल विशेष प्रविधान किए, बल्कि पहले चरण के लिए ईओआइ के आवेदन भी मंगाए गए। आंचल गोयल के अनुसार पहले फिल्म सिटी का कुछ हिस्सा नो डेवलपमेंट जोन में आता था। नई सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर यह बंदिश खत्म कर दी। अब इस हिस्से पर भी विकास कार्य किया जा सकेगा।

खाली पड़ी अधिगृहीत जमीन वापस पाने का अधिकार नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि अधिगृहीत जमीन कब्जे में लिए जाने के बाद भू-स्वामी को वापस नहीं की जा सकती, भले ही वह उपयोग में नहीं ली जा रही हो। भू-स्वामी उसकी वापसी की मांग करने का हकदार नहीं है। सरकार चाहे तो जमीन का अधिग्रहण रद कर सकती है। जिलाधिकारी इस कार्यवाही में किसान को हुए नुकसान की भरपाई करेंगे। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ वर्षों पहले अधिगृहीत जमीन को खेती के लिए वापस करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है।

एक ही मुद्दे पर दोबारा याचिका दाखिल, 25 हजार हर्जाना

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ही मुद्दे पर दोबारा दाखिल याचिका को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करार देते हुए 25 हजार हर्जाने के साथ खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अधिगृहीत जमीन का कब्जा लेकर वर्षों पहले ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को सौंपा जा चुका है। ऐसे में जमीन की वापसी नहीं की जा सकती। याची का कहना था कि अधिगृहीत जमीन आबादी की है। उस पर स्कूल बना था जिसे ध्वस्त कर दिया गया और जमीन उपयोग में नहीं है। अदालत का कहना था कि सरकार ने यह कहा है कि जमीन पर कोई निर्माण नही है, इस तथ्य को चुनौती नहीं दी गई। याची की मांग अस्वीकार करने के राज्य सरकार के आदेश की चुनौती याचिका वापस ले ली गई थी। दोबारा याचिका दाखिल करने की छूट भी नहीं ली गई तो उसी मुद्दे पर फिर याचिका न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

यह आदेश हाई कोर्ट ने विजयपाल और चार अन्य की याचिका पर दिया है। अदालत ने कहा कि याची यह मांग नहीं कर सकता कि कुछ लोगों की जमीन वापस की गई है इसलिए उसकी भी वापस की जाय। अदालत का कहना था कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता के अधिकार में गलत व अवैध लाभ पाने का अधिकार शामिल नहीं है। याची की गौतमबुद्धनगर, दादरी के थापखेरा गांव स्थित जमीन का कई साल पहले पहले अधिग्रहण किया गया था। उसकी आपत्ति अस्वीकार कर दी गई। याचिका में उसका कहना था कि वह जाटव जाति का किसान है। इस जमीन के अलावा उसके पास दूसरी जमीन नहीं है। कुछ लोगों की जमीन वापस की गई है इसलिए उसकी भी वापस की जाय। कोर्ट ने कहा कि देरी से मांग के आधार पर ही याचिका खारिज होने योग्य है और किसी को गलत आदेश से जमीन वापस की गई है तो उस गलती का लाभ नहीं मांगा जा सकता।

फाइटर पायलट आशीष को हासीमारा वायुसेना स्टेशन की कमान

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल के हासीमारा वायुसेना स्टेशन में राफेल लड़ाकू विमानों की औपचारिक तैनाती से ठीक पहले अनुभवी फाइटर पायलट आशीष श्रीवास्तव को इस महत्वपूर्ण एयरबेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है।

कोलकाता में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी कर बताया कि एयर कमोडोर श्रीवास्तव ने हासीमारा वायुसेना स्टेशन के नए एयर आफिसर कमांडिंग (एओसी) के रूप में पदभार संभाल लिया है। चीन से लगी पूर्वी सीमा पर भारतीय वायुसेना के महत्वपूर्ण व रणनीतिक एयरबेस माने जाने वाले हासीमारा वायुसेना स्टेशन में राफेल आने का इंतजार हो रहा है। जुलाई माह में यहां औपचारिक रूप से राफेल के 101 स्क्वाड्रन की तैनाती होने वाली है। अंबाला के बाद यहां राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन होगा, जिसका नाम 101 फाल्कन्स आफ छम्ब एंड अखनूर दिया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि एयर कमोडोर श्रीवास्तव के पास मिराज व जगुआर समेत 18 प्रकार के लड़ाकू, परिवहन और प्रशिक्षक विमानों पर 5600 घंटे से अधिक के उड़ान का अनुभव है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि गलवन घाटी में भारत-चीन के बीच संघर्ष के मद्देनजर वर्तमान में हासीमारा वायुसेना स्टेशन अधिक महत्वपूर्ण हो गया है और इस एयरबेस के संचालन में श्रीवास्तव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। वायुसेना ने अंबाला और हासीमारा को 4.5 जनरेशन के राफेल विमानों के लिए 'मेन आपरेटिंग होम बेस' के तौर पर चुना है। पूर्वी सेक्टर में चीन के खिलाफ हासीमारा में राफेल की तैनाती भारतीय वायुसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

पोषक तत्वों वाली फसलों पर जोर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश में कुपोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों वाली खेती पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ फोर्टिफाइड यानी विभिन्न पोषक तत्वों से युक्त चावल का उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है ताकि कुपोषण से जूझ रहे क्षेत्रों में इनकी उपलब्धता बढ़ाई जा सके। ऐसी उपज के लिए पायलट प्रोजेक्ट का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और महिला व बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से इस परियोजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

कुपोषण का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश ने पहल की है। इन राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। देश में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है।

पौष्टिकता की खेती

फोर्टिफाइड राइस का उत्पादन कर कुपोषित लोगों को मुहैया कराया जाएगा। पोषक तत्वों से युक्त इन खाद्यान्नों का वितरण फिलहाल राशन प्रणाली, आंगनवाड़ी, मिड डे मील स्कीम आदि में किया जा रहा है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथारिटी आफ इंडिया (एफएसएसएआई) के सीईओ ने वित्त सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि आगामी 2024 के जनवरी महीने से राइस फोर्टिफिकेशन को वैधानिक बना दिया जाना चाहिए। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के माध्यम से अप्रैल, 2021 से आंगनवाड़ी और मिड डे मील स्कीम में फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू कर दिया है। इन दोनों योजनाओं के लिए एफसीआइ ने छह लाख टन से अधिक चावल की खरीद कर ली है, जिससे देश के सभी राज्यों में चल रही इन योजनाओं के लिए पोषक तत्वों से युक्त चावल का वितरण किया जा सकता है। सरकार ने चावल मिलों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें बैंकों से वित्तीय मदद मुहैया कराने का फैसला किया है। फोर्टिफाइड चावल तैयार करने में प्रति किलो 73 पैसे की अतिरिक्त लागत आती है। फिलहाल देश में फोर्टिफाइड चावल का उत्पादन बढ़कर 3.5 लाख टन पहुंच गया है। देश में 58 फीसद बच्चों और 53 फीसद गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की शिकायत पाई गई है। इसी तरह पुरुषों में भी एनीमिया के अलावा और अन्य तत्वों की कमी है। मोटे अनाज वाली फसलों को पोषक तत्वों वाली फसल कहा जाता है, जिसकी खेती का पूरा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने इन्हीं पोषक तत्वों वाली फसलों का वर्ष घोषित किया है। देश में इसके लिए सभी राज्यों के किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

15 जुलाई से भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों के लिए मालदीव वीसा आन अराइवल सेवा फिर से शुरू करने जा रहा है। लेकिन पर्यटकों को पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट देना होगा।

अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में गृहयुद्ध के आसार

शांति स्थापना में मुश्किल ▸ काबुल में शीर्ष अमेरिकी कमांडर ने जताई आशंका

कहा- समस्या का सैन्य समाधान न हो पाने पर करना पड़ा राजनीतिक समझौता



अफगानिस्तान में तैनात जनरल आस्टिन एस मिलर। एपी

काबुल, एएनआइ : अमेरिका के एक शीर्ष कमांडर ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो देशों की सेना वापसी के बाद वहां गृहयुद्ध हो सकता है।

अफगानिस्तान में तैनात जनरल आस्टिन एस मिलर ने काबुल में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि हमको सेना वापसी के बाद यहां गृहयुद्ध की स्थिति की आशंकाओं पर भी विचार करना चाहिए। यह अफगानिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है।

मिलर ने कहा कि अमेरिकी सेना के यहां 20 साल रहने के बाद यह माना गया है कि समस्या का सैन्य तरीके से समाधान नहीं निकाला जा सकता है। इसीलिए, एक राजनीतिक समझौता करना पड़ा। मिलर ने कहा कि तालिबान के हिंसा में विस्तार करने के कारण शांति स्थापित करना मुश्किल हो रहा है।

अमेरिका कुछ ही दिनों में सेना की वापसी का काम पूरा कर लेगा। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अब अफगानिस्तान में एक हजार सैनिक रहेंगे। जो एयर पोर्ट और काबुल स्थित अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। नाटो देशों के कितने सैनिक बने रहेंगे, इसकी अभी जानकारी नहीं दी गई है।

उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने 11 सितंबर तक अमेरिका और नाटो देशों की सेना की वापसी का एलान किया था।

आइएएनएस के अनुसार नाटो सेना में शामिल जर्मनी की सेना की अंतिम टुकड़ी 20 साल के बाद वापस लौट गई है। यह जानकारी जर्मनी के रक्षा मंत्री एनग्रेट क्रम्प ने दी।

अमेरिका ने कहा, तालिबान हिंसा छोड़ वार्ता करे

अफगानिस्तान में अमेरिका के राजदूत रोस विल्सन ने कहा है कि जिस तरह से तालिबान की देश के कई हिस्सों में हिंसा किए जाने की जानकारी मिल रही है। उसे यह सब रोककर वार्ता की टेबिल पर आना चाहिए।

सैन्य उपकरण और टैंक ले जाने वालों पर हवाई हमले होंगे

अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्री अब्दुल सत्तार मिर्जाकवाल ने तालिबान को चेतावनी दी है कि वह उसकी सुरक्षा बलों से कब्जाए गए सैन्य उपकरण और टैंक पाक ले जाना बंद करे। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों पर अब सीधे हवाई हमले किए जाएंगे। ये टैंक और उपकरण जाबुल प्रांत के रास्ते पाक पहुंचाए जा रहे हैं।

अफगानिस्तान में अब जनता भी उठा रही है हथियार

रायटर के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान से मुकाबला करने के लिए कई प्रांतों में नागरिक खुद ही हथियार लेकर खड़े हो रहे हैं। परवान प्रांत में दोस्त मोहम्मद ने बताया कि उनका अपना ग्रुप है। उन्होंने बताया कि सात साल का बच्चा भी यहां हथियार चलाना सीख रहा है।



अफगानिस्तान में परवान प्रांत के घोरबंद जिले में अग्रिम पंक्ति की ओर प्रस्थान करता अफगान कमांडो बल का बख्तरबंद काफिला। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगान सुरक्षा बलों पर अहम जिम्मेदारी आ गई है। रायटर

अमेरिका में धीमी पड़ी टीकाकरण की गति

वाशिंगटन, आइएएनएस : अमेरिका में कोरोना के डेल्टा वैरिएंट से टीकाकरण का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यहां इस वैरिएंट के भय से पिछले सप्ताह में वैक्सीन लगवाने वालों में 55.3 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है।

अमेरिका में 46.4 फीसद लोगों को पूरी तरह से कोरोना का टीका लगा दिया गया है। 54.2 फीसद आबादी को कम से कम एक टीका लग चुका है। कुछ राज्यों अलबामा, अरकंसास, लुसियाना, मिसिसीपी और टेनसी में टीकाकरण की गति कम है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि जो बाइडन के चार जुलाई तक 70 फीसद आबादी को टीके की एक खुराक देने का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकेगा। यहां पर डेल्टा वैरिएंट आने के बाद लोगों में दहशत है और वैक्सीन सेंटरों पर टीका लगवाना की गति कम हो गई है। सीडीसी के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 20 फीसद से ज्यादा मरीज डेल्टा वैरिएंट के सामने आ रहे हैं।

फ्रांस में भी डेल्टा वैरिएंट के मरीजों की संख्या 20 फीसद पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरन ने कहा है कि धीरे-धीरे डेल्टा वैरिएंट प्रभावी होता जा रहा है। यह चिंताजनक है।

रायटर के अनुसार आस्ट्रेलिया में कोरोना को लेकर हाई अलर्ट है। यहां पर कुल मरीजों की संख्या 30 हजार से ज्यादा हो गई है। आठ राज्यों और क्षेत्रों में लाकडाउन को बढ़ा दिया गया है।

उत्तर कोरिया भी संक्रमण की चपेट में : एएनआइ के अनुसार उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने कोरोना संक्रमण को रोकने में लापरवाही पर अधिकारियों को फटकार लगाई है। माना जा रहा है कि संक्रमण ने यहां पैर पसार लिए हैं।



इंडोनेशिया में वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। यहां अचानक आक्सीजन की मांग बढ़ गई है। राजधानी जकार्ता में बुधवार को आक्सीजन गैस सिलेंडर भरवाने के लिए दुकान के बाहर लगी लाइन। एएफपी

- पिछले सप्ताह में 55 फीसद से ज्यादा की गिरावट
- फ्रांस में डेल्टा के 20 फीसद मरीज हुए

नेपाल में तीसरी लहर का चेतावनी

नेपाल : एएनआइ के अनुसार तीसरी लहर की चेतावनी के बाद भी काठमांडू में सार्वजनिक परिवहन को अनुमति दे दी गई है।

बांग्लादेश : स्कूल-कालेज 31 जुलाई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं।

इंडोनेशिया : बच्चों में तेजी से कोरोना फैल रहा है। मई से अब तक बच्चों के मरने के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं।

रूस : राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के बाद भी देशव्यापी लाकडाउन से बचा जाएगा।

अमेरिकी संसद में भारत को सहायता देने का प्रस्ताव पारित

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने भारत में कोविड-19 के विनाशकारी प्रभाव को देखते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है और भारत को तत्काल सहायता देने के लिए बाइडन प्रशासन से आग्रह किया है। भारत और भारतीय मूल के अमेरिकियों पर हाउस कॉकस के डेमोक्रेटिक सह-अध्यक्ष, सांसद ब्रैड शेरमेन ने सांसद स्टीव चाबोट के साथ मिलकर प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव पेश किया था। सांसद शर्मन ने कहा, 'अमेरिका संकल्पबद्ध भारत के लोगों के साथ खड़ा है क्योंकि वे सामूहिक रूप से कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए काम करते हैं।' अमेरिका को दुनिया भर में अपने सहयोगियों के साथ काम करना चाहिए ताकि हर जगह वायरस को खत्म किया जा सके। चाबोट ने कहा, 'भारत और भारतीय अमेरिकियों पर हाउस कॉकस के सह-अध्यक्ष के रूप में, मुझे खुशी है कि इस कठिन समय के दौरान भारत के लिए सदन के समर्थन को व्यक्त करते हुए इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए मेरे सहयोगी एक साथ आए।' यह प्रस्ताव भारतीय अमेरिकियों और अमेरिकी फर्मों के इस समय के दौरान भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का समर्थन करने के प्रयासों को भी मान्यता देता है।

न्यूज गैलरी

अफगान से लगी सीमा पर दो पाकिस्तानी सैनिक मारे गए

पेशावर : पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर जिले में सीमा पार तालिबान के पूर्व गढ़ माने जाने वाले इलाके से आतंकियों की गोलीबारी में दो पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। यह गोलीबारी अफगानिस्तान से लगी सीमा की चेक पोस्ट पर हुई है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग के अनुसार दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में उत्तरी वजीरिस्तान में दता खेल में सुरक्षा चेकपोस्ट को निशाना बनाते हुए आतंकियों ने दो पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। बताया जाता है कि पाकिस्तानी सेना ने इस हमले का त्वरित जवाब दिया। पाकिस्तान ने लगातार अफगानिस्तानी सीमा से जारी हमलों का विरोध दर्ज किया है। (प्रेट्र)

भारतवंशी अमेरिकी महिला अमेरिका में न्यायाधीश नामित

वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारतवंशी अमेरिकी शालिना डी कुमार को ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आफ मिशिगन के संघीय न्यायाधीश पद के लिए नामित किया है। वह मिशिगन में पहली दक्षिण एशियाई मूल की न्यायाधीश होंगी। बुधवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आफ मिशिगन के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश शालिना ने 2007 से आकलैंड काउंटी सिक्स्थ सर्किट कोर्ट में सेवा दी है। जनवरी 2018 में मिशिगन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सर्किट कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। (प्रेट्र)

दुनिया के 10 सबसे तनावपूर्ण शहरों में कराची

कराची : पाकिस्तान के कराची शहर को रहने के लिए दुनिया के 10 सबसे तनावपूर्ण शहरों में चुना गया है। जियो न्यूज के मुताबिक जर्मनी की एक कंपनी वीएएवाइ की सूची में तनाव के 15 प्रमुख मानक रखे गए हैं। इसके तहत सुशासन, पर्यावरण, वित्त और सुरक्षा आदि को संकेतक बनाया गया है। इन्हीं बातों के आधार पर दुनिया के प्रमुख शहरों को इस सूची में रखने का क्रम तैयार किया गया है। यह शहर ना सिर्फ आकार के आधार पर बल्कि विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराने के आधार पर भी देखे जा रहे हैं। पाकिस्तानी शहर कराची सूची में 93वें स्थान पर है। (एएनआइ)

पाक की पनाह पाकर मजबूत हुए आतंकी अब उसी के लिए बने खतरा

इस्लामाबाद, एएनआइ : आतंकवादियों की फसल तैयार करने वाला पाकिस्तान अब इन्हीं के चंगुल में खुद फंस गया है। पांच हजार से ज्यादा आतंकी अब उसके लिए मुसीबत बन गए हैं।

इनका मकसद अफगानिस्तान के साथ ही पाक में भी शरिया आधारित एक कट्टरपंथी इस्लामी शासन स्थापित करना है। अफगानिस्तान में जैसे-जैसे तालिबान मजबूत हो रहा है। पाक में सक्रिय तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) भी मजबूत होता जा रहा है। अब तक अफगानिस्तान में इन आतंकवादी संगठनों की पाक से बराबर आवाजाही है। वहां पनाह लेकर अपनी ताकत बढ़ाते रहे हैं। अब तालिबान के साथ अन्य आतंकी संगठन मिलकर अफगानिस्तान के साथ ही पाक में भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहे हैं। डान अखबार के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने कहा है कि तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के पांच हजार लड़ाके उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। इनके पाकिस्तान की सीमा और अंदरुनी क्षेत्रों में लगातार हमले हो रहे हैं।

अखबार के अनुसार विदेश मंत्रालय का मानना है कि जैसे-जैसे तालिबान मजबूत हो रहे हैं, इनकी सक्रियता पाक सीमा पर बढ़ रही है। यह पाक के लिए, चिंता का कारण हो गए हैं। कुछ समय पहले पाक के मंत्री शेख राशिद उम्मीद जताई थी कि तालिबान टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों को उनके देश के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देने की अनुमति नहीं देगा।

विश्व बैंक ने पाकिस्तान को दिए 80 करोड़ डालर

वाशिंगटन डीसी, एएनआइ : विश्व बैंक ने पाकिस्तान में दो कार्यक्रमों के लिए 80 करोड़ अमेरिकी डालर (करीब 59.53 अरब रुपये) की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। पाकिस्तान सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के लिए कार्यक्रम चला रहा है और दूसरा कार्यक्रम सुरक्षित मानव निवेश को बढ़ावा देने के लिए है। इसी के साथ निकट भविष्य में पाकिस्तान का विदेशी ऋण बढ़ेगा क्योंकि अपने बकाया विदेशी ऋणों को चुकाने, अपने चालू खाते को वित्तपोषित करने और अपने विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करने के लिए हर साल अधिक से अधिक उधार लेने की उसकी मजबूरी है। विश्व बैंक की विज्ञप्ति में कहा गया कि 40 करोड़ अमेरिकी डालर का पाकिस्तान प्रोग्राम फॉर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी बिजली क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के उपायों पर केंद्रित है और कम कार्बन ऊर्जा के लिए देश के संक्रमण का समर्थन करता है। विश्व बैंक के टास्क टीम लीडर रिकार्ड लिडेन ने कहा, 'पाकिस्तान की वित्तीय चुनौतियों को हल करने के लिए बिजली क्षेत्र में सुधार महत्वपूर्ण है।' फोस्टर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए 40 करोड़ अमेरिकी डालर सेकेंड सिक्योरिंग ह्यूमन इन्वेस्टमेंट मानव पूंजी संचय के लिए बुनियादी सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए एक संघीय ढांचे का समर्थन करता है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को बेहतर बनाने, गरीबों के लिए आय सृजन के अवसरों को बढ़ाने और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

आस्ट्रेलिया विवि में चीन सरकार के दमन से परेशान चीनी छात्र

सिडनी, एपी : एक मानवाधिकार संगठन ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि चीनी सरकार और उसके समर्थकों ने आस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों में रह रहे लोकतंत्र समर्थक चीनी छात्रों की निगरानी की, उत्पीड़न किया और उन्हें धमकाया है। लेकिन आस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय इन छात्रों की शैक्षणिक आजादी की रक्षा करने में अक्षम रहे। बुधवार को रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में लोकतंत्र के समर्थक इन चीनी छात्रों को चीन सरकार की ओर से इतना अधिक धमकाया गया कि वह बुरी तरह से सहमे हुए हैं। यहां तक उनकी कक्षा के अन्य छात्रों से इन छात्रों की जानकारियां चीनी अधिकारियों तक पहुंचाई गई हैं।

ये चीनी छात्र इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि उन्होंने अपनी गतिविधियों और अभिव्यक्ति को सीमित कर लिया है। इन्हें डर है कि चीन में मौजूद उनके परिवार को परेशान किया जा सकता है। आस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं के मानवाधिकार संगठन का कहना है कि यह बहुत ही तकलीफदेह है कि यह छात्र अपने घर से दूर यहां एकदम अकेले पड़ गए हैं और इनके अधिकारों की रक्षा के लिए आस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं।

चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शताब्दी समारोह आज से

बीजिंग, प्रेट्र : चीन की कम्युनिस्ट पार्टी गुरुवार को पूरे 100 साल की हो जाएगी। करीब 72 साल से चीन की सत्ता में बनी कम्युनिस्ट पार्टी अब अगले सौ साल के लिए सत्ता और संगठन का खाका तैयार कर रही है। भूत और भविष्य की यही झांकी एक जुलाई से शुरू होने वाले पार्टी के शताब्दी समारोह में पेश की जाएगी। इस समारोह में चीन को सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करने और अगले सौ साल को चीन की सदी बनाने के तौर-तरीके जनता के सामने रखे जाएंगे।

शताब्दी समारोह में गुरुवार को सुबह राष्ट्रपति शी चिनफिंग का भाषण होगा। वह कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी हैं। अपने कार्यों से उन्होंने खुद को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग के बराबर ला खड़ा किया है। ताजिंदगी राष्ट्रपति बने रहने के लिए पार्टी और देश के संविधान में परिवर्तन करा लिया है। शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक राष्ट्रपति के भाषण का सरकारी चैनल लाइव प्रसारण करेंगे। इसी भाषण पर सबकी निगाह है और उसी का विश्लेषण होगा। चिनफिंग शताब्दी समारोह को भव्य तरीके से मनाने की पहले ही घोषणा कर चुके हैं। इसके जरिये चीन कोविड-19 महामारी पर विजय पाने का संदेश देगा। दुनिया को बताएगा कि वह इस महामारी को पीछे छोड़ चुका है। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया है कि समारोह के दौरान मिलिटरी परेड का कार्यक्रम रद कर दिया गया है। पहले यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि थ्येनआनमन चौक पर देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होगा। लेकिन दुनिया में चीन के खिलाफ बढ़ रही एकजुटता के मद्देनजर इस परेड को रद करना ही उचित समझा गया है।

मुख्य समारोह थ्येनआनमन चौक और स्थित ग्रेट हाल ऑफ पीपुल में होगा। यहां पर पार्टी और देश के लिए, अमूल्य योगदान के लिए 29 कार्यकर्ताओं को चिनफिंग पदकों से नवाजेंगे।



राष्ट्रपति शी चिनफिंग के भाषण पर सबकी निगाह, होगा लाइव प्रसारण

काला सागर में ब्रिटेन के युद्धपोत के साथ था अमेरिकी टोही विमान

मास्को, एपी : ब्रिटेन के युद्धपोत के काला सागर में घुसने को लेकर रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले सप्ताह 23 जून को ब्रिटेन की उकसाने वाली कार्रवाई नियोजित थी। इस युद्धपोत के साथ एक अमेरिकी टोही विमान भी था।

पुतिन ने कहा कि ब्रिटेन की इस हरकत को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है। उनका कहना था कि हाल ही में जब जेनेवा में बैठक हुई थी, तब एकदम उकसाने वाली कार्रवाई का क्या मतलब हो सकता है। रूस ने घटना को अपनी सीमा में घुसपैठ बताया है और इसमें अमेरिका के भी शामिल होने का आरोप लगाया। पुतिन ने कहा है कि इस युद्धपोत के साथ एक अमेरिकी टोही विमान भी था। जबकि ब्रिटेन ने कहा है कि रूस का दावा गलत है। उसे अपने युद्धपोत को अंतरराष्ट्रीय सीमा में ले जाने का अधिकार है। वैसे भी काला सागर का जल क्षेत्र यूक्रेन की सीमा में है, रूस में नहीं। ब्रिटेन ने यह भी कहा कि रूस ने उसके युद्धपोत पर कोई फायरिंग नहीं की, यदि भविष्य में ऐसा करने की हिमाकत की तो वह बमबारी करेगा।

▸ रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, उकसाने वाली कार्रवाई सुनियोजित



व्लादिमीर पुतिन की फाइल फोटो। जागरण आर्काइव

म्यांमार में सैन्य सरकार ने 23 सौ कैदी रिहा किए

यंगून, एपी : म्यांमार की सैन्य सरकार ने बुधवार को देश भर में करीब 23 सौ कैदियों को रिहा कर दिया। फरवरी में सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं और रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को हिरासत में ले लिया गया था। यंगून की इन्सेन जेल से बसें कैदियों को बाहर लेकर आईं। रिहाई के इंतजार में सुबह से ही कैदियों के परिवार के लोग और मित्र डेरा डाले बैठे थे।

यंगून रीजन जेल विभाग के प्रमुख जाव जाव ने जेल से 720 कैदियों के रिहा होने की पुष्टि की। दशकों से इसी जेल में राजनीतिक बंदियों को रखा जाता है। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि सभी कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को रिहा कर दिया गया है।

उप सूचना मंत्री मेजर जनरल जाव मिन तुन ने इससे पहले कहा था कि देश भर में करीब 23 सौ कैदियों को रिहा किया जाएगा। चीन की शिन्हुआ समाचार एजेंसी से उन्होंने कहा कि रिहा किए जाने वाले कैदियों में वे लोग हैं जिन्होंने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, लेकिन हिंसा में भाग नहीं लिया। उन्होंने अपराध नहीं किया और दंगे की अगुआई नहीं की। वकीलों और हिरासत में बंद रहे कुछ कार्यकर्ताओं के मित्रों ने रिहाई की पुष्टि की है।

▸ यंगून की इन्सेन जेल से बसें कैदियों को लेकर बाहर आईं

▸ कैदियों के परिवार और मित्र रिहाई के इंतजार में पहले से ही डाले थे डेरा



म्यांमार की सैन्य सरकार ने बुधवार को देशभर में करीब 23 सौ कैदियों को रिहा कर दिया। यंगून की जेल से रिहा होने के बाद एक व्यक्ति हाथ उठाकर खुशी व्यक्त करते हुआ। एपी

फ्लोरिडा में इमारत गिरने में मरने वालों की संख्या 12 हुई, 149 अभी लापता

फ्लोरिडा, रायटर : फ्लोरिडा के समुद्र किनारे बसे सर्फसाइड शहर में छह दिन पहले 12 मंजिला इमारत के ढहने के बाद राहत कार्य अभी भी चल रहा है। अब तक यहां मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। 149 लोग लापता हैं, लापता लोगों के बचने की संभावना बहुत कम रह गई है। पुलिस मलबे में शवों की तलाश कर रही है।

मियामी डेड काउंटी की मेयर डेनिएला लेविन कावा ने बताया कि राहत कार्य के दौरान एक मृत व्यक्ति का शव और मिला है। मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी इमारत के अचानक ढहने का पहला मामला है। इस इमारत को लेकर पहली बार 2018 में इंजीनियरिंग रिपोर्ट में कमी बताई गई थी। अप्रैल 2021 में इस इमारत में रहने वाले लोगों को आगाह भी किया गया था।

मौसम की मार

वैंकूवर में अब तक 134 लोगों की मौत, कनाडा के लिटन शहर में पारा 49.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूयार्क में राहत देने के लिए खुले सैकड़ों कूलिंग सेंटर



अमेरिका और कनाडा इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में तापमान 47.9 डिग्री सेल्सियस के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग कूलिंग सेंटरों की शरण में जा रहे हैं और सार्वजनिक फव्वारों का आनंद ले रहे हैं। एएफपी

कनाडा और अमेरिका में अब गर्मी बनी जानलेवा

वैंकूवर, एएफपी : कनाडा और अमेरिका के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में भीषण गर्मी ने सभी रिकार्ड ध्वस्त कर दिए। वैंकूवर में गर्मी मौत बनकर बरस रही है। यहां मरने वालों की संख्या 134 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका में भी मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। यहां लोगों को गर्मी से बचाने के लिए सैकड़ों कूलिंग सेंटर खोल दिए गए हैं।

कनाडा के वैंकूवर में एक दिन में 65 से ज्यादा लोग मारे गए। पुलिस विभाग का कहना है कि ये सभी मौत गर्मी के कारण हुई हैं। अब तक यहां 134 लोगों की मौत हो गई है। वैंकूवर के लोगों का कहना है कि गर्मी का कहर पहली बार देखा है। पुलिस और नगर निगम में गर्मी से मौत की लगातार सूचनाएं आ रही हैं। वैंकूवर से ढाई सौ किमी दूर ब्रिटिश कोलंबिया के शहर लिटन में 49.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

एपी के अनुसार अमेरिका के वाशिंगटन और ओरेगन में गर्मी से दर्जनों मौत हो गई हैं। बिजली की भारी मांग के कारण कुछ स्थानों पर ब्लैक आउट भी करना पड़ रहा है। सिएटल में 65 व 68 वर्ष की दो महिलाओं की मौत हो गई। वाशिंगटन के एवरेट में 51, 75 और 77 वर्ष के तीन पुरुष गर्मी से अपनी जान गंवा बैठे। ओरेगन में नर्सरी में काम करने वाले एक मजदूर की मौत हो गई।

न्यूयार्क भी लू की चपेट में

आइएएनएस के अनुसार न्यूयार्क शहर भी लू की चपेट में है। भयंकर गर्मी से लोगों को जान बचाना मुश्किल हो रहा है। यहां पर प्रशासन ने सैकड़ों कूलिंग सेंटर खोल दिए हैं। जहां लोगों को ठंडे वातावरण में रुकने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

घर में ही रहने की चेतावनी

न्यूयार्क के मेयर बिल डी ब्लेसिओ ने चेतावनी दी है कि लोग अपने घरों से न निकलें। अपने शरीर में पानी की कमी न होने दें। न्यूयार्क शहर के सामाजिक सेवा विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। नेशनल वेदर सर्विस ने गर्मी से बचने के लिए गाइड लाइन जारी की है।

राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि गर्मी को जलवायु परिवर्तन से जोड़ना गलत है। यह सिर्फ कल्पना है।

रायटर के अनुसार ओरेगन के सालेम में तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। पोर्टलैंड व अन्य क्षेत्रों में गर्मी के कारण रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा है। कुछ स्थानों पर रेल सेवाएं बंद कर दी गई हैं।

सौर ऊर्जा की दिशा में भारत की कोशिशें एक उदाहरण : प्रिंस चार्ल्स

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने कहा कि सौर ऊर्जा की दिशा में भारत की कोशिशें पूरी दुनिया के लिए, एक उदाहरण है और शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले भविष्य की तरफ कदम तेज करने के लिहाज से प्रकृति आधारित एवं प्रौद्योगिकी से प्रेरित समाधानों के लिए वैश्विक तलाश में भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

ब्रिटेन की राजगद्दी के 72 वर्षीय उत्तराधिकारी और पर्यावरण कार्यकर्ता चार्ल्स ने 'इंडिया ग्लोबल फोरम सेशन ऑन क्लाइमेट एक्शन' में अपने विशेष संबोधन के दौरान भारतीय उद्यमियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से सस्टेनेबल मार्केट्स इंडिया काउंसिल में शामिल होने की अपील की। सस्टेनेबल मार्केट्स इंडिया काउंसिल जलवायु संबंधी लक्ष्यों की दिशा में गति को बढ़ाने के लिए सतत निवेश की मांग करने के उद्देश्य से गठित किया गया है।

चार्ल्स ने कहा, 'भारत की वैश्विक पहुंच और मजबूत निजी क्षेत्र के साथ, मुझे लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण रास्ते हैं जहां हम अपनी कोशिशों को तेज करने और एक ज्यादा सतत भविष्य के निर्माण की खातिर मिलकर काम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस बदलाव में मदद करने के लिए निजी पूंजी के प्रवाह को तेज करने पर ध्यान देने की जरूरत है।'

उन्होंने कहा, 'मुझे पता है कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा, खासकर सौर ऊर्जा तेजी से आधार बना रहा है और यह बाकी दुनिया के लिए एक शानदार उदाहरण है।' इंडिया इंक ग्रुप ने दो दिन (30 जून-एक जुलाई) के इस सम्मेलन का आयोजन किया है। इंडिया इंक ग्रुप लंदन की एक मीडिया कंपनी है।

▸ इंडिया ग्लोबल फोरम सेशन ऑन क्लाइमेट एक्शन में विशेष संबोधन

▸ इंडिया इंक ग्रुप ने दो दिनी सम्मेलन का किया है आयोजन

बार्सिलोना से आजाद मेसी, करार खत्म

मैड्रिड, एपी : सुपरस्टार स्ट्राइकर लियोन मेसी का स्पेनिश फुटबाल क्लब बार्सिलोना के साथ करार बुधवार को खत्म हो गया और यह खिलाड़ी और क्लब दोनों अलग हो गए। हालांकि खिलाड़ी और क्लब की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान मेसी के भविष्य या क्लब के साथ उनके आगे जुड़ने को लेकर नहीं आया है। 34 साल के अर्जेंटीनी खिलाड़ी मेसी अभी कोपा अमेरिका में खेल रहे हैं। कई रिपोर्टों में यह कहा जा रहा है कि वह क्लब के साथ अगले दो साल के लिए के लिए नया करार करने के करीब हैं तो वहीं, पेरिस सेंट जर्मेन और इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी भी उनके साथ करार कर सकते हैं। वह एक जुलाई से किसी भी क्लब के साथ नया करार करने के लिए स्वतंत्र हैं। 2019-20 सत्र के बाद से मेसी का भविष्य अंधेरे में रहा है क्योंकि उन्होंने उस सत्र में क्लब को छोड़ने के लिए कहा था लेकिन, क्लब ने मना कर दिया था। इसके बाद काफी विवादों के बाद वह क्लब में रुक गए थे। वह 2004 में बार्सिलोना के साथ जुड़े थे और तब से अभी तक इस क्लब के लिए खेल रहे थे। उन्होंने क्लब के लिए 778 मैचों में 672 गोल दागे हैं जबकि 288 मैचों में उन्होंने गोल करने में मदद की है।

खराब मैचों को भुला यूक्रेन ने स्वीडन को चौंकाया

ग्रुप स्तर में खराब प्रदर्शन करने वाले यूक्रेन ने मजबूत स्वीडन को 2-1 से हराया



गोल करने के बाद जोश में आर्तेम डोवबिक ● रायटर

ग्लास्गो, एपी : स्थानापन्न खिलाड़ी आर्तेम डोवबिक के अतिरिक्त समय के इंजुरी समय में दागे गोल की बदौलत यूक्रेन ने मंगलवार को यहां स्वीडन को 2-1 से हराकर यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

यूक्रेन का ग्रुप स्तर पर में प्रदर्शन खराब रहा था और वह दो मैच हारा था और सिर्फ एक में जीत दर्ज करा पाया था जबकि स्वीडन ने दो जीत दर्ज की थी जिसमें पोलैंड पर जीत भी शामिल है और एक मैच उसने ड्रा खेला था। प्री क्वार्टर फाइनल में जब दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो स्वीडन को दावेदार बताया जा रहा था लेकिन, यूक्रेन ने अपने खराब मैचों को भुलाकर अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया।

मैच में यारमोलमेंको ने गोल पोस्ट के पास गेंद ओलेक्सांद्र जिनचेंको की तरफ भेज जिन्होंने 27वें मिनट में यूक्रेन को बढ़त दिलाने में कोई गलती नहीं की। जब पहले हाफ में दो मिनट का समय शेष था जब एमिल फोर्सबर्ग ने स्वीडन को बराबरी दिला दी। पहले हाफ में स्कोर 1-1 से बराबर रहा। दूसरे हाफ में स्वीडन की टीम ने अधिक आक्रामक रुख अपनाया और अधिक मौक बनाए। फोर्सबर्ग के शाट गोल पोस्ट और क्रासबार से टकराए जिससे स्वीडन की टीम ने बढ़त बनाने का मौका गंवा दिया। इसके बाद अतिरिक्त समय लिया गया। 98वें मिनट में फाउल के कारण स्वीडन के डेनिलसन को रेड कार्ड मिला और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। टीम को शेष मैच 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। इसके बाद यूक्रेन ने दबदबा बनाना शुरू किया और जब लग रहा था कि मैच का नतीजा पेनाल्टी शूटआउट से निकाला जाएगा तब डोवबिक (120+1वां मिनट) ने इंजुरी समय में गोल दागकर यूक्रेन की जीत सुनिश्चित कर दी।

गोल

यूक्रेन 2	स्वीडन 1
ओलेक्सांद्र जिनचेंको (27वां मिनट)	एमिल फोर्सबर्ग (43वां मिनट)
आर्तेम डोवबिक (120+1वां मिनट)	

क्वार्टर फाइनल लाइन-अप

स्विट्जरलैंड	बनाम	स्पेन
बेल्जियम	बनाम	इटली
चेक गणराज्य	बनाम	डेनमार्क
इंग्लैंड	बनाम	यूक्रेन

नोट : क्वार्टर फाइनल की शुरुआत शुक्रवार से होगी

गेंद रखी

55% 45%

यूक्रेन		स्वीडन
02	यलो कार्ड	02
00	रेड कार्ड	01
03	आफ साइड	02
02	कार्नर किक	06
02	गोलकीपर बचाव	02

जोकिम को यादगार विदाई नहीं दे पाए जर्मनी के खिलाड़ी



इंग्लैंड और जर्मनी का मैच देखने पहुंचे भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत ने प्रशंसक के साथ फोटो खींची ● ट्विटर

बर्लिन, आइएएनएस : जर्मनी को यूरो कप में इंग्लैंड के हाथों हार झेलनी पड़ी और उसके खिलाड़ी अपने कोच जोकिम लो को संतोषजनक विदाई देने में असफल रहे। जोकिम का टीम के साथ करार खत्म हो गया। जोकिम लो ने कहा, 'काफी निराशा हुई। ड्रेसिंग रूम में शांति थी और सभी लोग निराश थे। मुझे भले ही निराशा हुई लेकिन, टीम के साथ इतने लंबे समय तक रहने के बाद मुझे खालीपन लग रहा है। इसके बाद शायद मेरे लिए एक नई चुनौती इंतजार कर रही है।' उनके नेतृत्व में टीम ने 198 मैच में से 124 जीते और वह देश के सबसे सफल राष्ट्रीय कोच में से एक बने।

साउथगेट के लिए यादगार पल : यह मैच इंग्लिश कोच गेरेथ साउथगेट के लिए भावनात्मक रहा। 25 साल पहले ओल्ड वेंबले स्टेडियम में साउथगेट पेनाल्टी पर गोल करने से चूक गए थे जिससे इंग्लैंड यूरो 1996 के फाइनल में जगह नहीं बना पाया था।

इंग्लैंड सीरीज से बाहर हो सकते हैं चोटिल गिल

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं। उनकी जगह स्टैंडबाई अभिमन्यु ईश्वरन मुख्य टीम में आ सकते हैं।

बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने कहा, 'यह संभावना है कि गिल टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं। उनकी चोट गंभीर है और हमें कई चीजें जाननी हैं।' यह माना जा रहा है कि पंजाब का यह बल्लेबाज पिंडली या हैमस्ट्रिंग (घुटने के पीछे की नस) की चोट से परेशान है जिसे ठीक होने में काफी समय लग सकता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें यह चोट कब और कैसे लगी। उनकी इस चोट पर इंग्लैंड में उनके साथ मौजूद फिजियो नितिन पटेल और स्ट्रेंथ व कंडिशनिंग कोच सोहुम देसाई नजर रख रहे हैं। गिल का प्रदर्शन पिछली कुछ पारियों में खराब रहा है। पिछली चार टेस्ट पारियों में वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं। अगर गिल बाहर हो जाते हैं तो मयंक अग्रवाल और लोकेश राहुल भी सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल हैं। ईश्वरन सिर्फ स्टैंडबाई सूची से उनकी जगह आएंगे।

घास पर गिरते-फिसलते जोकोविक ने दर्ज की जीत

विंबलडन, एपी : कुछ ही दिन पहले 13 जून को लाल बजरी के क्ले कोर्ट में फ्रेंच ओपन किंग बने नोवाक जोकोविक जैसे ही ग्रास कोर्ट पर खेलने आए तो वह कई बार गिरते-फिसलते नजर आए। हालांकि उन्होंने घास पर संतुलन बनाए रखते हुए दूसरे दौर में दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन पर सीधे सेटों में 6-3, 6-3, 6-3 से जीत दर्ज की। लेकिन इस जीत के बाद वह खुश नजर नहीं आए बल्कि अपना गुस्सा ग्रास कोर्ट पर कई बार निकाला।

विंबलडन के ग्रास कोर्ट पर दरअसल घास से निकलने वाली नमी सूख नहीं पा रही है जिसके चलते मैच खेलने पर जोकोविक कई बार फिसलते हुए गिरे, हालांकि भाग्यशाली रहे कि वह इस दौरान चोटिल नहीं हुए। जैसे कि पहले ही फिसलने के कारण सेरेना विलियम्स और एड्रियन मनारिनो चोटिल होकर बाहर हो चुके हैं। ऐसे में जोकोविक की शिकायत पर आल इंग्लैंड लान टेनिस क्लब के सदस्य टिम हेनमन ने कहा कि कोर्ट हर साल की तरह ही इस साल तैयार किए गए हैं। उसमें कोई कमी नहीं है। हालांकि खेलने की विपरीत स्थितियां होने के बावजूद जोकोविक ने मैच में अपनी पकड़ बनाए रखी। एंडरसन के खिलाफ मैच में उन्होंने कभी भी ब्रेक पाइंट का सामना नहीं किया और सिर्फ छह बेजा गलतियां ही की। इस तरह साल 2018 के विंबलडन फाइनल मैच की याद दिलाते हुए जोकोविक ने एक बार फिर एंडरसन को एकतरफा अंदाज में हराया। जोकोविक की यह विंबलडन में लगातार 16वीं जीत है। जोकोविक अपने करियर के 20वें ग्रैंडस्लैम खिताब की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वह ऐसा करते हैं तो इस मामले में 20-20 ग्रैंडस्लैम खिताब जीत में रोजर फेडरर और राफेल नडाल की बराबरी कर लेंगे। वहीं पुरुषों के एक और मुकाबले में पूर्व यूएस ओपन उप विजेता जापान के केई निशिकोरी ने आस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपिरिन को 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर 100वीं ग्रैंडस्लैम मैच जीत दर्ज की। स्पेन के पाब्लो एंडुजर ने पसली की चोट के कारण दूसरे दौर का मैच खेलने से मना कर दिया, जिससे डेनिस शापोवालोव ने तीसरे दौर में जगह बना ली। वहीं 15 जून को संपन्न हुए हाले ओपन के फाइनल मुकाबले में जापानी खिलाड़ी जैन लेनार्ड स्ट्रूफ से हारने वाले डेनिल मेदवेदेव ने इस खिलाड़ी को पहले दौर में चार सेटों तक चले मैच में 6-4, 6-1, 4-6, 7-6 से हराया।

महिला वर्ग में फ्रांस की एलिजे कोर्नेट ने पहले दौर में प बियांका आंद्रेस्कू को हराकर उलटफेर किया। कोर्नेट ने दो हफ्तों में दूसरी बार आंद्रेस्कू को हराया। उन्होंने पूर्व अमेरिकी चैंपियन आंद्रेस्कू की पांच बार सर्विस तोड़ी और कनाडा की इस खिलाड़ी को 6-2, 6-1 से हराया।

रोमांचक टाई ब्रेकर में जीते किर्गियोस

विंबलडन, रायटर : टेनिस जगत में हमेशा कुछ न कुछ अलग करने वाले आस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस ने अपने पहले मैच में ही दर्शकों के दिल की धड़कनों को थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। मैच के दौरान अंतिम सेट में दर्शकों को शानदार टाई ब्रेकर देखने को मिला। किर्गियोस ने फ्रांस के यूगो हंबर्ट के खिलाफ पांच सेट तक चले मैच को 6-4, 4-6, 3-6, 6-1, 9-7 से अपने नाम किया। मैच के चार सेट के बाद बारिश ने खलल डाल दिया। जिस समय स्कोर 6-4, 4-6, 3-6, 6-1, 3-3 पर था। इस कारण खिलाड़ियों को दिन के अंत में कोर्ट नंबर एक में ले जाया गया, जिसकी छत बंद थी। दर्शक भी अंत तक बने रहे। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर 3-3 से आगे अंतिम सेट का खेल शुरू हुआ और इस रोमांचक टाई ब्रेकर में किर्गियोस ने 9-7 से अंतिम सेट में बाजी मारते हुए दूसरे दौर में जगह बना ली।

घास बनी सेरेना-मनारिनो के बाहर होने की वजह

विंबलडन : दुनिया के एकमात्र ग्रास कोर्ट ग्रैंडस्लैम के शुरुआती चरण में ही अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स फिसलकर चोटिल हो गईं और उन्हें बाहर होना पड़ा। इससे सेरेना की आखों में आंसू आ गए। विंबलडन के सेंटर कोर्ट में सेरेना उसी जगह पर फिसली थीं जहां रोजर फेडरर के सामने मैच खेल रहे एड्रियन मनारिनो चोटिल हुए थे। मैच के बाद फेडरर ने कहा था कि बारिश होने के कारण कोर्ट की छत बंद है और घास नम हो रही है। जिससे हमें कोर्ट पर काफी संभलकर खेलना होगा। विंबलडन होने से पहले हर साल नई घास लगाई जाती है जिससे यह हरी-भरी नजर आती है। क्लब प्रमुख नील स्टबली ने कहा, 'इस समय कोर्ट की घास बिल्कुल नई और मुलायम है। यह कोई नई बात नहीं है।'



मैच जीतने के बाद खुश नोवाक जोकोविक ● एएफपी

धौनी करते हैं युवाओं का मार्गदर्शन : भुवी

नई दिल्ली, एएनआइ : श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम के उप कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने बुधवार को पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को याद किया। उन्होंने कहा कि धौनी हमेशा युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं और इसके लिए हमेशा तैयार भी रहते हैं। भुवनेश्वर ने उस एक पोस्ट को याद किया जब उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर धौनी के साथ एक तस्वीर पोस्ट की थी। भुवी ने धौनी के संन्यास के ठीक एक दिन बाद यानी 16 अगस्त 2020 को इंटरनेट मीडिया पर धौनी के साथ एक फोटो पोस्ट की थी।

बीसीसीआइ द्वारा शेयर एक वीडियो में भुवनेश्वर ने बताया कि धौनी क्यों उनके लिए हमेशा खास होंगे। वीडियो में भुवनेश्वर ने कहा, 'यह तस्वीर मैंने तब पोस्ट की थी जब माही भाई ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। हर कोई जानता है कि वह किस तरह के खिलाड़ी थे, लेकिन वह किस तरह के इंसान है इसलिए मैंने उसके लिए कुछ पोस्ट किया था। अगर आप धौनी के बारे में किसी से भी बात करते हैं, तो सभी आपको बताएंगे कि वह (धौनी) कितने मददगार हैं। वह हमेशा सभी युवाओं को मार्गदर्शन देते हैं।'

खेल रत्न के लिए मिताली और अश्विन के नाम की सिफारिश

नई दिल्ली, प्रेट्र : बीसीसीआइ ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के लिए महिला क्रिकेट की दिग्गज खिलाड़ी मिताली राज और शीर्ष स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के नाम की सिफारिश करने का फैसला किया है। अर्जुन पुरस्कार के लिए बोर्ड सीनियर बल्लेबाज शिखर धवन, लोकेश राहुल और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम भेजेगा।

वहीं अन्य खेलों में टेबल टेनिस फेडरेशन ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए अचिंत शरत कमल जबकि द्रोणाचार्य के लिए कमल के कोच सौम्यदीप राय का नाम भेजा है। जबकि अर्जुन पुरस्कार के लिए सुतिथा मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी व मानव ठक्कर का नाम शामिल हैं। तीरंदाजी संघ ने खेल रत्न के लिए ज्योति कुमारी और अर्जुन पुरस्कार के लिए मुस्कान किरार के नाम भेजे हैं।

निशानेबाजी : खेल रत्न के लिए अंकुर मित्तल और अंजुम मोदगिल, अर्जुन पुरस्कार के लिए इलावेनिल व अभिषेक वर्मा के नाम भेजे हैं।

एथलेटिक्स : खेल रत्न पुरस्कार के लिए नीरज चोपड़ा का नाम भेजा है।

गोल्फ : खेल रत्न के लिए शुभंकर शर्मा जबकि अर्जुन पुरस्कार के लिए उदयन माने, राशिद खान और दीक्षा डागर का नाम भेजा है।

फुटबाल : खेल रत्न के लिए सुनील छेत्री और अर्जुन पुरस्कार के लिए बाला देवी का नाम ।

कुश्ती : भारतीय कुश्ती महासंघ ने अर्जुन पुरस्कार के लिए रवि दहिया, दीपक पूनिया, अंशु मालिक और सरिता मोर का नाम भेजा गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए विक्रम कुलदीप मलिक और सुजीत मान का नाम भेजा गया है।

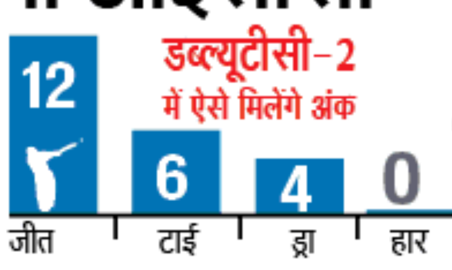


मिताली राज ● फाइल फोटो, ट्विटर

अंक प्रणाली को सरल बनाने की कोशिश करेगा आइसीसी

नई दिल्ली, प्रेट्र : आइसीसी दूसरे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) चक्र के दौरान अंक प्रणाली को सरल बनाने की कोशिश में है। डब्ल्यूटीसी के दूसरे चक्र की शुरुआत भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ होगी।

आइसीसी के अंतरिम सीईओ ज्योफ अलार्डिस ने इसी महीने कहा था कि अंक प्रणाली में बदलाव किया जाएगा। आइसीसी बोर्ड के सदस्य ने कहा, 'पहले प्रत्येक सीरीज के समान 120 अंक होते थे, फिर चाहे यह दो टेस्ट की सीरीज हो या पांच टेस्ट की। अगले चक्र में प्रत्येक मैच के समान अंक होंगे- अधिकतम 12 प्रति मैच। टीमों ने मैच खेलकर जो अंक हासिल किए हैं, उनके प्रतिशत अंकों के आधार पर टीमों की रैंकिंग तय होगी।' आगामी हफ्तों में आइसीसी के मुख्य कार्यकारियों की समिति बैठक में अंक प्रणाली में बदलाव को स्वीकृति दी जानी है। लक्ष्य यह है कि अंक प्रणाली को सरल बनाने का प्रयास किया जाए और किसी भी समस्य तालिका में टीमों की सार्थक तुलना की जा सके, फिर भले ही उन्होंने अलग संख्या में मैच और सीरीज क्यों नहीं खेली हो।' जून 2023 में खत्म होने वाले डब्ल्यूटीसी के दूसरे चक्र में भारत-इंग्लैंड सीरीज के अलावा इस साल होने वाली एशेज सीरीज ही पांच मैचों की एकमात्र सीरीज होगी। सभी नौ टीमों में से प्रत्येक टीम कुल छह सीरीज खेलेंगी जिसमें से तीन स्वदेश और तीन विरोधी के मैदान पर होंगी जैसा कि पिछले सत्र में भी हुआ।





डब्ल्यूटीसी-2 (2021-2023) के तहत होने वाली सीरीज नोट : ब्रैकेट में मैच हैं।

टीमें (मैच)	घरेलू सीरीज	विदेश में खेली जाने वाली सीरीज
आस्ट्रेलिया (18)	इंग्लैंड (03)-वेस्टइंडीज (02)-दक्षिण अफ्रीका (03)	पाकिस्तान (02)- श्रीलंका (02)- भारत (04)
बांग्लादेश (12)	पाकिस्तान (02)-श्रीलंका (02)-भारत (02)	न्यूजीलैंड (02)- दक्षिण अफ्रीका (02)- वेस्टइंडीज (02)
इंग्लैंड (22)	भारत (05)-न्यूजीलैंड (03)- दक्षिण अफ्रीका (03)	आस्ट्रेलिया (05)-वेस्टइंडीज (03)- पाकिस्तान (03)
भारत (19)	न्यूजीलैंड (02)- श्रीलंका (03)- आस्ट्रेलिया (04)	इंग्लैंड (05)- दक्षिण अफ्रीका (03)- बांग्लादेश (02)
न्यूजीलैंड (13)	बांग्लादेश (02)- दक्षिण अफ्रीका (02)- श्रीलंका (02)	भारत (02)-इंग्लैंड (03)-पाकिस्तान (02)
पाकिस्तान (13)	आस्ट्रेलिया (02)- न्यूजीलैंड (02)- इंग्लैंड (03)	वेस्टइंडीज (02)-बांग्लादेश (02)- श्रीलंका (02)
दक्षिण अफ्रीका (15)	भारत (03)- बांग्लादेश (02)- वेस्टइंडीज (02)	न्यूजीलैंड (02)-इंग्लैंड (03)- आस्ट्रेलिया (03)
श्रीलंका (13)	आस्ट्रेलिया (02)- पाकिस्तान (02)- वेस्टइंडीज (02)	बांग्लादेश (02)-भारत (03)- न्यूजीलैंड (02
वेस्टइंडीज (13)	पाकिस्तान (02)- इंग्लैंड (03)- बांग्लादेश (02)	दक्षिण अफ्रीका (02)- श्रीलंका (02)- आस्ट्रेलिया (02)

केन फिर शीर्ष पर, कोहली चौथे स्थान पर बरकरार

दुबई, प्रेट्र : न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में फिर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। तीस साल के विलियमसन ने भारत के खिलाफ कम स्कोर वाले फाइनल की दो पारियों में क्रमशः 49 और नाबाद 52 रन बनाए जिससे उनके 901 अंक हो गए हैं और उन्होंने स्टीव स्मिथ (891 अंक) पर 10 अंक की बढ़त बना ली।

भारतीय कप्तान विराट कोहली चौथे स्थान पर बरकरार हैं जबकि रोहित शर्मा छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। दो हफ्ते पहले स्मिथ कीवी बल्लेबाज विलियमसन को पछाड़कर रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए थे लेकिन, न्यूजीलैंड के कप्तान ने फिर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। काइल जेमिसन गेंदबाजी रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 13वें स्थान पर पहुंच गए। आलराउंडरों की सूची में एक हफ्ते शीर्ष पर रहने के बाद भारत के रवींद्र जडेजा दूसरे स्थान पर खिसक गए। वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर एक बार फिर शीर्ष पर हैं।

वहीं आइसीसी की टी-20 रैंकिंग में वेस्टइंडीज के बायें हाथ के सलामी बल्लेबाज एविन लुइस दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी-20 में 35 गेंद में 71 रन की पारी खेलने के बाद तीन स्थान के फायदे से 10वें स्थान पर पहुंच गए।

गेंदबाजों की सूची में इंग्लैंड के क्रिस जोर्डन पांच स्थान के फायदे से 11वें, मार्क वुड 11 स्थान के फायदे से 14वें, सैम कुर्रन 62 स्थान के फायदे से 39वें और डेविड विली 23 स्थान के फायदे से 51वें स्थान पर हैं। श्रीलंका के वानिंदु हसारंगा पांच स्थान के फायदे से पांचवें और दुष्मंत चमीरा 43वें स्थान पर हैं।

ओलंपिक में दर्शकों के आने पर लग सकती है पाबंदी

टोक्यो, रायटर : टोक्यो ओलंपिक को शुरू होने में एक महीने से भी कम का समय बचा है। इसी बीच जापानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि टोक्यो और अन्य क्षेत्रों में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए जारी अर्ध-आपातकाल को एक सप्ताह या एक माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि दर्शकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके स्टेडियम में आने पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। जापान के कई क्षेत्रों में इस समय अर्ध-आपातकाल जारी है, जो 12 जुलाई को समाप्त जो जाएगा। हालांकि अब सरकार इसको आगे तक भी बढ़ा सकती है।

श्रीहरि नटराज ने क्वालीफाई किया : भारतीय तैराक श्रीहरि नटराज ने बुधवार को टोक्यो ओलंपिक में आधिकारिक रूप से जगह बनाई जब खेल की वैश्विक संचालन संस्था फिना ने रोम में सेटे कोली ट्राफी में पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में उनके ए क्वालीफिकेशन स्तर को स्वीकृति दी।

दुती ने हासिल किया ओलंपिक टिकट : भारत की फर्राटा धावक दुती चंद ने इस साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए टिकट हासिल कर लिया है। दुती ने विश्व रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक खेलों का टिकट कटाया है। दुती ने 100 मीटर और 200 मीटर दोनों स्पर्धाओं में टिकट हासिल किया है। 100 मीटर में 22 स्थान खाली थे तो वहीं 200 मीटर में 15 स्थान खाली थे। ऐसे में दुती ने दोनों स्पर्धाओं का टिकट हासिल कर लिया है।

चोट को चित्त करके फिर 'पहलवान' बने रवि

पदक के दावेदार

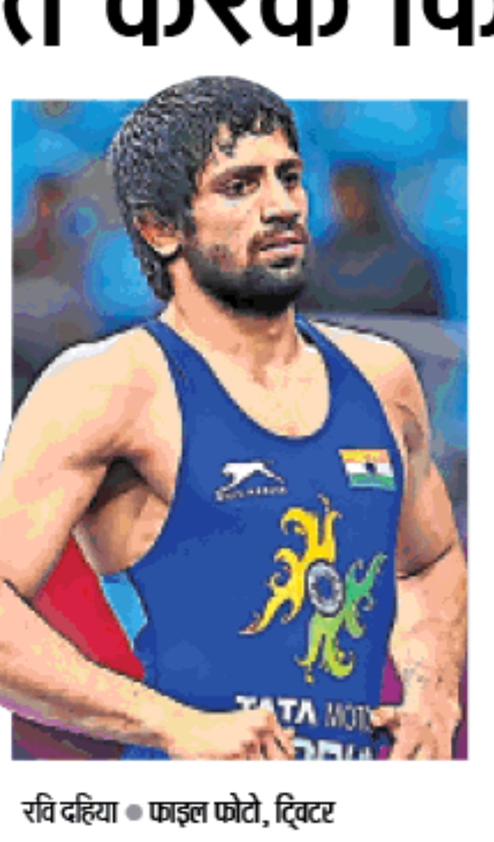
TOKYO 2020 — 22 दिन शेष

अनिल भारद्वाज ● गुरुग्राम

टोक्यो ओलंपिक में 57 किग्रा भारवर्ग में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया दुनियाभर के 15 पहलवानों के बीच पदक के सबसे मजबूत दावेदार हैं। उनकी दो वर्ष की कड़ी मेहनत ने उन्हें पदक के करीब पहुंचा दिया। बात वर्ष 2015 की है जब जूनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान वह चोटिल होकर अखाड़े से दूर हो गए थे। तब उन्हें लगा कि सबकुछ बर्बाद हो गया। उन्हें तीन साल अखाड़े से दूर रहना पड़ा। वो तीन साल उनके लिए बेहद मुश्किल रहे। जब-जब कहीं प्रतियोगिताएं होती थीं तो उनका मन कचोटता था।

रवि का मानना है कि वर्ष 2018 में चोट से उबरने के बाद जब अखाड़े में लौटा तो लगा कि शायद पहले वाले दिन नहीं आएंगे। उस समय मेरे सामने एक लक्ष्य था टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल करना। उसे पाने के लिए मैंने स्वयं को समर्पित कर दिया। इसके लिए मेरे पास दो वर्ष थे। उस दौरान मैंने ना सिर्फ कड़ी मेहनत से वापसी की बल्कि भारत के उन पहलवानों की कतार में आ खड़े हुआ जो टोक्यो ओलंपिक की टिकट हासिल करने की लाइन में थे। रवि ने कहा कि जब मैंने टोक्यो का टिकट हासिल किया तब ही ओलंपिक में पदक हर हाल में जीतने का लक्ष्य बना लिया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं पदक के करीब हूं।

रवि उन दिनों को याद करते हैं जब वह 8-9 साल की उम्र में अखाड़े में उतरे थे। उन्होंने कहा कि मेरे गांव नाहरा-नाहरी में कुश्ती का माहौल शुरू से रहा है और कई पहलवान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेले भी हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर अपना लक्ष्य बनाया। मेरे पिता पिता किसान है। उन्हें भी कुश्ती को बहुत शौक था। पिता चाहते थे कि मैं पहलवान बनकर देश का नाम रोशन करूं। बस इसके बाद गांव के मिट्टी के अखाड़े में कुश्ती शुरू कर दी और उसके बाद मुझे 2007 में दिल्ली छत्रसाल स्टेडियम में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि छत्रसाल में आने के बाद 2013 में सब जूनियर एशियन चैंपियनशिप में खेलने का मौका मिला और रजत जीता। यहीं से लगा कि मैं देश का नाम रोशन कर सकता हूं। फिर वर्ष 2015 में जूनियर एशियन चैंपियनशिप में खेलने का मौका मिला, तो स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहा। यहां पर सेमीफाइनल मुकाबले में चोट लग गई थी लेकिन मैं स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहा था। इसके बाद तीन साल अखाड़े से दूर रहना पड़ा। रवि अब तक की सफलता का श्रेय महाबली सतपाल पहलवान को देते हैं। उनकी सलाह व प्रशिक्षण की बदौलत उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है।



रवि दहिया ● फाइल फोटो, ट्विटर

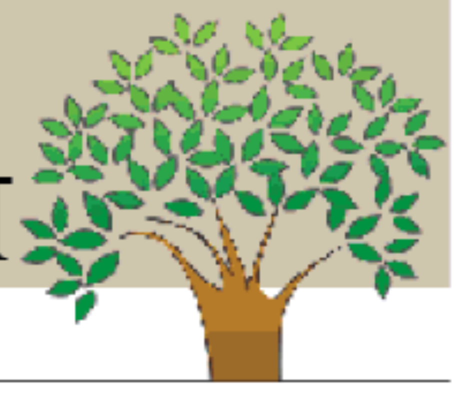
रवि की उपलब्धियां

साल	टूर्नामेंट	पदक
2013	सब जूनियर एशियन चैंपियनशिप	रजत पदक
2015	जूनियर एशियन चैंपियनशिप	स्वर्ण पदक
2015	जूनियर विश्व चैंपियनशिप	रजत पदक
2018	अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप	रजत पदक
2019	सीनियर विश्व चैंपियनशिप	कांस्य पदक
2020	एशियन चैंपियनशिप	स्वर्ण पदक
2021	एशियन चैंपियनशिप	स्वर्ण पदक

15 पहलवानों से मिलेगी कड़ी चुनौती

रवि ने कहा कि कि 15 पहलवान हैं और सभी से कड़ा मुकाबला होना है। रवि ने कहा कि कुछ पहलवान है जिनके साथ खास मुकाबला रहेगा। उसमें रूस के जावुर उगुएव, तुर्की के सुलेमान अतली, कजाखस्तान के नूरइस्लाम सनाएव, ईरान के रेजा अहमदअली, अमेरिका के थामस पैट्रिक गिलमैन, उज्बेकिस्तान के गुलोमजोन अब्दुल्लाऐव, जापान के यूकी ताखाशी, मंगोलिया के बेखबायर अर्डेनबैट के पहलवान शामिल है। 15 पहलवानों में छह पहलवान ऐसे हैं जिनको पहले हराया है लेकिन उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता।

दैनिक जागरण
सप्तरंग
संयम और संकल्प का
गुरुवार, 1 जुलाई, 2021



जीवन में उमंग का संचार करता है संगीत


फोटो : इमेजेज बाजार

सकारात्मकता की राह

याद करें उन दिनों को, जब कोरोना ने इटली में कोहराम मचा रखा था। तब वहां के निवासियों द्वारा अपने घर की बालकनी में संगीत सुनने, वाद्य यंत्र बजाने या गीत गुनगुनाने के दृश्य आम हो गए थे। धीरे-धीरे अन्य देशों के संगीतकारों ने भी अपने निवास स्थान से लाइव परफार्मेंस शुरू कर दी। प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल समय में एक-दूसरे से जुड़े रहने का प्रयास कर रहा था, जिसमें संगीत ने एक सेतु का कार्य किया। ग्लोबल काउंसिल आन ब्रेन हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार, संगीत में मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बढ़ाने की अद्भुत क्षमता है। न्यूरोलाजिस्ट्स से लेकर मनोचिकित्सक उन न्यूरल पाथवेज को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे पता लग सके कि आखिर बच्चों के विकास में संगीत किस प्रकार एक प्रभावशाली भूमिका अदा कर सकता है? कैसे वह आम जन की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति, यहां तक कि अल्जाइमर, सिजोफ्रेनिया, पर्किंसन जैसी बीमारियों में कारगर हो सकता है? अमेरिका के मिनेसोटा के रोचेस्टर स्थित मायो क्लीनिक में कार्यरत डा. एलविस फ्रैंकायस तो इस महामारी के दौरान अपने संगीत से कई कोविड पीड़ितों का मनोबल बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। जहां तक दवा की पहुंच नहीं, वहां संगीत अपना प्रभाव छोड़ जाता है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग में तैनात डा. प्रखर डागर को सभी प्यार से 'सिंगिंग डाक्टर' कहते हैं, क्योंकि वह मरीजों के इलाज में संगीत का बखूबी प्रयोग करते हैं। उनकी मानें, तो संगीत हर प्रकार की नकारात्मकता से लड़ने में मदद करता है। कोविड काल में ऐसे अनेक उदाहरण सामने आए, जब निराश रोगियों में भी जीने की अभिलाषा जागी और वे स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. आरती आनंद का कहना है, 'संगीत अवसाद से उबारने में जितना कारगर है, उतना ही प्रभावशाली तरीके से विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम बनाने में कारगर है।' कई न्यूरोलाजिकल रिसर्च में ऐसा दावा किया गया है कि संगीत सुनने से कार्टिजोल, सेरेटोनिन, आक्सीटोसिन, डोपामिन जैसे हारमोन निकलते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। यही कारण है कि इन दिनों तमाम लोग वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के तहत आने वाली म्यूजिक थेरेपी की मदद ले रहे हैं। अवसर खुशी का हो या गम का, संगीत का साथ नहीं छूटता।

अंशु सिंह

संगीत के फायदे

- याददाश्त शक्ति को बढ़ाता है।
- चीजों की बेहतर समझ पैदा होती है।
- मानसिक अवसाद, तनाव को दूर करने में कारगर है।
- मूड ठीक करने में है मददगार।
- म्यूजिक सुनने से कम होती है बेचैनी, घबराहट।

उजाले की ओर

प्रो. (डा.) युशी मोहनदास
माइंड कोच व मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट

आत्मशक्ति की खाद डालें और बढ़ा लें सकारात्मक सोच। आत्मसंयम का इत्र लगा खुशबू फैलाएं चारों ओर। विचारों में भी लाएं इम्युनिटी और मन के सुरक्षा कवच को करें मजबूत। गूगल से दोस्ती अच्छी नहीं, मन से मिलाएं मन। जान लें खुद को जानने का मंत्र...


फोटो : इमेजेज बाजार

मन को भी दें सुरक्षा कवच



अगर हम कई लोगों से खिचड़ी बनाने के लिए कहें तो सबकी बनाई खिचड़ी का स्वाद अलग होगा, क्योंकि हम शारीरिक रूप से बेशक एक जैसे हैं, लेकिन मानसिक रूप से अलग। खिचड़ी की सामग्री के इस्तेमाल के तरीके से ही खिचड़ी का स्वाद बदलेगा। लोगों को समझना चाहिए कि जितना आप बाहर की बातों पर फोकस करते हैं, उतना ही अपने भीतर भी फोकस करें। थोड़ी देर शांति से बैठें। अपने साथ संपर्क बढ़ाएं। सांसों पर ध्यान दें। आगे की न सोचें। ज्यादा सोचने से मतभेद बढ़ता है, नींद नहीं आती, संतोष नहीं मिलता। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि भीतर से प्राप्त खुशी और संतोष ही स्थायी है। इसे पाने के लिए अपने विचारों के साथ मूल्य जोड़ने होंगे।

आत्मशक्ति है खाद: मिट्टी में बीज के साथ खाद डालेंगे तो बीज भी उगेगा और खरपतवार भी। खाद तो नहीं जानती कि क्या अच्छा बढ़ रहा और क्या गलत। वह तो बस वृद्धि कर रही है। इसी तरह आपके भीतर की शक्ति को क्या पता कि आपमें अच्छा सोच पैदा हो रहा है या खराब। इसे तो आपको ही मैनेज करना होगा। हर आदमी के दिमाग में हर दिन हजारों विचार उपजते हैं। अगर आप अच्छे विचारों की खाद डालेंगे तो वे बढ़ेंगे और फालतू विचार आने बंद हो जाएंगे। आत्मशक्ति भी एक तरह की खाद है, जो आपको मजबूती देती है, लेकिन उसे दिशा तो आप ही देंगे न। जो व्यक्ति स्वयं अपना रास्ता चुनता है, वह मानसिक रूप से मजबूत होता है। हम सभी में यह शक्ति है, लेकिन मात्र दस प्रतिशत लोग ही ऐसा कर पाते हैं। बाकी पैसा कमाने और सामाजिक जीवन को चमकाने के लिए नौकरी करते हैं। अगर आपके पास दस बेडरूम का घर हो और आपको उसमें नींद न आए तो उसका क्या फायदा? और एक बेडरूम के घर में आप आठ घंटे की गाढ़ी नींद ले लेते हैं तो कौन-सा बेहतर हुआ?

आत्मसंयम से महकेंगे आप: जैसे इत्र की दुकान से निकलने पर आपसे भी खुशबू आएगी, वैसे ही आत्मसंयम भी आपको महका देगा। अगर आत्मसंयम है तो आप कोई नियम नहीं तोड़ेंगे। तीसरी लहर की आशंका है, लेकिन कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। जो जागरूक हैं, वे अनावश्यक बाहर नहीं निकलेंगे, कोविड प्रोटोकाल नहीं तोड़ेंगे। ध्यान करने वाले लोगों का आत्मसंयम बहुत होता है। जो आत्मसंयमित हैं, उन पर बाहरी स्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, वैसे ही ध्यान करें। आज हमें सिर्फ कोविड से बचने के लिए ही इम्युनिटी नहीं बढ़ानी है, बल्कि अपने विचारों में भी इम्युनिटी बढ़ानी है। शारीरिक बीमारी की जड़ मन में ही होती है। तनाव में रहेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे।

मन को साधना है जरूरी: दिल की बीमारी सब बताते हैं, लेकिन मन की नहीं। जब बच्चा थोड़े से लक्षण बताता है, चुप-चुप रहता है, लड़ाई करता है तो हम उसे मनोविज्ञानी या मनोचिकित्सक के पास न ले जाकर सोचते हैं कि उम्र के साथ सब ठीक हो जाएगा। हमें सजग रहकर अपने मन का ध्यान रखना होगा ताकि बीमारी वहीं खत्म हो जाए। मैं डाक्टर हूं लेकिन माइंड कोचिंग करती हूं। मेंटल हेल्थ और वेलनेस का काम कर रही हूं। मुझे भविष्य से फर्क नहीं पड़ता। मैं अतीत के बारे में भी नहीं सोचती। बस आज में रहती हूं। मन की बीमारियों से बचने के लिए वर्तमान में रहना जरूरी है।

यदि आपका कप खाली है तो आप किसी को क्या पिला सकते हैं? लोग पोषण का ध्यान रखते हैं, थोड़ी देर व्यायाम कर लेते हैं, लेकिन मन को नहीं साधते। मन को साधना ही जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग है। इस जमाने में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें दूसरों से प्यार की बात करने, किसी समस्या का समाधान ढूंढ़ने या खुशियों के छोटे-छोटे बहाने ढूंढ़ने की फुरसत ही नहीं है। सब शोकपूर्ण घटनाओं पर बहस कर रहे होते हैं। बरसात में भीगने से बचने के लिए हम छतरी लेते हैं या रेनकोट पहनते हैं। इसी तरह हमें अपने मन को भी सही रखने के लिए सुरक्षा कवच चाहिए। हम बातें सुनें, लेकिन उनका हमारे दिमाग पर असर न हो। अगर हम ध्यान लगाएंगे तो हमारा कवच मजबूत होगा।

गूगल है खतरनाक डाक्टर: आजकल डाक्टर से ज्यादा बीमार जानता है, क्योंकि वह गूगल करता है और गूगल का डाक्टर बहुत खतरनाक है। वह सबको बीमार बनाता है। अगर आप गूगल को अपने लक्षण बताएंगे तो वह आपको दस बीमारियां बताएगा। ऐसे में सावधानी की जरूरत है।

हो अच्छे विचारों का साथ: कुल मिलाकर, अच्छे विचारों के संपर्क में रहें, ताकि आप अपने अगले कदम को सुनिश्चित कर सकें। जिन्होंने बुरी सोच को बढ़ावा दिया, उन्हें अवसाद हुआ और जिन्होंने अच्छे सोच को पाला, वे खुश रहे। हमारे अंदर के रसायन खाने से नहीं बल्कि सोच-विचार से पैदा होते हैं। अच्छे सोच से हैप्पी रसायन बनते हैं। अगर मैं दस बार सोचूंगी कि कोविड से कितनी मौतें हुई हैं तो 'कार्टिजोल' पैदा होगा, जो मुझे बेचैन करेगा, जिससे अवसाद हो सकता है। मानसिक शोक गुस्से में बदल सकता है।

प्रस्तुति : यशा माथुर

भीतर की शक्ति से समाधान


डा. सारिका मेहता
मनोविज्ञानी, बाइकर

मैं बाइक से लंबी यात्रा पर होती हूं तो हर दिन 400-500 किमी. की यात्रा करती हूं। रास्ते में आई मुश्किलों को जीतती हूं। इसके लिए मानसिक मजबूती जरूरी है। हमें अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम पहाड़ों पर माइनस डिग्री में और रेगिस्तान में 48 डिग्री तापमान में भी राइड करते हैं। हर दिन मौसम बदलता है और हर दिन पानी बदलता है, लेकिन मैं ठीक रहती हूं। अध्यात्म में विश्वास रखती हूं। सुबह की प्रार्थना के बाद मानसिक संतुलन और शांति के लिए ध्यान करती हूं। ध्यान मन को हारने नहीं देता। जब कोई मुझसे पूछता है कि आप कैसे इतना सब कर लेती हैं तो मैं उनसे कहती हूं कि हमारे भीतर ही वह शक्ति है, जो समाधान देती है। मैं दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन अपने तरीके से समाज की भलाई के लिए काम तो कर ही सकती हूं। शिकायत करने से अच्छा है समाज के भले के लिए एक कदम उठाइए। मैंने यही किया है। मैं सूरत जैसे छोटे शहर में रहकर यह सब कर रही हूं तो मेरे दोनों बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं। वे कम उम्र में माउंटेनियर बन गए हैं। उनके लिए हीरो मैं ही हूं। यह मेरे लिए गर्व का विषय है। मेरे लिए चार बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली, खुद को समय देना। दूसरी, शिकायत नहीं करना। तीसरी, अपनी मदद खुद करना और चौथी, खुद अपना सम्मान हासिल करना।

विचारों का मैनेजमेंट



सच तो यह है कि मस्तिष्क के स्वास्थ्य का हमने कभी ध्यान नहीं रखा। अपने बच्चों को अंदरूनी खुशी के बारे में सिखाएं। संतुष्टि सिखाएं, नहीं तो वे भी आपकी तरह आगे पीछे की सोच-सोच कर परेशान रहेंगे। हमारा दिमाग कंप्यूटर है, जितना सोचेंगे, उतना ही वह भर जाएगा। दिमाग में हमें थोड़ी जगह खाली रखनी होगी, ताकि हम अपने विचारों को मैनेज कर सकें। जो विचार चाहिए उन्हें रखें और जो नहीं चाहिए उन्हें निकाल फेंकें। जैसा सोच रखेंगे वैसा ही व्यवहार में बाहर आएगा। कल की बात सोच कर आज खराब न करें। जब आपका मानसिक संतुलन बढ़ेगा तो गुस्सा कम हो जाएगा। सिर्फ तीस बार अपनी सांसें गिनकर ध्यान लगाएं। सांस, स्वयं और इंद्रियों के बारे में जागरूकता बढ़ाइए। अपने लिए पंद्रह मिनट रोज रखिए। अपने सोच से अपना परिचय करवाइए। ठहरें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें, प्रयास करें।

ध्यान है मस्तिष्क का व्यायाम

हम सब प्रेशर कुकर बन गए हैं, पर हमारे पास वह वाल्व नहीं है, जिससे दबाव बाहर निकल जाए। मैं लोगों को समझाती हूं कि सबके साथ दोस्ती बढ़ाएं। हमारे देश में लोग योग व ध्यान कम करते हैं, जबकि विदेशी हमसे सीखते हैं। ध्यान मस्तिष्क का व्यायाम है। ध्यान हर दिन करना चाहिए। एक दिन करने से नहीं होगा। अगर आप कोविड से उत्पन्न भ्रम की स्थिति से निकलना चाहते हैं तो आप अपनी मानसिक जागरूकता बढ़ाने के प्रयास करें। अपनी सांस को मैनेज करें। योग निद्रा, प्राणायाम करें। कुछ देर ध्यान लगाएं। आपको बहुत शांति मिलेगी। लोगों से दोस्ती बढ़ाएंगे तो एक-दूसरे से काफी कुछ सीख सकते हैं। अहम को दूर रखें। मैं जब रात में सोती हूं तो स्वयं को कृतज्ञ समझती हूं। जो दिन भर परेशान रहते हैं कि मनमाफिक जूता नहीं मिला, क्या उन्होंने कभी उस व्यक्ति को गौर से देखा है, जिसके पैर ही नहीं हैं। वे लोग यह बात नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने अभाव देखा नहीं। इस तरह के विचारों को बदलने और संतुष्ट रहने की जरूरत है।

खूबियों को देख कर मिलती है प्रेरणा

मदद की पहल

स्पर्श शाह
अंतरराष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर


फोटो : इमेजेज बाजार

हर इंसान में अपनी एक विशेषता होती है। कोई साहसिक होता है, कोई दयालु। किसी में धैर्य होता है, तो कोई दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जैसे हम सबने देखा कि कैसे डाक्टर, नर्स, मेडिकल सपोर्ट स्टाफ से लेकर केयरटेकर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, सबने अपना जीवन दांव पर लगाकर कोविड पीड़ितों की देखभाल की। इससे समाज में एक प्रेरक संदेश गया और हर ओर से मानवता का नया रंग देखने को मिलने लगा। छोटे बच्चों से लेकर सेवानिवृत्त बुजुर्ग तक मदद के लिए आगे आए। किसी ने भूखे को भोजन खिलाया, किसी ने इलाज कराया। वैश्विक महामारी ने ही यह एक बड़ा सबक दिया है कि विश्व में कोई भी सुरक्षित नहीं है, जब तक कि हर कोई सुरक्षित न हो। इसलिए दुनिया के तमाम देश एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। वक्त का तकाजा भी यही है कि राष्ट्र कोई भी हो, समुदाय कोई भी हो, मानवता की असल पहचान तभी है, जब हम बिना किसी भेदभाव के बुजुर्गों, बच्चों, पीड़ितों एवं जरूरतमंदों की सहायता करें।

अमेरिकी लेखक हैरोल्ड एस कुश्नर ने कहा है, लोगों की मदद करें, इसलिए नहीं कि वे कौन हैं, किस पद पर विराजमान हैं या बदले में आपको क्या दे सकते हैं, बल्कि उनकी मदद इसलिए करें, क्योंकि आपके अंदर सेवा करने की निःस्वार्थ इच्छा व भाव है। इस धरती पर रहते हुए हम एक अहम कार्य यह कर सकते हैं कि लोगों को बताएं कि वे अकेले नहीं हैं। आप उनके साथ हैं।

इन दिनों जब चारों तरफ एक अनिश्चितता का वातावरण, अशांति एवं नकारात्मकता व्याप्त है, ऐसे में हर दूसरे अथवा तीसरे व्यक्ति में कमी निकालना, उनकी कमजोरियों को देखना, उसका वर्णन करना लोगों के लिए आसान हो गया है। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जब हम दूसरों की कमियों को देखते हैं, तो खुद भी परेशान होते हैं और तनाव से घिर जाते हैं। वहीं, जब सामने वाले की खूबियों को देखना शुरू करते हैं, तो न सिर्फ खुद में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह महसूस करते हैं, बल्कि इससे वायुमंडल एवं अन्य व्यक्तियों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 11वीं के स्टूडेंट मोहित का अधिकांश समय मोबाइल फोन पर वीडियो गेम्स देखते हुए गुजरता था। पढ़ाई पर फोकस घट रहा था, तो पैरेंट्स से अक्सर कहासुनी हो जाती थी। एक दिन मां ने पूछा, 'इतना वीडियो गेम देखते हो, तो कुछ न कुछ सीखा भी होगा?' मोहित ने फौरन जवाब दिया, 'हां, अब तक चार एप बना चुका हूं। अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया है।' तब मां ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि यह तो सभी को पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या कौशल है? इस पर मोहित के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। कहने का आशय है कि जैसे ही मां ने बेटे की विशेषता देखी, न सिर्फ उनकी निराशा दूर हो गई, बल्कि मोहित को भी अपनी गलती का एहसास हो गया।

जीवन में उपयोगी है निर्भयता

जीने की राह


आचार्य विनोबा भावे



निर्भयता तीन प्रकार की होती है- विज्ञ निर्भयता, ईश्वरनिष्ठ निर्भयता और विवेकी निर्भयता। विज्ञ निर्भयता वह निर्भयता है, जो खतरों से परिचय प्राप्त करके उनका इलाज जान लेने से आती है। यह जितनी प्राप्त हो सकती हो, उतनी कर लेनी चाहिए। जिसकी सांपों से जान-पहचान हो गई, सांप पकड़ने की कला जिसे सिद्ध हो गई, सांप काटने पर किए जाने वाले इलाज मालूम हो गए, सांप से बचने की युक्ति जिसे विदित हो गई, वह सांपों की तरफ से निर्भय हो जाएगा। जिसे सांपों में रहना पड़ता है, उसके लिए यह निर्भयता व्यावहारिक उपयोग की चीज है, क्योंकि उसकी बदौलत जो हिम्मत आती है, वह मनुष्य को अस्वाभाविक आचरण से बचाती है। यह निर्भयता मर्यादित है। दूसरी यानी ईश्वरनिष्ठ निर्भयता मनुष्य को पूर्ण निर्भय बनाती है। परंतु दीर्घ प्रयत्न, पुरुषार्थ, भक्ति इत्यादि साधनों के सतत अनुष्ठान के बिना वह प्राप्त नहीं होती। तीसरी विवेकी निर्भयता है। यह अनावश्यक साहस नहीं करने देती, फिर भी यदि खतरे का सामना करना ही पड़े तो विवेक से बुद्धि शांत रखती है। विवेकी निर्भयता की आदत डालने का प्रयत्न करना चाहिए। मान लीजिए कि मेरा शेर से सामना हो गया और वह मुझ पर झपटना चाहता है। अगर मेरी मृत्यु बदी हो तो वह टल नहीं सकती, परंतु यदि मैं भयभीत न होकर अपनी बुद्धि शांत रखने का प्रयत्न करूं, तो बचने का कोई रास्ता सूझने की संभावना है।

(पुस्तक 'विनोबा के विचार' से साभार)

अपनी राय हमें जरूर बताएं :
feature@jagran.com

आज का भविष्यफल

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति: 1 जुलाई, 2021 गुरुवार आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष सप्तमी का राशिफल।
आज का राहुकाल: दोपहर 01:30 बजे 03:00 बजे तक।
आज का दिशाशूल: दक्षिण।
विशेष: पंचक।
पर्व एवं त्योहार: कालाष्टमी।

मेष: किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी।

वृष: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। आध्यात्मिक या भौतिक सुख की अनुभूति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी।

मिथुन: बहुप्रतिक्षित कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा।

कर्क: व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। भाग्यवश सुखद समाचार मिलेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा।

सिंह: उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। किसी कार्य के संपन्न होने में बाधा आएगी। बुद्धि कौशल से किए गए कार्य में सफलता मिल सकती है।

कन्या: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। पिता या संबंधित अधिकारी का भरपूर सहयोग मिलेगा।

तुला: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। बुद्धि कौशल से किए गए कार्य में सफलता मिलेगी।

वृश्चिक: शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

धनु: शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। सामाजिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। दांपत्य जीवन सुखमय होगा।

मकर: गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। दांपत्य जीवन सुखमय होगा। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। दायित्व की पूर्ति होगी।

कुंभ: पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। नए संबंध बनेंगे।

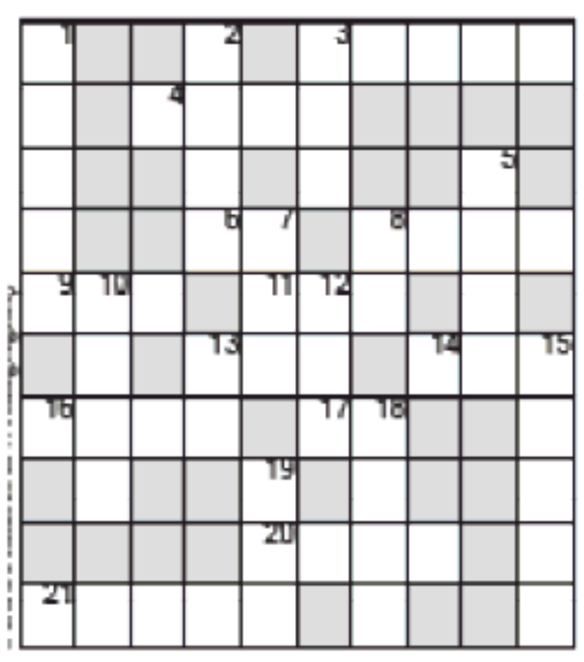
मीन: व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास की वृद्धि होगी।

कल 2 जुलाई का पंचांग



कल का दिशाशूल: पश्चिम।
विशेष: पंचक।
पर्व एवं त्योहार: शीतलाष्टमी।
विक्रम संवत 2078 शके 1943 उत्तरायन, उत्तरगोल, ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी 15 घंटे 29 मिनट तक, तत्पश्चात् नवमी रेवती नक्षत्र 29 घंटे 14 मिनट तक, शोभन योग तत्पश्चात् अतिगण्ड योग मीन में चंद्रमा।

वर्ग पहेली-1623



© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं
3 [illegible] [5]।
4 [illegible] [4]।
6 [illegible] [2]।
8 [illegible] [4]।
9 [illegible] [3]।
11 [illegible] [3]।
13 [illegible] [3]।
14 [illegible] [3]।
16 [illegible] [4]।
17 अधिपति, प्रभु, स्वामी [2]।
20 पानी में रहने वाला [4]।
21 जल और स्थल दोनों पर रहने वाला [5]।

ऊपर से नीचे
1 [illegible] [5]।
2 [illegible] [4]।
3 [illegible] [3]।
5 [illegible] [4]।
7 [illegible] [3]।
8 [illegible] [2]।
10 [illegible] [4]।
12 [illegible] [3]।
13 [illegible] [2]।
15 [illegible] [5]।
18 भूमि पर रहने वाला प्राणी कहलाता है [4]।
19 दृष्टि, निगाह [3]।

कल का हल

आ		तं	म	सं		अं	गो	च	र
प				मा		च			
बी		अ		चौ	र	पा	ई		को
ती	मा	र	दा	र		ग			त
		ह				लं	लीं	का	र
अ	म	र	तौ				स		
म			रा		अं	म	ल	ता	सं
न		कें	मं	द	ल		सा		नि
			ह		गा				क
कौं	ला	ह	ल		नी	नि	क		ट

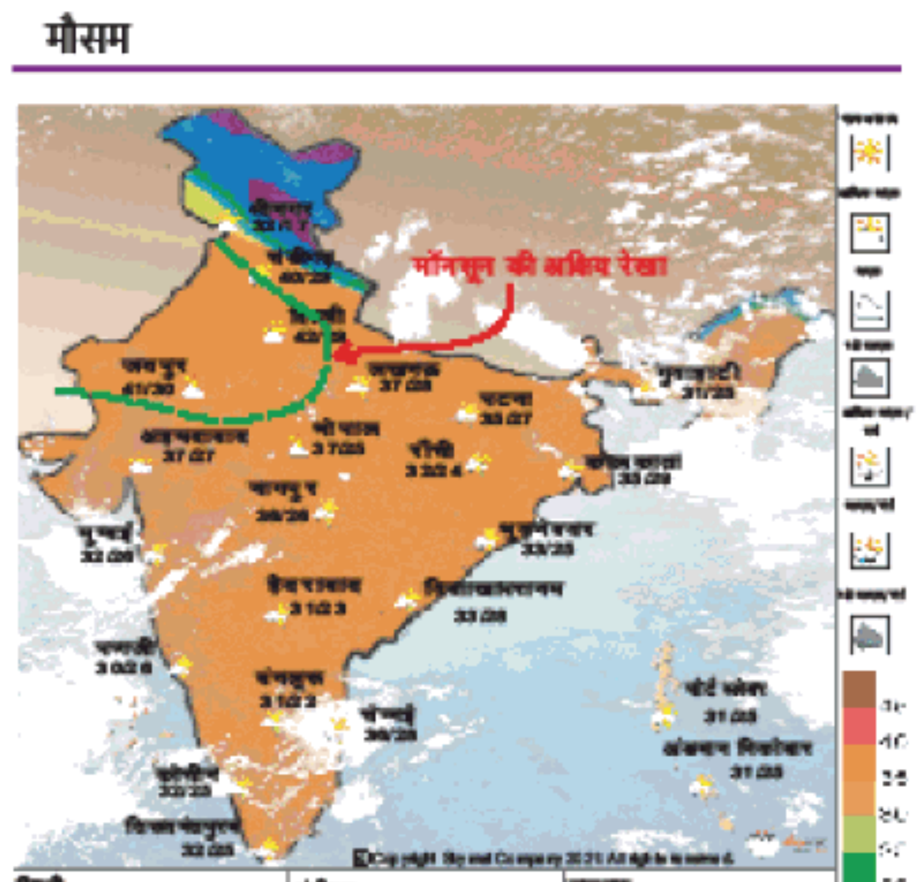
जागरण सुडोकू-1623

	5	1		8		3		9
2			6				1	
		3		5	1	6		4
	3		4			9		1
1		2	9	3	5		8	
4				6			3	
3			8			7		2
		4		1			9	
9			5		6	1		3

कल का हल

8	5	1	3	6	4	7	2	9
2	4	3	8	9	7	5	1	6
6	9	7	2	5	1	8	3	4
3	7	5	4	2	6	9	8	1
1	8	2	9	7	5	4	6	3
4	6	9	1	8	3	2	7	5
7	1	8	6	4	9	3	5	2
5	3	4	7	1	2	6	9	8
9	2	6	5	3	8	1	4	7

मौसम



हिमाचल प्रदेश, कश्मीर व लद्दाख के पहाड़ों में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश व जम्मू के मैदानी भागों में मौसम गर्म बना रहेगा। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा व उत्तरी राजस्थान में मौसम शुष्क व गर्म बना रहेगा। लू जैसी स्थिति बन सकती है।

कल पढ़ें



हसीन दिलरुबा तापसी

दो जुलाई को ओटीटी पर रिलीज हो रही फिल्म हसीन दिलरुबा में तापसी पन्नू नजर आएंगी। पिछले दिनों वह रूस से छुट्टियां मनाकर लौटी हैं। इस फिल्म, उनकी छुट्टियों और इंटरनेट मीडिया पर उनके बेबाक अंदाजों को लेकर उनसे बातचीत...

भारत में हुई पोस्टकार्ड की शुरुआत, तीन पैसे थी कीमत

वर्ष 1879 में आज ही के दिन भारत में पहला पोस्टकार्ड जारी किया गया था। हल्के भूरे रंग में छपे इस कार्ड की कीमत तीन पैसे थी। इस पर ईस्ट इंडिया पोस्टकार्ड छपा था। बीच में ग्रेट ब्रिटेन का राजचिह्न मुद्रित था। दाएं कोने में महारानी विक्टोरिया की मुखाकृति थी।





एक देश-एक कर प्रणाली के तौर पर जीएसटी अस्तित्व में आया

वर्ष 2017 में आज ही के दिन एक देश-एक कर प्रणाली के तहत पूरे देश में जीएसटी लागू किया गया था। भारतीय कर सुधार की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम था। देश में कर सुधार की शुरुआत राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुई थी।

वीर अब्दुल हमीद ने खोद दी थी दुश्मन के पैटन टैंकों की कब्र

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव में वर्ष 1933 में आज ही के दिन परमवीर चक्र से सम्मानित वीर अब्दुल हमीद का जन्म हुआ था। 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में वह पंजाब के तरनतारन जिले के खेमकरण सेक्टर में तैनात थे। दुश्मन ने पैटन टैंकों की मदद से हमला कर दिया। हवलदार हमीद के पास गन माउंटेड जीप थी, जिसकी मदद से उन्होंने दुश्मन के सात टैंक ध्वस्त कर दिए। जब वह आठवें टैंक को निशाना बना रहे थे तब एक गोला लगने से उनकी जीप के परखचे उड़ गए। गंभीर रूप से घायल हमीद 10 सितंबर को वीरगति को प्राप्त हो गए।



इधर-उधर की

घर में पड़ी थी करोड़ों की पेंटिंग, परिवार था अनजान

पेरिस, एजेंसी : कभी-कभी हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जिनकी कीमत को लेकर हम अनजान होते हैं। ऐसा ही कुछ फ्रांस के मार्ने शहर में रहने वाले एक परिवार के साथ हुआ। उसके पास फ्रांस के प्रसिद्ध चित्रकार ज्यां होनोर फ्रैगनार्ड की एक खोई हुई पेंटिंग थी, लेकिन उसे इसके बारे में पता नहीं था। इसका पता तब चला जब घर में मौजूद पुरानी चीजों की कीमतों का पता लगाने के लिए आक्शन हाउस से एक व्यक्ति को बुलाया गया। उसकी नजर जब दीवार पर टंगी पेंटिंग पर पड़ी तो उसने उसे नीचे उतारा। जब उसने पेंटिंग को पलटकर देखा तो काली स्याही से चित्रकार का नाम लिखा था। वैसे तो उसे पेंटिंग के बेशकीमती होने का पता चल गया था, लेकिन इसकी पुष्टि करने को उसने इसे पेरिस स्थित एक अन्य आक्शन हाउस भेजा। यह पेंटिंग 1768 से 1770 के बीच की है। आक्शन हाउस ने पेंटिंग को 9.1 मिलियन डालर (67 करोड़ रुपये से ज्यादा) में एक व्यक्ति को बेचा। खरीदने वाले के बारे में जानकारी नहीं दी गई है।


आक्शन हाउस ने पेंटिंग को 67 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत में बेचा। इंटरनेट मीडिया

इम्यून सेल की बढ़ाई जा सकेगी 'इम्यूनिटी'

कामयाबी ▸ विज्ञानियों ने तलाशा, कैसे किया जा सकता है प्रतिरक्षा कोशिकाओं को रीप्रोग्राम

भविष्य में इम्यून सिस्टम को मजबूत कर बीमारियों से लड़ने में मिलेगी मदद

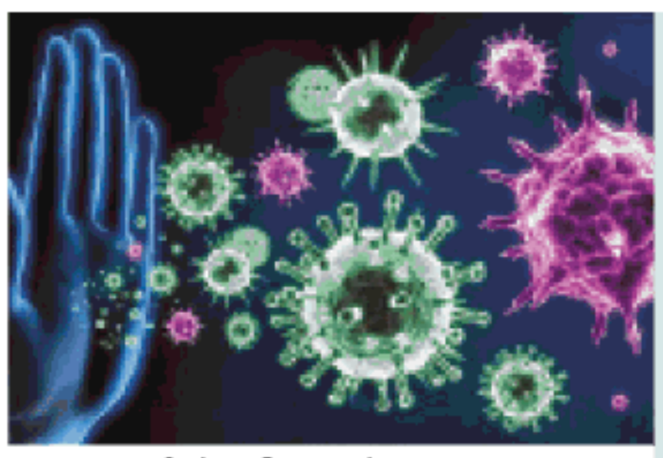
वाशिंगटन, एएनआइ : वायरस या बैक्टीरिया के संक्रमण से लड़ने के लिए शरीर के इम्यून सेल (प्रतिरक्षा कोशिकाओं) का मजबूत होना जरूरी है। अक्सर किसी के बीमार पड़ने पर उससे कहा जाता है कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, इसे मजबूत करें। अच्छा खान-पान और व्यायाम इसे मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन अब विज्ञानियों ने ऐसा रास्ता तलाश लिया है, जिससे इम्यून सेल को रीप्रोग्राम या ट्रेंड करके उन्हें और भी मजबूत किया जा सकेगा। इससे भविष्य में संक्रामक बीमारियों से लड़ने में मदद मिल सकेगी। यूनिवर्सिटी आफ कैलिफोर्निया- लास एंजिल्स (यूसीएलए) के विज्ञानियों ने एक खास किस्म के सेल को इस प्रक्रिया से गुजारने के लिए कुछ मौलिक नियमों की खोज की है।

साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित इस शोध के मुताबिक, शोधकर्ताओं ने संक्रमण के खिलाफ लड़ने वाले इम्यून सिस्टम के मैक्रोफैज के भीतर एक अहम मालिक्यूलर क्रिया विधि की खोज की है, जो यह तय कर सकता है कि सेल को क्या और कितने अच्छे तरीके से प्रशिक्षित किया जा सकता है। इस निष्कर्ष के आधार पर भविष्य में इम्यून सिस्टम के कामकाज को और ज्यादा लक्षित और सटीक बनाया जा सकता है।

यूसीएलए के डेविड गेफेन स्कूल आफ मेडिसिन में संक्रामक रोग विभाग के क्लिनिकल प्रोफेसर और इस शोध के मुख्य लेखक क्वेन चेंग के मुताबिक, जिस प्रकार से पूर्व अनुभवों के आधार पर एक सैनिक या एथलीट को प्रशिक्षण देकर उसके प्रदर्शन में सुधार लाया जा सकता है, उसी प्रकार से स्वाभाविक रूप से संक्रमण के खिलाफ लड़ने वाले इम्यून सेल को भी प्रशिक्षित कर उसे संक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए और मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि कुछ इम्यून सेल अन्य की तुलना में प्रशिक्षण के लिए बेहतर होते हैं। इसी दिलचस्प निष्कर्ष ने हमें यह समझने के लिए प्रेरित किया आखिर इसके पीछे क्या नियम और प्रक्रिया है।

यह पता लगाने का किया प्रयास : विज्ञानियों के मुताबिक, इस शोध में यह पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या इम्यून सेल की ट्रेनिंग इस बात पर निर्भर करती है कि सेल का डीएनए किस प्रकार से लपेटा या कसा हुआ है। इस मामले में यदि इंसान के सेल की बात करें तो छह फीट से ज्यादा लंबा डीएनए कोशिका के न्यूक्लियस (केंद्र) में फिट होता है और यह काफी सूक्ष्म होता है। इस स्थिति के लिए डीएनए क्रोमोजोम में कसकर लिपटा होता है।

इस तरह किया जा सकता है रीप्रोग्राम : एक अन्य शोधकर्ता और इस शोध के वरिष्ठ लेखक अलेक्जेंडर हाफमन ने बताया है कि ऐसे में डीएनए का चुनिंदा हिस्सा ही बाहर होता है और उस तक पहुंच होती है। इसी वजह से उन पहुंच वाले हिस्से में मौजूद जीन ही संक्रमण से लड़ने में सक्षम हो पाते हैं, लेकिन यदि मैक्रोफैज में माइक्रोब (सूक्ष्म जीवाणु) या पैथोजन (रोगाणु) से निकाले गए अंश को उद्दीपक (स्टिम्यलस) के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो पहले से कसा हुआ डीएनए खुल सकता है। इस प्रकार डीएनए के खुलने से नए जीन एक तरह से प्रशिक्षित होकर अधिक आक्रामकता के साथ संक्रमण के खिलाफ लड़ सकता है।


साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ शोध। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

शोध में विज्ञानियों ने यह भी लगाया पता

इस नए शोध से मैक्रोफैज में अहम इम्यून सिग्नल मालिक्यूल के डायनामिक्स (गतिकी) के बारे में भी पता चला है, जिसे एनएफबी कहा जाता है। इससे यह भी तय हो सकेगा कि जीन खुलेगा या नहीं। हालांकि, शोधकर्ताओं की रिपोर्ट कहती है कि एनएफबी की डायनामिक गतिविधि खास प्रकार के बाहरी उद्दीपक से तय होगी। चेंग के मुताबिक, हमारे अध्ययन में यह देखने में आया कि इम्यून सेल को कुछ खास उद्दीपकों (स्टिम्यलस) के जरिये ट्रेनिंग से ज्यादा आक्रामक बनाया जा सकता है। इस शोध से यह उम्मीद जगी है कि भविष्य में इम्यून सेल को और मजबूत किया जा सकेगा, जिससे संक्रामक रोगों से लड़ने में मदद मिल सकेगी।



धान उत्सव पर कीचड़ की होली...

नेपाल में राष्ट्रीय धान दिवस (नेशनल पैडी डे) धूमधाम के साथ पारंपरिक ढंग से मनाया गया। इस दौरान किसानों ने कीचड़ की 'होली' खेली। एक-दूसरे पर कीचड़ फेंका और लोकगीत गाकर खुशियां मनाई। इस वर्ष धान उत्पादन में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और समृद्धि के नारे के साथ उत्सव मनाया गया। इसके साथ ही यहां धान की रोपाई का काम शुरू हो जाएगा। एएफपी

बीमारियों से बचना है तो खूब करें व्यायाम, लें पर्याप्त नींद

अनुसंधान


ब्रिटिश जनरल में प्रकाशित हुआ अध्ययन। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जरूरी है कि दैनिक जीवन में खूब व्यायाम करें और पर्याप्त नींद भी लें। एक अनुसंधान में यह सामने आया है कि व्यायाम न करने और पूरी नींद न लेने वालों को हृदय रोग, पक्षाघात और कैंसर जैसी बीमारियों का ज्यादा खतरा रहता है।

अध्ययन के निष्कर्ष ब्रिटिश जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। अध्ययन में पाया गया है कि खराब नींद और शारीरिक निष्क्रियता दोनों का ही संबंध सीधे स्वास्थ्य से है। यह अध्ययन 38 लाख लोगों के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें 55 साल के औसत आयु वाले स्त्री-पुरुषों को शामिल किया गया। यूको बायोबैंक के इन आंकड़ों में ब्रिटेन से बाहर के भी लाखों लोग शामिल किए गए, जिनकी आयु 37 से 73 साल तक के बीच की थी। अध्ययन में शामिल लोगों से उनकी शारीरिक सक्रियता के स्तर की साप्ताहिक रिपोर्ट ली गई। इसको मेटाबोलिक इक्विवेलेंट आफ टास्क (एमइटी) मिनट में नापा गया। साथ ही उनकी नींद के बारे में भी जानकारी ली गई। नींद की पांच श्रेणी बनाकर आंकड़े एकत्रित किए गए। उनकी शारीरिक सक्रियता या निष्क्रियता पर अन्य जानकारी भी हासिल की गईं। अध्ययन 11 साल तक चला और मई 2020 में पूरा हुआ। इस अध्ययन के दौरान 15503 लोगों की मौत हुई। इनकी मौत के कारणों को भी अध्ययन में शामिल किया गया। जीवित लोगों से उनकी बीमारी की भी नियमित जानकारी ली गई। अध्ययन के निष्कर्ष में निकलकर आया कि शारीरिक रूप से सक्रिय और पूरी नींद लेने वाले लोग तमाम रोगों से बचे रहे। - एएनआइ

ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ रहा समुद्र का जल स्तर, मंडरा राह खतरा

▸ विज्ञानियों के नए अध्ययन में आए आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता
▸ लक्षद्वीप में समुद्र तल में सालाना 0.4 से लेकर 0.9 एमएम प्रति वर्ष की बढ़ोतरी की आशंका


ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। इंटरनेट मीडिया

नई दिल्ली, आइएसडब्ल्यू : ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों ने पूरी दुनिया के समक्ष किस्म-किस्म के जोखिम उत्पन्न कर दिए हैं। इनमें एक सबसे बड़ा खतरा समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी का है, जिससे सागर तट के किनारे बसे इलाकों पर अस्तित्व का संकट मंडराने लगा है। भारत के समुद्र तटीय इलाके और द्वीप समूह भी इस जोखिम से अछूते नहीं है। हाल में हुए एक अध्ययन में इस खतरे को बहुत करीब से महसूस भी किया गया है। विभिन्न हरित गैस परिदृश्यों के आधार पर हुए इस अध्ययन में कहा गया है कि देश की पश्चिमी तट रेखा के पास में स्थित लक्षद्वीप में समुद्र तल में सालाना 0.4 एमएम प्रति वर्ष से लेकर 0.9 एमएम प्रति वर्ष के दायरे में बढ़ोतरी हो सकती है।

इस अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि उत्सर्जन के विभिन्न परिदृश्यों के अनुसार समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी से यह पूरा द्वीप समूह संवेदनशील स्थिति में है। लक्षद्वीप को लेकर किया गया यह अपनी तरह का पहला अध्ययन है, जिसमें क्लाइमेट माडल अनुमान के आधार पर भविष्य की तस्वीर का खाका खींचने का प्रयास किया गया है। आइआइटी खड़गपुर के वास्तुशिल्प एवं क्षेत्रीय नियोजन और महासागर आभियांत्रिकी एवं नौवहन वास्तुशिल्प की संयुक्त टीम ने इस अध्ययन को मूर्त रूप दिया है। इस अध्ययन के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत संचालित जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम (सीसीपी) ने भी सहयोग किया है।

उल्लेखनीय है कि 36 द्वीपों का समूह लक्षद्वीप न केवल अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए, बल्कि सामुद्रिक जैव-विविधता के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन के अनुसार समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी से लक्षद्वीप के चेलट और अमिनी जैसे छोटे द्वीपों को बहुत नुकसान होगा। समुद्र का बढ़ता जल इन द्वीपों की जमीन के एक बड़े हिस्से को निगल सकता है। इन अनुमानों के आधार पर अमिनी में 60 से 70 प्रतिशत के बीच तट रेखा और चेलट में 70 से 80 प्रतिशत तट रेखा पर समुद्र का पानी हावी हो सकता है। इसमें यह भी बताया गया है कि मिनिकॉय जैसे बड़े द्वीप और राजधानी कावारत्ती भी बढ़ते पानी के कोप से प्रभावित हो सकते हैं। इस शोध-अध्ययन के निष्कर्ष 'रीजनल स्टडीज इन मैरिन साइंस' में प्रकाशित किए गए हैं।

स्क्रीन शॉट

'कुछ नया और अलग करने की चाहत से स्वीकार की लूप लपेटा'


लूप लपेटा में जूलिया का किरदार निभा रही हैं श्रेया।

अक्सर कलाकारों द्वारा किसी प्रोजेक्ट को स्वीकृति देने के कुछ खास कारण होते हैं। स्क्रिप्ट के चुनाव में उनकी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। वेब सीरीज द फैमिली मैन और स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी की अभिनेत्री श्रेया धनवंतरी की आगामी फिल्म लूप लपेटा चुनने के पीछे भी अपनी प्राथमिकताएं रहीं। तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन अभिनीत इस फिल्म में श्रेया जूलिया का महत्वपूर्ण किरदार निभा रही हैं। इस फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, निर्माता इस फिल्म के लिए लोकप्रिय और सशक्त अभिनेत्री की तलाश में थे, जो स्क्रीन पर तापसी और ताहिर का बराबरी से साथ दे पाए। श्रेया इससे पहले भी साल 2019 में इस फिल्म के निर्माता अतुल कासबेकर और तनुज गर्ग के साथ फिल्म व्हाइ चीट इंडिया में काम कर चुकी हैं। लिहाजा निर्माताओं को उनकी परफॉर्मेंस याद रही और लूप लपेटा में जूलिया के किरदार के लिए वह उपयुक्त अभिनेत्री लगीं। वहीं इस फिल्म को स्वीकृति देने पर दैनिक जागरण से बातचीत में श्रेया कहती हैं, 'मेरे लिए इस फिल्म को करने के कई कारण थे। मुझे जो किरदार ऑफर हुआ था वह इतना दिलचस्प था कि मैं इन्कार नहीं कर सकी। इस फिल्म का शीर्षक भी बहुत आकर्षक था। मुझे हमेशा कुछ नया और अलग करने की चाहत रहती है। इसी चाहत की वजह से मैंने लूप लपेटा को स्वीकार किया।' आकाश भाटिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म की शूटिंग तापसी पूरी कर चुकी हैं।

जब से कंगना का ट्विटर अकाउंट बंद हुआ है तब से दोनों के बीच बहसबाजी बंद थी। तापसी द्वारा क्वीन अभिनेत्री को अप्रासंगिक कहने पर वह एक बार फिर भड़क गई हैं

कंगना रनोट ने फिर कसा तापसी पर तंज

कंगना रनोट और तापसी पन्नू के बीच अक्सर छींटाकशी होती रहती है। कंगना की बहन रंगोली ने तो तापसी को कंगना की सस्ती कापी तक कह दिया था। जब से कंगना का ट्विटर अकाउंट बंद हुआ है, तब से दोनों के बीच बहसबाजी बंद थी। अब तापसी के कंगना को अप्रासंगिक कहने पर एक बार फिर क्वीन अभिनेत्री भड़क गई हैं। कंगना ने तापसी पर इंस्टाग्राम के जरिये वार किया है। दरअसल, पिछले दिनों जब तापसी से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था कि क्या कंगना का ट्विटर अकाउंट बंद होने से आप उनको मिस करती हैं। इस पर तापसी ने कहा था कि कंगना मेरे लिए अप्रासंगिक हैं। कंगना भी मेरी तरह एक एक्टर हैं और हम दोनों के बीच बस यही एक रिश्ता है। सहकर्मी के तौर पर मैं उनकी इज्जत करती हूं, इसके अलावा कंगना मेरे जीवन में कोई मायने नहीं रखती हैं। कंगना के लिए मेरे मन में अच्छी या बुरी कोई भावना नहीं है। इस बात से नाराज कंगना ने इंस्टाग्राम पर तापसी को टैग करते हुए लिखा कि वह (तापसी) निर्माताओं को फोन करके भीख मांगती थीं कि कंगना जी ने कुछ छोड़ा है तो मुझे दे दो प्लीज और आज इसकी (तापसी की) औकात देखो। जो कभी गरीब प्रोड्यूसर की कंगना कहलाने में गर्व महसूस करती थी, आज मुझे ही अप्रासंगिक कह रही है। खैर, तुम्हारी आने वाली फिल्मों के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। कोशिश करो मेरे नाम के बिना फिल्म को प्रमोट कर पाओ। तापसी की तरफ से फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि तापसी पहले ही दैनिक जागरण को दिए इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि वह अपनी बातों को एक मर्यादा के तहत कहना पसंद करती हैं।


इंस्टाग्राम के जरिये साधा निशाना ● जागरण आर्काइव »

'कास्टिंग मेरी नौकरी है और एक्टिंग जुनून'

हिंदी सिनेमा में कई कलाकार अभिनय के साथ-साथ अन्य पेशों से भी जुड़े रहते हैं। स्त्री और ड्रीम गर्ल फिल्मों तथा पाताललोक और मिर्जापुर वेब सीरीज के अभिनेता अभिषेक बनर्जी भी उन्हीं कलाकारों की सूची में शामिल हैं। अभिनेता के साथ-साथ अभिषेक इंडस्ट्री के जाने-माने कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं। दोनों में से किसी एक को प्राथमिकता देने के सवाल पर दैनिक जागरण से बातचीत में अभिषेक कहते हैं, 'मुझे मजा तो एक्टिंग करने में ही आता है। एक्टिंग मेरा जुनून है। कास्टिंग का काम मेरे लिए एक नौकरी की तरह है। वह मैं किसी और के लिए करता हूं तथा किसी और के लिए उत्तरदायी रहता हूं। लेकिन एक्टिंग करते वक्त मैं अपने प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र रहता हूं। उसमें मेरी अपनी सोच और कला होती है। उसमें अगर कोई गलती हुई तो मेरी हुई, अगर काम अच्छा हुआ तो भी मेरा। इसलिए एक्टिंग में मुझे ज्यादा मजा आता है। कास्टिंग की बात करें तो इससे भी मुझे एक फायदा होता है कि मेरे अंदर कभी आलस्य नहीं आता है, मेरे पास हमेशा कुछ न कुछ काम होता है। किसी प्रोजेक्ट की शूटिंग खत्म होने के बाद मैं छुट्टियां मनाने में समय व्यर्थ नहीं करता हूं। उसके बाद मैं अपने कास्टिंग के काम में जुट जाता हूं। अगर कभी मैं छुट्टियों पर भी जाता हूं, तब भी मेरा दिमाग किसी न किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोचता रहता है। मैं अपनी इस व्यस्तता का पूरा आनंद लेता हूं।' अभिषेक, वरुण धवन अभिनीत फिल्म भेड़िया में अभिनेता और कास्टिंग डायरेक्टर दोनों भूमिकाओं में काम कर रहे हैं।


आगामी दिनों में भेड़िया और आंख मिचौली फिल्मों में नजर आएंगे अभिषेक।

डिस्कवरी स्कूल सुपर लीग के चौथे सीजन की घोषणा की गई

अपने दर्शकों की दिलचस्पी के मुताबिक टेलीविजन चैनल भी अपने कार्यक्रमों के साथ लगातार प्रयोग करते रहते हैं। कुछ ऐसे ही प्रयोगात्मक कदम के तहत डिस्कवरी और डिस्कवरी किड्स चैनल ने पिछले साल छात्रों के लिए डिस्कवरी स्कूल सुपर लीग शो नामक क्विज शो की शुरुआत की थी। अब इस शो के चौथे सीजन का भी एलान हो गया है। बच्चों से सवाल-जवाब पूछे जाने वाले इस क्विज शो में देश के 30 हजार स्कूलों के कक्षा तीन से लेकर दस तक के करीब तीन लाख छात्र हिस्सा लेंगे। इस क्विज शो का हिस्सा छात्र अपने घर बैठे डिस्कवरी स्कूल सुपर लीग एप के माध्यम से बन सकते हैं। चौथे सीजन में छात्रों के साथ-साथ उनके माता-पिता, शिक्षक और प्रिंसिपल भी आपस में बात कर सकेंगे। शीर्ष पर रहने वाली प्रत्येक राज्य की एक टीम छह एपिसोड वाले टीवी क्विज शो के लिए क्वालीफाई करेगी, जिसका प्रसारण डिस्कवरी और डिस्कवरी चैनल पर किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में शीर्ष पर रहने वाले नौ छात्रों को उनके संबंधित शिक्षक या प्रिंसिपल के साथ अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) में एक दिन बिताने का मौका दिया जाएगा। इस शो के लेकर डिस्कवरी साउथ एशिया के हेड ऑफ एडवरटाइजिंग सेल्स शॉन नानजप्पा ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा, 'यह शो छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर चमकने के लिए बड़ा मंच प्रदान करता है। महामारी के कारण स्कूल बंद होने से छात्रों में क्विज में भाग लेने की उत्सुकता बढ़ गई है। हमारा मानना है कि नए और आकर्षक प्रारूपों के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बनाया जा सकता है।' शो के प्रसारण के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

तूफान के लिए आठ महीने ट्रेनिंग ली : फरहान



फिल्म में बाक्सर के किरदार में होंगे फरहान ● इंस्टाग्राम

डिजिटल पर रिलीज होने वाली फिल्मों में फरहान अख्तर और मृणाल ठाकुर अभिनीत फिल्म तूफान भी शामिल है। बुधवार को फिल्म का ट्रेलर वर्चुअली लांच किया गया। इस मौके पर फरहान, मृणाल के साथ फिल्म के निर्देशक राकेश ओमप्रकाश मेहरा और फिल्म के निर्माता रितेश सिधवानी मौजूद रहे। परेश रावल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये लांच से जुड़े थे। भाग मिल्खा भाग फिल्म के बाद राकेश ने इस फिल्म में फरहान को दोबारा निर्देशित किया है। इस बार वह स्पोर्ट्स बायोपिक की जगह खेल आधारित फिक्शन कहानी लेकर आ रहे हैं। इस बाबत उन्होंने कहा कि फिक्शन कहानी एक कैनवास की तरह होती है, जिसमें आप अपने रंग भर सकते हैं। हालांकि रंग दे बसंती और भाग मिल्खा भाग इन दोनों फिल्मों को बनाने में जितनी मेहनत लगी है, उतनी मिलाकर अकेले तूफान को बनाने में लगी है। फरहान ने बताया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने सात-आठ महीने बाक्सिंग की ट्रेनिंग ली थी। परेश फिल्म में बाक्सिंग कोच की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सेट से जब मैं घर जाता था, तो अपने बच्चों से यही कहता था कि काश मैंने 25 साल पहले बाक्सिंग सीखी होती। इससे पूरे शरीर का वर्कआउट होता है। तूफान 16 जुलाई को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी।

प्यार परवान पर चढ़ने की कहानी है क्वारंटाइन क्रश

अभिनेता आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप इन दिनों लेखन के साथ-साथ निर्देशन में भी हाथ आजमा रही हैं। उनके निर्देशन में बनी दूसरी वेब सीरीज फील्स लाइक इश्क 23 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। बुधवार को इस शो का ट्रेलर जारी किया गया। प्यार और जुनून की छह अलग-अलग कहानियों को मिलाकर बनी इस एंथोलाजी वेब सीरीज में ताहिरा ने क्वारंटाइन क्रश नामक कहानी का निर्देशन किया है। बाकी पांच कहानियों सेव द डेट, स्टार होस्ट, शी लव्स मी शी लव्स मी नाट, द इंटरव्यू और इश्क मस्ताना को क्रमशः रुचिर अरुण, आनंद तिवारी, दानिश असलम, सचिन कुंडालकर और जयदीप सरकार ने निर्देशित किया है। शो की अलग-अलग कहानियों में राधिका मदान, अमोल पराशर, काजोल चुघ, मिहिर आहूजा, सिमरन सोनी, रोहित सराफ, नीरज माधव और तान्या मनिकलता जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। छह एपिसोड की इस वेब सीरीज में हर एपिसोड की शुरुआत एक नई कहानी से होगी। अपनी कहानी क्वारंटाइन क्रश के बारे में दैनिक जागरण से बातचीत में ताहिरा ने बताया, क्वारंटाइन क्रश एक संवेदनशील प्रेम कहानी है, जिसमें प्यार तब परवान चढ़ता है जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही होती है।


निर्देशन में सक्रिय हैं आयुष्मान की पत्नी ताहिरा ● इंस्टाग्राम

23 जुलाई को रिलीज होगी हंगामा 2

फिल्मकार प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म हंगामा 2 को डिजिटल प्लेटफार्म पर रिलीज किए जाने की खबरें पहले ही आ चुकी हैं। बुधवार को इस फिल्म की रिलीज को लेकर आधिकारिक एलान किया गया। साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म हंगामा की सीक्वल फिल्म हंगामा 2 डिजिटल प्लेटफार्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 23 जुलाई को रिलीज होगी। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने फिल्म के पोस्टर के साथ रिलीज डेट इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए लिखा, शांत नहीं रह सकती, क्योंकि अब होगा हंगामा। हंगामा 2 का ट्रेलर एक जुलाई को रिलीज होगा। आप इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अपने के करीब 14 वर्ष बाद बतौर अभिनेत्री शिल्पा की यह पहली फिल्म रिलीज होगी। इस फिल्म में उनके साथ मीजान जाफरी, परेश रावल, प्रनिता सुभाष और राजपाल यादव अहम भूमिकाओं में हैं। वहीं मंगलवार को फिल्मकार अनुभव सिन्हा ने अपनी अनाम एक्शन थ्रिलर फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म को अनुभव निर्माता भूषण कुमार के साथ मिलकर बना रहे हैं, जबकि निर्देशन की बागडोर छलांग और अलीगढ़ जैसी फिल्मों के निर्देशक हंसल मेहता के हाथों में हैं। इस फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, यह फिल्म एक सच्ची अंतरराष्ट्रीय घटना पर आधारित है।


साल 2003 में बनी फिल्म हंगामा की सीक्वल फिल्म है हंगामा 2 ● इंस्टाग्राम

मुझमें सहने की क्षमता बहुत है : सूरज पंचोली

फिल्म इंडस्ट्री में महज तीन फिल्म पुराने अभिनेता सूरज पंचोली अब डिजिटल प्लेटफार्म पर अपने लिए रास्ते तलाश रहे हैं। हीरो, सेटेलाइट शंकर और टाइम टू डांस जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके सूरज ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि मैंने बतौर अभिनेता साल 2015 में करियर की शुरुआत की थी, लेकिन अब तक तीन फिल्में ही की हैं। दरअसल, मुझे ऊपर वाले ने बहुत धैर्य दिया है। मुझमें सहने की क्षमता बहुत है। कोशिश कर रहा हूं कि अपने लिए और अच्छे काम तलाश करूं। डिजिटल प्लेटफार्म पर निगेटिव किरदार निभाना चाहता हूं। हर एक जॉनर को एक्सप्लोर करने की इच्छा है। माता-पिता जरीना वहाब और आदित्य पंचोली के बारे में बात करते हुए सूरज ने कहा कि मेरे माता-पिता हमेशा मुझे यही कहते हैं कि जो फिल्म या प्रोजेक्ट्स करने हैं करो, हमारी पसंद से काम मत करो। यही वजह है कि माता-पिता से घर पर मेरी फिल्मों को लेकर कोई बात नहीं होती है। हम तीनों के ही काम करने के तरीका अलग है। मेरा जीवन में फिलहाल यही उद्देश्य है कि मुझे खुद को काम से साबित करना है। मैं दर्शकों के लिए काम करता हूं। फिलहाल लक्ष्य बहुत दूर है।

सभी फोटो इंस्टाग्राम


निगेटिव किरदार करना चाहते हैं सूरज।